आर्थिक दृष्टिकोण, संभावनाएं और नीतिगत चुनौतियां

01

अध्याय

1.1 प्रस्तावना

सुधार और अनुकूल वैदेशिक माहौल के लिए राजनीतिक जनादेश ने अवसर का एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण सृजित किया है जो भारत को द्विअंकीय विकास की राह पर ले जाएगा केंद्र द्वारा नियंत्रित नीतियों में निर्णायक परिवर्तनों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में सतत्, व्यापक और सृजनात्मक विकास से युगांतरकारी सुधारों की शुरूआत हो सकती है।

अब जब नई सरकार अपना पहला पूर्ण वर्षीय बजट पेश कर रही है, एक असाधारण अवसर हमारे सामने खड़ा है। भारत एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा है जहां से यह द्विअंकीय मध्यावधिक विकास पथ पर अग्रसर हो सकता है। कई राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। इसी विकास पथ के चलते आज भी गरीब और कमजोर वर्ग के ''हर आंख से आंसू पोंछने'' के बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ अधिकाधिक युवा, मध्यवर्गीय और महत्वाकांक्षी भारत के लिए अवसर पैदा होंगे जिससे वे अपनी असीमित क्षमता को साकार कर सकें।

यह रास्ता इसीलिए खुला है क्योंकि तथ्य और भाग्य भारत के पक्ष में है। वृहद् अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर हो गई है, सुधारों की शुरूआत हो गई है, विकास में गिरावट खत्म हो गई है और अर्थव्यवस्था अब पुनरुद्धार के पथ पर है, वैदेशिक माहौल अनुकूल है और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने खड़ी चुनौतियों ने भारत को उत्सुक निवेशकों की आंख का तारा बना दिया है। भारी चुनौतियां अभी भी बरकरार है, जिन्हें इस सर्वेक्षण में नज़रअंदाज नहीं किया गया है, लेकिन आर्थिक परिवर्तन के लिए मिले भारी जनादेश के कारण आशा जागी है कि इन चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। संक्षेप में, भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण को प्राथमिकताएं तय करने, समान रूप से समावेशी होने और विवादित रूप में चयनात्मक होने के दोषों से बचने की समस्या से जूझना पड़ता है। तद्नुसार इस सर्वेक्षण में दो प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया गया है-अवसरों का सृजन और असुरक्षा को कम करना-क्योंकि ये दो मुद्दे आज में बहुत महत्व रखते हैं और इनके संबंध में ही कई प्रमुख नीतिगत चुनौतियां हैं जिनका समाधान नई सरकार को करना है।

आर्थिक सर्वेक्षण के इस खंड की रूपरेखा इस प्रकार है। एक संक्षिप्त वृहद् आर्थिक समीक्षा और दृष्टिकोण अगले व्यापक विषयों और नीतिगत चर्चाओं के लिए संदर्भ का कार्य करेगी। कहना न होगा कि आय और संपदा के वितरण में सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों के उत्थान के लिए और उस वितरण में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर मुहैया कराने के लिए आर्थिक विकास का बहुत महत्व है।[1] तीव्र, सतत् और व्यापक विकास के लिए मजबूत बृहद आर्थिक बुनियाद जरूरी है, जिसका आधार राजकोषीय अनुशासन और विश्वसनीय मध्यावधिक राजकोषीय संरचना है। इन पूर्वापेक्षाओं को भाग 1.2 और 1.6 में वर्णित किया गया है।

लेकिन ''हर आंख से आंसू पोंछने'' के लिए सुचारू रूप से कार्य करने वाले, सुलक्षित, लीकेज प्रूफ ऐसे सुरक्षा जाल के रूप में सरकार से सकारात्मक सहायता की जरूरत होती है जो न्यूनतम आय मुहैया कराये और प्रतिकूल झटकों से संरक्षण दे। यह बात ग्रामीण भारत के बारे में भी सच है जहां किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थितियां खराब हैं। नीतिगत मुद्दा अब ''क्या'' नहीं है बल्कि यह है कि कैसे बेहतरीन ''प्रावधान और संरक्षण'' किया जाए और इस संबध में प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे (भाग 1.7 में वर्णित)।

[1] Bhagwati, J. and Arvind Panagariya, "*Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries*", 2013, A Council on Foreign Relations Book, Public Affairs Books.

पसीना और प्रेरणा, निवेश और कार्यदक्षता, दीर्घावधिक विकास को निर्धारित करते हैं। लेकिन भारत में निजी क्षेत्र के निवेश के माहौल पर पिछले दशक के अनुभव के बादल मंडरा रहे हैं। अनेक कारक–त्रुटिपूर्ण कारपोरेट तुलनपत्र, कमजोर बैंकिंग व्यवस्था, अर्थतंत्र से निकलने में कठिनाई और अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के दोष–निजी क्षेत्र के निवेश को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। निजी निवेश दीर्घावधिक विकास का मुख्य प्रेरक होना चाहिए। लेकिन अल्प से मध्यावधिक संदर्भ में जैसे–जैसे लगभग प्रचण्ड समस्याओं का समाधान होगा, सरकारी निवेश विशेषकर रेलवे द्वारा किए गए निवेश को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। ये मुद्दे और बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार एक सहायक भूमिका निभाए, भाग 1.8 और 1.9 में चर्चा का केंद्र है।[2]

अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में, विशेषकर एशिया में युद्धोत्तर काल में विनिर्माण और व्यापार विकास के प्रेरक रहे हैं। भारत के संदर्भ में उस अनुभव की मान्यता भाग 1.10 का केंद्र है जो मेक इन इंडिया के संदर्भ में महत्व प्राप्त कर चुका है। इसलिए अगले भाग में व्यापार से संबंधित चुनौतियों की बात की गई है।

भाग 1.12 तथा 1.13 जो जलवायु परिवर्तन और लिंग समानता के बारे में हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये मुद्दे विकास और अवसरों की समानता से जुड़ी चुनौतियों का केंद्र बिंदु हैं। कमजोर वर्गों के संरक्षण के उद्देश्य में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां भारत अधिकाधिक युवा, मध्यवर्गीय और महत्वाकांक्षी है, वहीं ये अभी भी हठधर्मी पुरूष हैं।

ये सभी नीतिगत मुद्दे और चुनौतियां इस खंड के अध्याय 2–10 में वर्णित हैं। अंतिम खंड केंद्र–राज्यकोषीय संबंधों को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने के संबंध में है। इसमें चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की जटिलताओं के प्रारंभिक विश्लेषण की व्यवस्था की गई।

आगामी बजट को लेकर बड़ी–बड़ी उम्मीदों के चलते, एक सवाल का सीधा–सीधा जवाब दिये जाने की जरूरत है: क्या भारत को भारी भरकम सुधारों की जरूरत है? युद्धोत्तर काल के वर्षों के संबंध में विभिन्न देशों के प्रमाण यह बताते हैं कि भारी भरकम सुधार किसी भी बड़े संकट के दौरान अथवा उसके बाद हुए। इसके अलावा, मजबूत लोकतंत्र में जहां कुछ करने, किये हुए को खत्म करने और काम को रोकने वाली संस्थाएं अनेकानेक भागीदार हों, वहां भारी भरकम सुधार केवल अपवादस्वरूप ही होते हैं, नियमानुसार नहीं। आज का भारत संकटग्रस्त नहीं है और निर्णय लेने वाली सत्ता अत्यधिक से और निराशाजनक रूप से बिखरी हुई है।

शक्ति के अनेक संचालक न सिर्फ ऊर्ध्व रूप से बिखरे हुए हैं जो राज्यों की शक्ति में प्रतिबिम्बित होता है बल्कि नीति बनाने का कार्य भी अनुप्रस्थ रूप से बिखरा हुआ है। उच्चतम न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने नीतिगत कार्रवाई करने और कार्रवाई न करने के बारे में निर्णायक प्रभाव छोड़ा है।

इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सुधार जैसे कि कर प्रशासन में सुधार अथवा कारोबार करने में आसानी संबंधी सुधार धीमे और कठिन हैं जिनके लिए उनके कार्यान्वयन में दृढ़ता और सहनशक्ति की जरूरत होती है। ये बात मैक्स वैबर के मशहूर कथन ''सख्य सतह में धीरे–धीरे छिद्रण'' की याद दिलाती है।

इसलिए भारी भरकम सुधार, जैसा भी परंपरागत तौर पर इन्हें समझा जाता है, सरकार की सुधारात्मक कार्रवाइयों का मूल्यांकन करने के लिए अनुचित और अव्यवहार्य मानक हैं।

इतना ही जरूरी यह भी है कि सरकार द्वारा प्राप्त जनादेश राजनीतिक अवसर के लिए एक विशेष रास्ता बना दे जिसे त्यागा न जाए। भारत को ''दृढ़, व्यापक और सृजनात्मक विकास'' के रास्ते पर चलना होगा लेकिन कुछ क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे जो निर्णायक तौर पर विगत से भिन्न होने का संकेत दें और जिनका उद्देश्य मुख्य समस्याओं का समाधान करना जैसे कि निवेश जुटाना, प्रतिस्पर्धी, निश्चित और स्वच्छ कर नीति माहौल तैयार करना, सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना और विनिवेश में तेजी लाना।

इस प्रकार वैबर का ज्ञान कार्रवाई न करने या कार्रवाई को टालते रहने का लाइसेंस नहीं हो सकता। ऐसे क्षेत्रों में निर्भीक उपाय करना जहां केंद्र द्वारा नीतिगत रस्सी आसानी से खींची जा सकती है, उसके साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में विकास करने से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जो समय बीतने पर भारी भरकम सुधारों की ओर ले जाएगी। यही एक उपयुक्त मानक है जिसके संदर्भ में भावी सुधारों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

[2] वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर पिछले वर्ष की समीक्षा में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी।

1.2 वृहत् आर्थिक समीक्षा और संभावनाएं

वृहत् आर्थिक मूलभत सिद्धांतों में नाटकीय सुधार हुआ है जो ज़मीनी आधार पर और विभिन्न देशों की तुलना में दिखाई देता है।

हम बदलती वृहत् आर्थिक परिस्थितियों से शुरूआत करते हैं। भारत का बदलता परिस्थितियां नाटकीय रूप से सकारात्मक है (चित्र 1.1)। वर्ष 2013 के उत्तराद्धं से मुद्रास्फीति में 6 प्रतिशतांक से अधिक की गिरावट हुई है और चालू लेखा घाटा 2012-13 की तीसरी तिमाही के स.घ.उ. के 6.7 प्रतिशत की चरम सीमा से घटकर आगामी वित्त वर्ष में अनुमानित 1.0 प्रतिशत पर आ गया है। विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाहों (अप्रैल 2014 से 38.4 बिलियन अमरीकी डॉलर) ने रुपए को स्थिर किया है, दीर्घावधिक ब्याज दरों पर अधोगामी दबाव बना रखा है जो 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय में भी दिखाई दिया है और इसने इक्विटी मूल्यों में उछाल को बढ़ावा दिया है (रुपए मूल्य में अप्रैल से 31 प्रतिशत और अमरीकी डॉलर मूल्य में और भी अधिक उछाल जिसकी वजह से यह उभरते बाजारों में शीर्षतम स्तर पर पहुंच गया है। लगभग 12 तिमाहियों के गिरावट के दौर में आर्थिक विकास दर औसतन 6.7 प्रतिशत रही लेकिन 2013-14 से यह औसतन 7.2 प्रतिशत पर बढ़ रही है और यह विकास के नए अनुमानों पर आधारित है (इनकी व्याख्या कैसे करें इसके लिए बॉक्स 1.1 देखें)।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप भारत की वृहत आर्थिक स्थिति अब अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। चित्र 1.2 में समग्र वृहद साधनहीनता सूचकांक (एमवीआई) दिखाया गया है जिसमें देश का राजकोषीय घाटा, चालू लेखा घाटा और मुद्रास्फीति का संयुक्त रूप है। इस तरह यह सूचकांक विभिन्न देशों और विभिन्न समयावधियों में तुलना दिखाता है। वर्ष 2012 में भारत 22.4 के सूचकांक मूल्य द्वारा यथामापित सबसे कमजोर देश था, जिसकी मुद्रास्फीति दर 10.2 प्रतिशत, बजट घाटा 7.5 प्रतिशत और चालू लेखा घाटा स.घ.उ. का 4.7 प्रतिशत था जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत अधिक था। वर्ष 2014 में तुर्की ने उच्च चालू लेखा घाटे (लगभग 8 प्रतिशत) के चलते भारत को पछाड़ दिया। आज भारत की स्थिति में बहुत सुधार हो गया है और भारत ने एमवीआई में काफी सुधार दिखाया है जबकि कई अन्य देश यथास्थिति बनाए हुए हैं अथवा कई की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है या बहुत गिरावट हो गई है (रूस)। भारत अभी भी निवेशक रेटिंग श्रेणी (बीबीबी) के संदर्भ में देशों की औसत से बदतर स्थिति में है लेकिन अभी भी बहुत से उभरते बड़े बाजारों वाले देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

यदि किसी देश की स्थिति/क्षमता का मूल्यांकन करने में वृहद् आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है, वहीं इसका वास्तविक और भावी विकास दूसरा कारक है। इसलिए सापेक्ष आर्थिक स्थिति की तुलना करने का एक आसान तरीका है कि वृहद् आर्थिक साधनहीनता सूचकांक के साथ ''रैशनल इनवेस्टर रेटिंग्स इंडेक्स (आरआईआरआई)'' को भी इस्तेमाल किया जाए।[3] प्रतिस्पर्धी गंतव्यों से जुड़े जोखिमों और लाभ का मूल्यांकन करते समय, सुविज्ञ निवेशक न सिर्फ वृहद् आर्थिक स्थिरता (जो जोखिमों के बराबर ही है) पर, बल्कि विकास पर भी ध्यान देता है जो निश्चित रूप से प्रतिलाभ और प्रतिफल को निर्धारित करते हैं।

ऊपर चित्र 1.3 में यह सूंचकंक भारत और विकास सहित अनेक अतुलनीय देशों जिसमें बीआरआईसीएस, अन्य उभरते प्रमुख बाजारों (तुर्की) तथा भारत की निवेशक रेटिंग (बीबीबी) और श्रेणी (ए) में शामिल देशों के बारे में है। भले ही भारत का विकास पुरानी विधि से मापा जाए या नई विधि से मापा जाए (देखें बोक्स 1.1), भारत इस सूचकांक में भारी सुधार दर्शाता है।

भारत अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक आकर्षक अन्य देशो में से एक है। भारत अपनी निवेश ग्रेड श्रेणी के लिए भी औसत से ऊपर दर्जे पर है, और साथ ही, इसके ऊपर की निवेश श्रेणी के औसत से भी ऊपर हैं (नए विकास अनुमानों के आधार पर) बीआरआईसीएस में केवल चीन ही भारत से ऊपर है।

बृहत आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ उच्च बढ़ते विकास की संभावना और सच्चाई भारत को आगे ले जाने का आश्वासन है।

---

[3]आरआईआरआई का आकलन देश के स.घ.उ. की वृद्धि दर और इसके वृहद् आर्थिक संकेतकों का औसत निकाल कर किया जाता है; उत्तरोक्त के राजकोषीय घाटे, चालू लेखा घाटे और मुद्रास्फीति (सभी नकारात्मक संकेतों सहित) की औसत के रूप में मापा जाता है। इस तरह विकास और वृहद् आर्थिक स्थिरता को समान भारांश दिया जाता है। यह आंकड़ा जितना अधिक होगा, निवेशक रेटिंग उतनी ही बेहतर होगी। चूंकि डब्ल्यूईओ के अद्यतन अनुमान सभी देशों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, यह आंकड़े सिटी ग्रुप से प्राप्त किये गये हैं और 2015 के संबंध में 58-60 अमरीकी डालर प्रति बैरल तेल की कीमत का अनुमान लगाते हुए जनवरी में अद्यतन किए गए हैं। अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़े आरआईआरआई के लिए ऐसे ही अनुमान देते हैं।

चित्र 1.1क: डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई मुद्रास्फीति, अप्रैल 2013 से जनवरी 2015 (प्रतिशत)

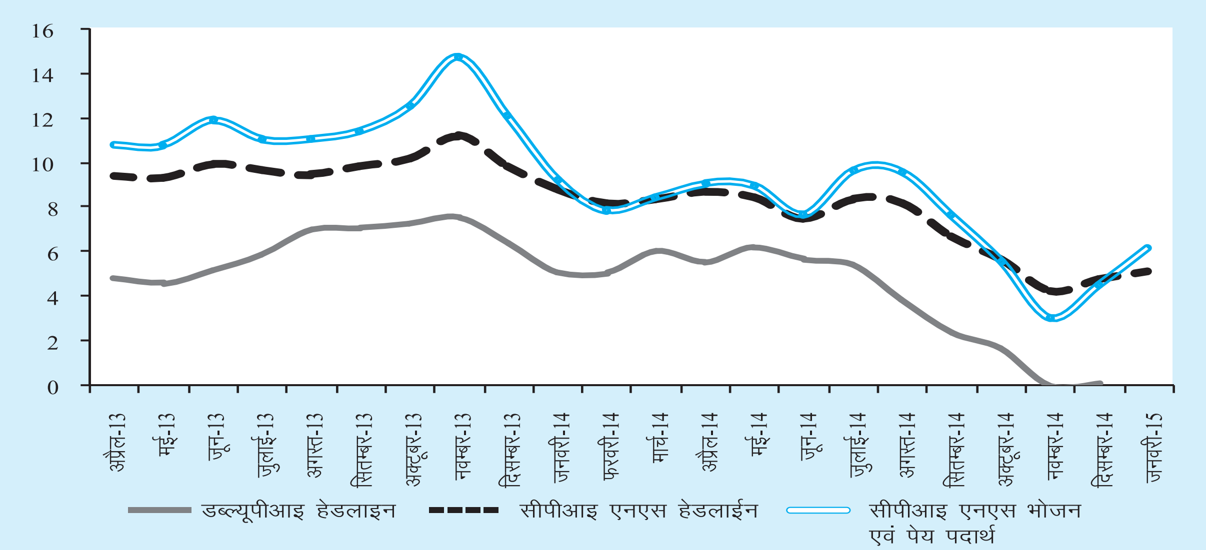

चित्र 1.1ख: चालू खाता शेष तथा निवल विदेशी निवेश, 2004-05 पहली तिमाही से 2014-15 दूसरी तिमाही (स.घ.उ. का प्रतिशत)

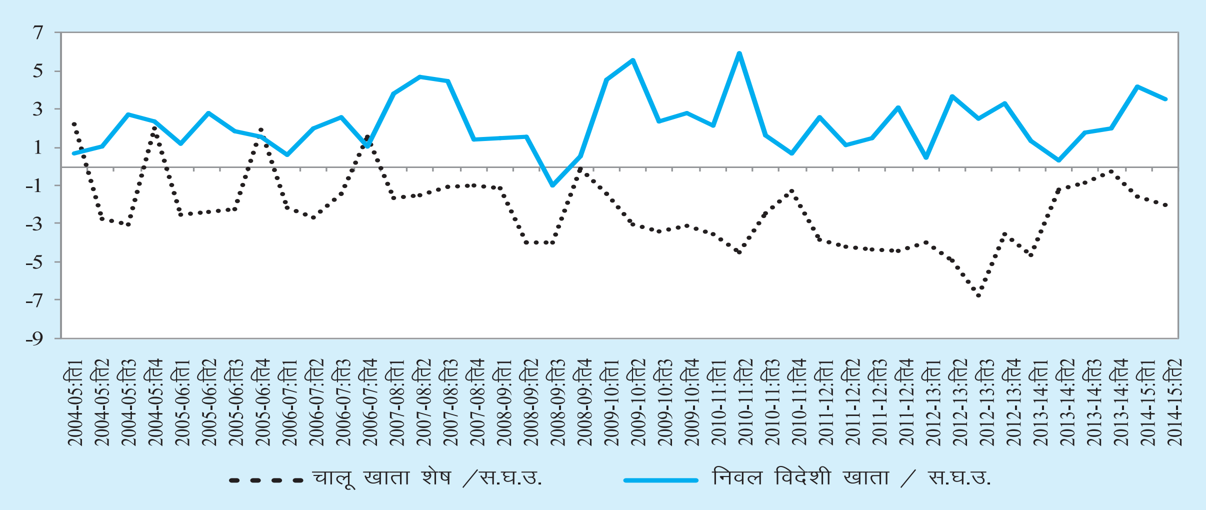

चित्र 1.1ग: दैनिक स्टॉक मूल्य (निफ्टी), जनवरी 2013 से फरवरी 2015

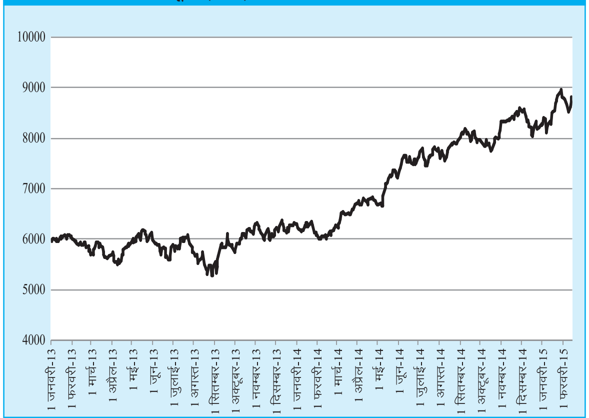

चित्र 1.1घ: त्रैमासिक स.घ.उ. वृद्धि 2005-06 ति.1 से 2014-15 ति.4 (प्रतिशत)

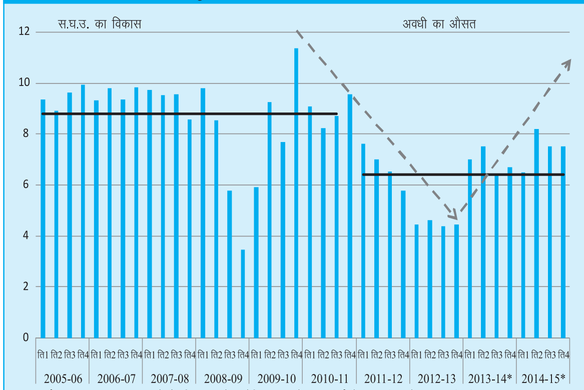

वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के त्रैमासिक आंकड़े संशोधित 2014 के आधार वर्ष के साथ सीएसओ द्वारा जारी की गई नई स.घ.उ. श्रृंखलाओं से लिए गए हैं।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार कार्यालय, औद्योगिकी पॉलिसी और संवर्धन विभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय स्टॉक एक्सचेंज।

चित्र 1.2: वर्ष 2010-15, चुनिन्दा उभरते बाजार देशों के बृहद संवेदनशील सूचकांक

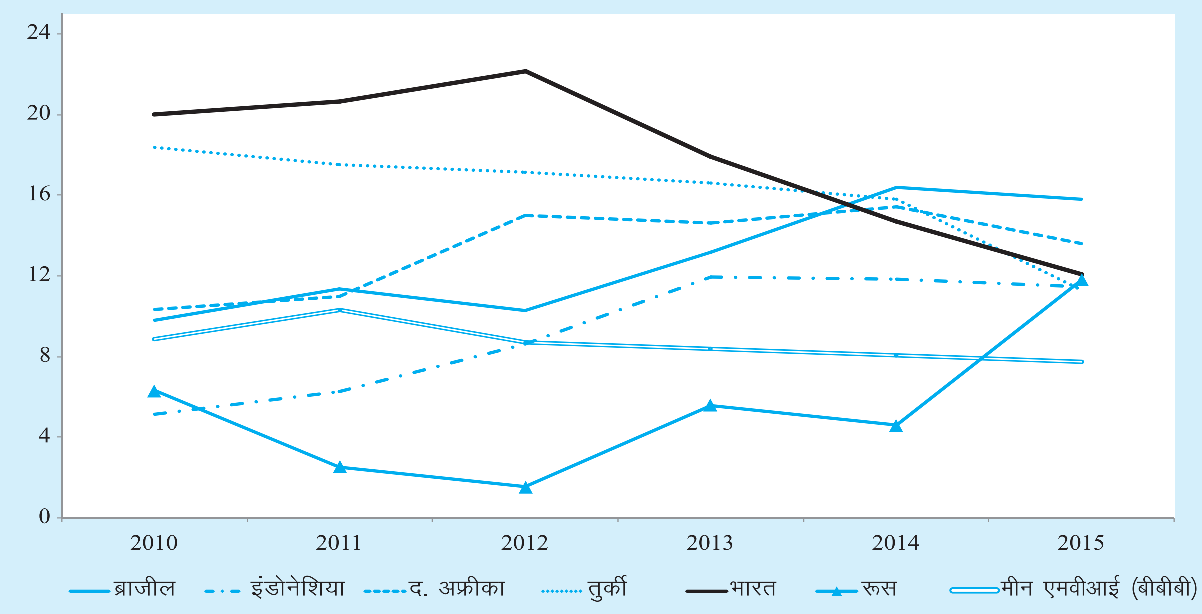

चित्र 1.3: 2010-2015 तक चुनिन्दा उभरते बाजार देशों के युक्ति मूलक निवेशक निर्धारण सूचकांक, 2010-2015

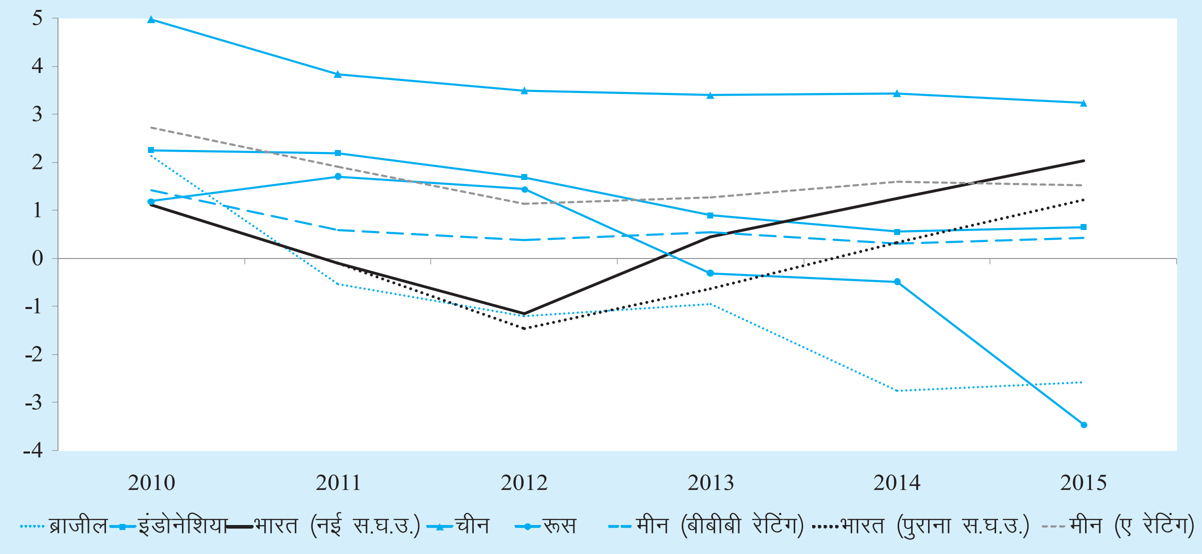

1.2क. वृहत आर्थिक प्रबंधन और नीतिगत सुधार

अनेक क्षेत्रें में सुधारों की शुरूआत की गई है, जिनमें से मुख्य क्षितिज पर हैं ट्रेड शॉक के समर्थन योग्य वृहत आर्थिक प्रत्युत्तर समुचित रूप से वृद्धित सरकारी बचतों और निजी खपत के दूरदर्शी मिश्रण की ओर इशारा करता हैं

नई सकार के नीतिगत सुधारों–वास्तविक और संभावित–ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी और आकर्षित है ये सुधार, जिनका संचित प्रभाव, निवेश और विकास के पुनर्जीवन पर विशेष रूप से हो सकता है, को बाक्स 1.2 में दर्शाया गया है। हांलॉकि वृहत आर्थिक प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसका आकलन सरल विश्लेषण परक अर्थों में किया जाना चाहिए।

जून 2014 से कच्चे तेल की कीमतों और अन्य जिन्सों में आई सूची 50-55 प्रतिशत की गिरावट के परिणाम स्वरूप ट्रेड शॉक स्थिति का अत्यधिक अनुकूल वातावरण भारत के पक्ष में आया है। मानक वृहत आर्थिक मैनुअल से जो आदेश

बॉक्स : 1.1 : स॰घ॰उ॰ और स॰घ॰उ॰ वृद्धि के संशोधित अनुमान

नए अनुमानों के बावजूद साक्ष्यों में ताल मेल और इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि भारत को विकसित होती अर्थव्यवस्था की बजाए पुनरूद्धार करते रही अर्थव्यवस्था के रूप से देखा जाए।

30 जनवरी को, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने स॰घ॰उ॰ की नई श्रृंखला जारी की जिसमें आधार वर्ष के 2004-05 से बदल कर 2011-12 किए जाने के साथ-साथ अधिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना और बेहतर विधि का प्रयोग शामिल था (समीक्षा के खण्ड 2 के अध्याय-1 विस्तार से बताया गया है)। स॰घ॰उ॰ के नए अनुमान वर्ष 2011-12 स 2014-15 तक के लिए दिए गए हैं।

इन अनुमानों को किस नज़रिए से देखा जाए? पहले, आंकड़ों और विधियों में सुधार होने से भारत स॰घ॰उ॰ के अनुमान लगाने में अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान स्तर पर आ गया। भारत इस बात में अनोखा है कि स॰घ॰उ॰ के संशोधनो के कारण आंकड़े कम हो जाने हैं न कि अधिक होते है जैसाकि कई देशों में दिखा जाता है। 2011-12 जो नया आधार वर्ष है, के स॰घ॰उ॰ स्तर के मुख्य अनुमान वस्तुत: पहले अनुमानिक आंकड़ो से 2 प्रतिशत कम है।

तथापि, विकास के अनुमान और अधिक विचार किया जाना जरूरी बना रहे हैं। दूसरी ओर, 2013-14 के मुबाबले 2014-15 के विकास अनुमान, बेहतर होते निवेशक माहौल और सुधार कार्रवाइयों के अनुरूप और संभव भी दिखाई दे रहे हैं।

दूसरी ओर, सही दिशा और स्तर के संदर्भ में 2013-14 के विकास अनुमान पेचीदा दिखाई दे रहे है। नए अनुमानों के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान बाजार मूल्यों में वृद्धि 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई (आधार मूल्यों पर विकास के लिए 1.5 प्रतिशतता बिन्दु)।

अर्थव्यवस्था के अन्य विकासों के साथ इन आंकड़ों का समायोजन करना कठिन प्रतीत होता है। वर्ष 2013-14 एक कठिन वर्ष था। निवेश प्रवाह अत्यधिक था, ब्याज दरें कठोर थी, समय कम था- और यह देखना कठिन है कि किसी अर्थव्यवस्था की विकास दर को ऐसी परिस्थितियों में कैसे गति प्रदान की जाए। वर्ष 2013-14 के दौरान वस्तुओं के आयात में भी 10 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट आयी जिसमें सोने के आयात में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। विकास में जो उछाल आया है उसका कारण आयात में आया उछाल है, न कि आयात में आयी गिरावट। यह उछाल घरेलू मांग पर अत्यधिक भरोसा करना था क्योंकि सकल बाह्य मांग का अंशदान अत्यधिक नकारात्मक था।

यह विकास उछाल, लगता है, बचत और निवेश अनुपात में अत्यधिक गिरावट को भी साथ में लिए हुए था, उदाहरण के लिए सकल निर्धारित पूंजी संरचना जो वर्ष 2011-12 में 33.6 प्रतिशत थी वह वर्ष 2013-14 में गिरकर 29.7 प्रतिशत रह गई जबकि सकल घरेलू बचत 33.9 प्रतिशत से घटकर 30.6 प्रतिशत रह गई। पेचीदगी यह है कि संकट वर्ष 2013-14 के दौरान विकास उछाल भारी उत्पादकता उछाल भी थी जिसे वृद्धिमान पूंजी अनुपात में देखा गया, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आयी और कुल घटक उत्पादकता विकास जिसमें दो प्रतिशत बिन्दुओं से भी अधिक वृद्धि हुई। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान निजी कारपोरेट निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि इसका कारण स्ट्रेस्ड् बैलेंसशीट और स्टाल्ड परियोजनाएं थीं।

नईश्रृंखलाओं को समझने के कुछ क्लू, निम्नलिखित चार्ट में दिए गए हैं जो नईश्रृंखला के बीच के भेद को वास्तविक ळक्न विकास दर और डिफलेटर से संबंधित भेद को समाप्त करते हैं। इस अपघटन को क्षेत्रवार रूप में दर्शाया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पन्न उत्पन्न दोश्रृंखलाओं के बीच और विनिर्माण क्षेत्र के बीच की भारी विसंगतियों जहां कि इसकी गंभीरता 6 प्रतिशत बिन्दुओं तक है: यहां तक कि 2012-13 के दौरान विनिर्माण में दोश्रृंखलाओं के बीच का डायवर्जेन्स 5 प्रतिशत बिन्दुओं तक है। ळक्न के विनिर्माण शेयर के स्तर में उछाल का कारण नई मैथडोलोजी है। परन्तु यह अभी तक अस्पष्ट है कि विकास की दर को पूर्व के अनुमानों और विनिर्माण विकास के अन्य संकेतकों से इतना अधिक डायवर्ज क्यों होना चाहिए (अर्थात् औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक इस तथ्य को स्वीकार करने के बावजूद कि बाद वाला इंडेक्स एक आयतन इंडेक्स है, और पहले वाला एक मूल्य वृद्धित इंडेक्स है भारी विषमताएं हैं। स्पष्ट है कि इन मुद्दों की वृहत्तर विस्तृत परीक्षा किए जाने की जरूरत है।

जब तक कि विश्लेषण और तुलनाओं के लिए विस्तृत आंकड़ाश्रृंखला उपलब्ध नहीं हो जाती और जब तक नए बेस की संगत भूमिकाओं में परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक नए आंकड़े और संवर्धित मैथेडोलाजी और गत कुछ वर्षों से विकास विवरण को पूरा समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। प्रगति कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने के लिए अद्यतन आंकड़ों को विश्लेषणपरक दृष्टि से देखने की जरूरत है क्योंकि उन्हें एक ही बार देखने का मौका मिलेगा लेकिन साक्ष्यों के तालमेल और सतर्क सलाहकार प्रवाहमान भारतीय अर्थव्यवस्था के बजाय उसकी व्याख्या के पक्ष में है।

चित्र: आर्थिक वृद्धि के नए एवं पुराने अनुमानों में अन्तर, 2012-13 तथा 2013-14 (प्रतिशत)

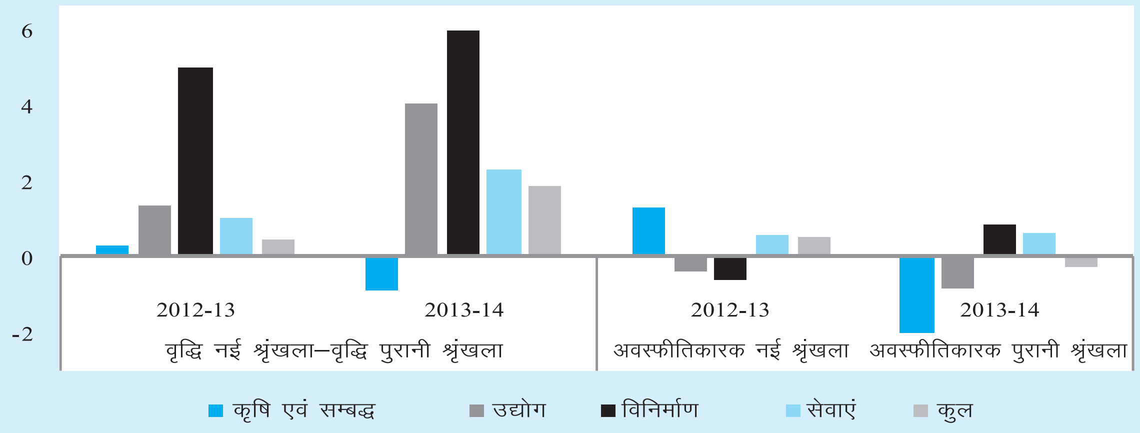

स्रोत : **केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।**

स्वीकृत हुआ है वह ट्रेड शॉक स्थिति के प्रत्युत्तर में उनकी प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए: एक सकारात्मक शॉक जिसे स्थायी तौर पर प्राप्त किया जाए, को वृहत्तर खपत वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि देश की स्थायी आय में वृद्धि है; दूसरी ओर अस्थायी सकारात्मक शॉक से वृहत्तर बचत होनी चाहिए। भारत ने क्या किया?

शॉक की प्रकृति के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए भारत समुचित रूप से बाड़बंद हो गया है। निम्न चित्र 1.4 में अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आयी गिरावट की तुलना पेट्रोल और डीजल की घरेलू रीटेल कीमतो में आयी संगत गिरावट के साथ की गई है। वर्ष 2014 के जून माह के अन्त से अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आयी है इस में से लगभग 17 प्रतिशत (संपूर्ण) गिरावट का लगभग 34 प्रतिशत) ग्राहकों को दे दिया गया, जबकि शेष सरकार ने अपने पास रख लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेड शॅप के टर्म्स का 66 प्रतिशत सरकार की बचत में गया ओर शेष ग्राहकों को दे दिया गया (जैसा कि खण्ड 1.12 में दर्शाया गया है) इस संबंध में सरकार की कार्रवाई से वस्तुत: कार्बन कर के रूप में सहायता की जा रही है)। कीमतों के भावी उतार-चढ़ाव के बारे में अनिश्चितता के लिए वृहत आर्थिक प्रत्युत्तर में बचत और खपत के साथ समुचित संतुलन बना लिया है। और पहले का पक्ष लेना है, बशर्ते कि भविष्य में उच्चतर तेल कीमतों के प्रभाव को सहन करने के लिए आवश्यक साधन मिल जाए।

1.2 ख. विकास की संभावनाएं

थोड़े समय के लिए निम्नतर तेल कीमतों से निम्नतर मूल्य वृद्धि और निम्नतर मूल्य वृद्धिपरक अपेक्षाओं द्वारा सुविधा से सम्पन्न समान मौद्रिक नीति से, और सामान्य मानसून की भविष्यवाणी से विकास को गति मिलेगी। मध्यवधि संभावनाओं को ''बैलेंसशीट सिंड्रोम विद इंडियन करेक्टेरस्टिक्स'' द्वारा अनुकूलित किया जाएगा जिसमें निजी क्षेत्र पूंजी निवेश में तीव्र वृद्धि को होल्डबैक करने की संभावना है।

आने वाले वर्ष के दौरान वास्तवित जीडीपी विकासदर को बाजार कीमतों के आधार पर लगभग 0.6-1.1 प्रतिशत बिन्दु जो वर्ष 2014-2015 की तुलना में अनुमानित किया जाएगा। इस वृद्धि के लिए चार घटकों की जरूरत पड़ेगी, पहला सरकार ने अनेक सुधार शुरू किए हैं और अन्य अनेक की योजना बना रही है (बॉक्स 1.2)। उनका संचित विकास प्रभाव सकारात्मक रहेगा।

वृद्धि के लिए और प्रेरण मुद्रास्फीति में जारी अनुकूलन द्वारा प्रदत्त बढ़ती हुई आर्थिक सुविधा तेल की घटती हुई कीमतों द्वारा दी जाएगी। कर कटौतियों के प्रभावों को अनुरूप करने और तेल की कीमतों में गिरावट आने से परिवारों की खर्च करने की शक्ति में वृद्धि होगी। खपत और वृद्धि में उछाल आएगा। तेल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण इनपुट भी है और घटती हुई कीमतें लाभ मार्जिनों के लिए सहारा होगी और इसलिए कारपोरेट सेक्टर की तुलनपत्रों में भी सहायता प्रदान करेगी। गिरती हुई इनपुट लागतें थोक मूल्य सूचकांक में परिलक्षित होती हैं जो जनवरी 2005 में अवस्फीति को दर्शाता है।

मुद्रास्फीति में और अधिक गिरावट और उसकी परिणामी आर्थिक सुविधा से वृद्धि के लिए लाभ संवेदी सेक्टरों में परिवारों के खर्च को प्रोत्साहित करके और फर्मों के ऋण बोझ घटाकर, उनके तुलनपत्रों को सशक्त करके दोनों द्वारा नीतिगत समर्थन मिलेगा। अंतिम अनुकूल वेग वह मानसून होगा जिसका पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य रहने का पूर्वानुमान किया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए आधार के रूप में नए प्राक्कलन का प्रयोग करके यह वर्ष 2015-16 में 8.1-8.5 प्रतिशत के बाजार मूल्य पर वृद्धि अन्तर्निहित होती है।

सभी बोटों को उठाने के लिए वृद्धि की शक्ति मुख्यत: से इसके रोजगार सृजन की संभावना पर निर्भर करेगी। दीर्घकालिक रोजगार रुझानों पर आंकड़ों की व्याख्या करना डाटा स्रोतों के विस्मयकारी बहुलता, कार्य प्रणाली और कवरेज के कारण कठिन होता है (बाक्स 1.3 देखें)। एक संभावित निष्कर्ष यह है कि वर्ष 1990 के दशक की तुलना में वर्ष 2000 के दशक में दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि में संभवत: गिरावट रही है और संभवत: वृद्धि के रोजगार में लचीलापन लाने में कमी रही है। अर्थात् वृद्धि की निर्दिष्ट मात्रा के कारण विगत की तुलना में अपेक्षाकृत कम जॉब सृजित हुए हैं। यह स्पष्ट तथ्य है कि श्रमिक बल वृद्धि (अनुमानत: 2.2-2.3 प्रतिशत है) रोजगार वृद्धि (लगभग 1½ प्रतिशत) से अधिक है इसलिए रोजगार अवसर सृजित करने की चुनौती महत्वपूर्ण रहेगी।

1.2ग सुधारों के दृष्टिकोण

आगामी माहों के दौरान अनेक सुधार भारी निवेश और वृद्धि में मददगार होंगे। बजट प्रावधान में वित्तीय समेकन मध्यावधि फ्रेमवर्क में अन्त: स्थापक कार्रवाईयों की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। 2004 के लिए भारत के जीडीपी राशियों पर समग्र राजस्व का प्राक्कलन आईएमएफ द्वारा 19.5 प्रतिशत किया गया है। इसके लिए तुलनाकर्ता देशों में विद्यमान स्तरों की ओर जाना आवश्यक होता है जो उभरते हुए एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 25% और जी 20 में उभरते हुए बाजार देशों के लिए 29 प्रतिशत के रूप में आकलित है। इसी दौरान व्यय नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के दौरान

चित्र 1.4: ईधन: अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में गिरावट, अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 (लीटर/रुपए एवं बैरल/अमरीकी डॉलर)

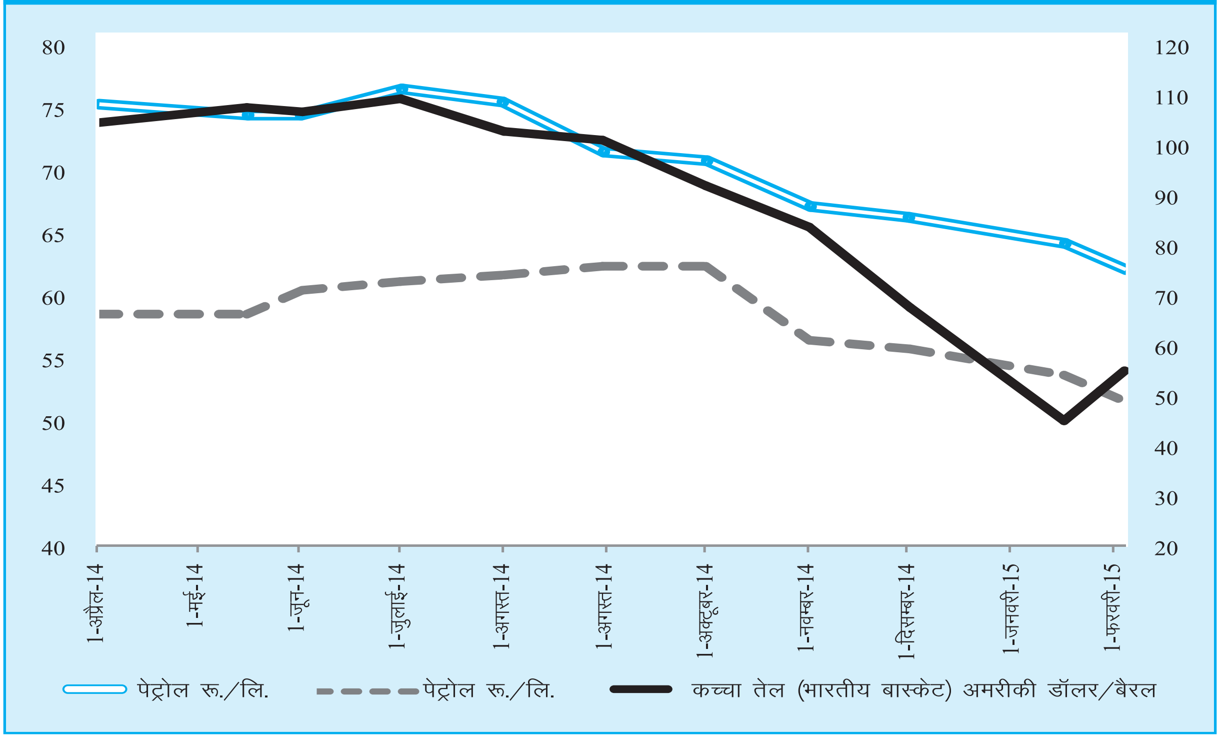

स्रोत : **पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पीआईबी, भारत सरकार।**

टिप्पणी : **पेट्रोल और डीजल की कीमतें अखिल भारतीय औसत पर आधारित हैं।**

---

4. http://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/el-nino-scare-abandoned-normal-indian-monsoon-likely-in-2015/

बाक्स 1.2 : नई सरकार की सुधार संबंधी कार्रवाईयां

मई 2014 से जबसे नई सरकार सत्ता में आयी है उसने अनेक नए सुधारात्मक उपायों की शुरूआत की है जिनका पर्याप्त संचित प्रभाव हो सकेगा।

इनमें शामिल हैं:–

- पेट्रोलियम क्षेत्र में नए निवेशों की सुविधा के लिए डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट करना;
- गैस कीमतों को 4.2 अमेरीकी डालर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट को 5.6 अमेरीकी डालर बढ़ाना और मूल्य निर्धारण करने को पारदर्शिता के साथ स्वत: ही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ जोड़ना ताकि वृहत्तर गैस आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकें और परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र को संकट से उबारा जा सके;
- ऊर्जा उत्पादों पर कर लगाना। चूंकि अक्टूबर से तेल की गिरती कीमतों का लाभ उठाते हुए डीजल और कोयले पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में चार गुना वृद्धि की गई थी। लगभग 70 हजार करोड़ रुपए की संग्रहण के अलावा (वार्षिक आधार पर), इस कार्रवाई से सकारात्मक पर्यावरणात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जैसा कि खण्ड 11 में उल्लिखित है।
- रसोई गैस की सब्सिडी को पूरे देश में सीधे उपभोक्ता के खाते के अन्तरित करना।
- व्यय प्रबंधन आयोग का गठन करना जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट व्यय विभाग को युक्ति-युक्त संगत बनाने के लिए प्रस्तुत कर दी है।
- बोलियों के द्वारा कोयला क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अध्यादेश पारित करना।
- वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) पर राजनीतिक सहमति प्राप्त करना जिससे संविधान संशोधन विधेयक के विधायी पैसेज को अनुमति मिलेगी।
- वित्तीय अन्तर्वेशन के लिए मुख्य कार्यक्रम शुरू करना-प्रधान मंत्री जन-धन योजना-जिसके अंतर्गत फरवरी के मध्य तक 12.5 करोड़ नए खाते खुल चुके हैं;
- आधार कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज का विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास करना, एक बिलियन भारतीयों के नामांकन का लक्ष्य, फरवरी के प्रारंभ तक 757 मिलियन भारतीयों की जैव पहचान (बायो आइडेंटीफिकेशन) हो चुकी है और 139-आधार संबद्ध बैंक खाते खोले जा चुके हैं;
- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाना;
- सोने पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना;
- भूमि अर्जन को सरल बनाने के लिए अध्यादेश जारी करना, जिससे व्यापार करने की लागत को सुविधाजनक बनाया जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल गया है;
- राजस्थान में श्रम सुधारों के लिए राष्ट्रपति परिसंपत्ति को सुविधा प्रदान करना, राज्यों द्वारा और अधिक सुधार प्रयासों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना, और अनेक श्रम विधियों को समेकित करना व उन्हें पारदर्शी बनाना; तथा
- बीमा में एफडीआई कैप को 49 प्रतिशत तक बढ़ाकर अध्यादेश पारित करना विनिवेशों का कार्यक्रम चालू करना जिसके अंतर्गत कोल इंडिया में 10% सरकारी जोखिम पब्लिक को दिया गया था, लगभग 22500 करोड़ रुपए की प्राप्तियां जिसमें से 5800/- करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों से प्राप्त किए गए थे।
- खनन और खनिज पदार्थ (विकास और विनियम (एमएमडीआर) संशोधन अध्यादेश 2015 पारित करना देश में अब तक के गतिरोधित खनन क्षेत्र को पूनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शिता और राज्यों के लिए भारी राजस्वों में परिनियामक होगी।

समेकित होना चाहिए कि आर्थिक सहायताओं के प्रावधान में लीकेजों को दूर करने और लक्षित प्रक्रिया में सुधार करने से इसमें सार्वजनिक खपत से सार्वजनिक निवेश के रूप में परिवर्तन आया है।

निवेशकों के लिए कानूनी निश्चितता और विश्वास दिलाने के लिए कोयला, बीमा और भूमि संबंधी अध्यादेशों को संसद द्वारा अनुमोदित विधान में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन को भी संसद द्वारा पहले विधान में परिवर्तित किया जाना और उसके बाद राज्यों के अनुमोदन द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता है। सीमित छूट के साथ अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों पर निर्धारित एकल जीएसटी दर (संपूर्ण राज्यों और उत्पादों के लिए) इसकी प्रो. वृद्धि, प्रो. अनुपालन और प्रो. एकल बाजार सृजक संभावना को अधिकतम करेगी।

यद्यपि आधुनिक और व्यापक अप्रत्यक्षकर प्रणाली के लिए रूपरेखा जीएसटी की सहायता से तैयार की जा रही है, फिर भी प्रत्यक्ष कर के संबंध में समान प्रयास करना अपेक्षित है।

बाक्स 1.3 : रोजगार वृद्धि और रोजगार में लचीलापनः प्रमाण क्या है?

रोजगार वृद्धि और आर्थिक वृद्धि के सापेक्षिक इसके लचीलेपन के प्राक्कलन अति व्यापक है। तथापि प्रयोगात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि रोजगार वृद्धि और इसमें लचीलापन 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में कमी हुई है। चूंकि श्रमिक बल में वृद्धि रोजगार वृद्धि से अधिक है इसलिए श्रमिक आमेलन एक चुनौती होगी। सुधारों और तीव्र आर्थिक वृद्धि को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा।

यदि नए जीडीपी आकलन बढ़ा दिए गए हैं तो मौजूदा आर्थिक विकासों, रोजगार वृद्धि आकलन पैटर्नों की हमारी समझ के बारे में प्रश्न चुनौती से कम नहीं है। भारत में रोजगार वृद्धि पर आकलन लगभग विस्मयकारी है। विभिन्न समयावधि के लिए आंकड़े विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिनके कवरेज नमूना आकार अलग-अलग कार्य प्रणालियों के होते हैं। इनका वर्णन नीचे तालिका में किया गया है।

तालिका : विभिन्न डाटा स्रोतों की आवधिकता, कवरेज और जनसंख्याआकार

क्र.सं.	डाटा स्रोत	आवधिकता	सेक्टर कवरेज	जनसंख्या/नमूना
1.	जनगणना	दशकीय	संपूर्ण	जनसंख्या
2.	श्रम ब्यूरो (एलबी)	वार्षिक	संपूर्ण	नमूना (वर्ष 2013-14) के सर्वेक्षण में 1.37 परिवार, 6.80 व्यक्ति।
3.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस)	पंचवर्षीय	संपूर्ण	नमूना (वर्ष 2011-12 के दौर में 1.02 परिवार, 4.57 व्यक्ति।
4.	आर्थिक जनगणना (ईसी)	कोई निर्धारित अवधि नहीं	सभी स्थापनाएं जिसमें असंगठित क्षेत्र भी शामिल है और इसमें फसल उत्पादन पौधारोपण, लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा शामिल नहीं है।	नमूना (वर्ष 2014 की आर्थिक जनगणना में 25 लाख परिवार, 56 मिलियन स्थापनाएं
5.	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)	वार्षिक	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2ड(i) और 2ड(ii) के अधीन पंजीकृत सभी कारखाने और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से पंजीकृत बिजली के उत्पादन संभरण और वितरण में लगे सभी विद्युत उपक्रम	वर्ष 2012-13 के सर्वेक्षण में 2.17 लाख कारखाने

टिप्पणी : (1) जनगणना में नियोजित व्यक्तियों को मुख्य और सीमांतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

(2) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में रोजगार का मुख्य और गौण दोनों स्थितियों का लेखा जोखा होता है।

(3) श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण से हम 15 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या का आकलन करते है।

(4) वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक के एएसआई आंकड़ों के लिए, जनगणना क्षेत्र को आशोधित किया गया था ताकि इसमें 200 और इससे अधिक कामगारों के बजाय 100 और इससे अधिक नियोजित कामगारों की यूनिट शामिल की जा सके। अतः 2000-01 के बाद के आंकड़े पिछले दौर के आंकड़े से तुलना योग्य नहीं है।

1990 के दशक और 2000 के दशक के लिए जीडीपी वृद्धि से संबंधित रोजगार वृद्धि के लचीलेपन और रोजगार वृद्धि के बारे में ये स्रोत हमें क्या बताते हैं? संबंधित परिणाम नीचे तालिका में संक्षेप में दर्शाए गए हैं।

तालिका: रोजगार वृद्धि और रोजगार लचीलापन

	जनगणना		राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण		श्रम ब्यूरो	आर्थिक जनगणना		उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण	
	1991 to 2001	**2001 to 2011**	**1993-94 to 1999-2000**	**1999-00 to 2011-12**	**2011-12 to 2013-14**	**1990 to 1998**	**1998 to 2014**	**1990-91 to 1998-99**	**2003-04 to 2012-13**
रोजगार में परिवर्तन (मिलियन)	88.4	79.2	25.5	73.4	9.15	12.9	44.4	0.43	5.07
रोजगार वृद्धि	2.5	1.8	1.1	1.4	1.0	2.1	2.7	0.6	5.7
जीडीपी वृद्धि	5.7	7.7	6.8	7.3	4.6	6.1	6.6	5.5	10.7
रोजगार में लचीलापन	0.44	0.24	0.16	0.19	0.22	0.35	0.41	0.12	0.54

कुल अति प्रयोगात्मक निष्कर्ष पूर्णतया अस्पष्ट प्रक्कलनों से निकाले जा सकते है। सकल रोजगार वृद्धि 1990 के दशक में 2 प्रतिशत अधिक रही है। यद्यपि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े भिन्न भिन्न दर्शाते है, फिर भी जनगणना और आर्थिक जनगणना इस संबंध में परस्पर काफी जनदीक है। दोनों ही जनगणनाओं और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 2000 के दशक में रोजगार वृद्धि में 1.4 और 1.8 प्रतिशत के बीच गिरावट आई है। इसके प्रतिफल संगठित उद्योग में रोजगार वृद्धि के आंकड़े 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में पर्याप्त उच्चतर रोजगार वृद्धि के साथ प्रतिशत अस्थायी पैटर्न दर्शाते है।

वृद्धि के रोजगार संबंधी लचीलेपन के लिए वैसे ही पैटर्न का सुझाव दिया गया है अर्थात 1990 के दशक में लगभग 0.35–0.44 का उच्चतर लचीलापन और 2000 के दशक में लगभग 0.2 की गिरावट दर्शाती है। श्रम ब्यूरो से प्राप्त सर्वाधिक नवीनतम आंकड़े यह संकेत देते हैं कि वर्ष 2011–12 तक भी रोजगार संबंधी लचीलापन कम रहा है। रोजगार आमेलन प्रमाणिक रूप से विगत दशक में कम सफल था।

जिस पर ध्यान न देते हुए डाटा स्रोत का प्रयोग किया जाता है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रोजगार वृद्धि श्रमिक बल में वृद्धि से पीछे है। उदाहरण के लिए वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनगणना के अनुसार श्रमिक बल में वृद्धि 2.23 प्रतिशत थी (पुरुष एवं महिलाओं को जोड़कर)।

यह इस दशक में किए गए रोजगार वृद्धि के अधिकांशत: आकलनों से कम है जो कि लगभग 1.4 प्रतिशत है। अधिक तीव्र रोजगार अवसर सृजन करना स्पष्ट रूप से प्रमुख पॉलिसी चुनौती है। रोजगार के लचीलेपन की संगणना में रोजगार और वृद्धि के आंकड़ों के मध्य कवरेज की संगतता यथासंभव मात्रा में सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए आर्थिक गणना डाटा के लिए विनिर्माणकारी जीडीपी का प्रयोग प्रसंगिक आधार के रूप में किया जाता है। उद्योगों का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के लिए कुछ मूल्य वर्धन (विनिर्माणकारी जीडीपी द्वारा अवस्फीति) का प्रयोग संगणनाओं के आधार के रूप में किया जाता है।

[1]रोजगार लोचता के परिकलन में, रोजगार और विकास डाटा के बीच कवरेज की संगति संभावित सीमा तक सुनिश्चित की जाती है। उदाहरण के लिए, ईसी डाटा के लिए विनिर्माण जीडीपी संगत बेस के रूप में प्रयुक्त की जाती है जबकि ए.एम.आई. सकल मूल्य वृद्धि (विनिर्माण जी.डी.पी. द्वारा अपस्फीति कारक) को परिकलन में आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

References: Misra, Sangita and Anoop K Suresh *"Estimating Employment Elasticity of Growth for the Indian Economy"*, 2014, RBI Working Paper Series 6.

Mehrotra, Santosh "Explaining Employment Trends in the Indian Economy: 1993-94 to 2011-12", 2014, Economic and Political Weekly, XLIX(32).

इसका उद्देश्य प्रतियोगी, पूर्वसूचनीय, स्पष्ट और छूट युक्त कम कर नीति का ऐसा विधान तैयार करना होना चाहिए जिससे पूंजीगत लागत, प्रोत्साहन बचत में कमी आए और करदाता के लिए इसका अनुपालन सुविधाजनक हो।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा स्फीति नियंत्रण में वर्तमान लब्धियों को समेकित करने के लिए आर्थिक नीति फ्रेमवर्क अनुबंध तैयार करना और एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था को संहितावद्ध करना चाहिए जो वस्तुत: व्यवहार में हो। यह इस बात का संकेत होगा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति के उद्देश्यों की पूर्ति में संयुक्त रूप से प्रयासरत हैं। मजदूरी और भूमि कानूनों के सुधारों और कारोबार करने की लागतों को घटाने के लिए राज्यों और केंद्र को संयुक्त रूप से प्रयास करना आवश्यक होगा (स्पष्टीकरण के लिए वर्ष 2014–15 के छमाही आर्थिक विश्लेषण का बॉक्स 3 देखें) जीएसटी को लागू करने संबंधी अद्भुत बदलाव की संभावना और प्रत्यक्ष लाभ देने वाली प्रौद्योगिकी–जिसे जेएएम (जन धन–आधार–मोबाईल) संख्या त्रयी समाधान को कम नहीं आंका जाना चाहिए।

1.3 मुद्रास्फीति और धनराशि

मुद्रास्फीति संबंधी प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन पर निम्नतर तेल कीमतों और कृषि कीमतों तथा मजदूरियों में मंदन के कारण अभी कार्रवाई जारी है। ये परिवर्तन प्रभावशाली ढंग से उन्नत परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में साथ-साथ परिलक्षित हो रहे हैं।

अर्थव्यवस्था से भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा स्फीति लक्ष्य 0.5-1 प्रतिशत तक प्रभावित होने की संभावना होती है, और इससे आर्थिक नीति को और अधिाक सरल बनाने का मार्ग खुलता है।

जैसा कि छमाही आर्थिक विश्लेषण 2014-15 में विस्तार से दिया गया है। मुद्रा स्फीति की गति ने बाजार भागीदारों और नीति निर्माताओं को आश्चर्य चकित किया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी है। तिमाही औसत के आधार पर मौसमी रूप से समायोजित और वार्षिक आधार पर मापित वृद्धि लागभग 15 प्रतिशत से घटकर 5% से कम रह गई है। (चित्र 1.5)[5] यह रूचि कर है कि खाद्य मूल्यों में तेजी अत्यधिक कम हो गई है और यह समग्र मुद्दा स्फीति के स्तर से नीचे है।

आगे बढ़त हुए यह तीन क्षेत्रों मे गति तीन महत्वपूर्ण विकासों के कारण अवरोधित हो सकती है जो भारत में मुद्रास्फीति प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत कच्चा तेल (कूड ऑयल) कृषि और मुद्रास्फीति की संभावनाएं।

कच्चे तेल की कीमतों के आगामी माहों में हितकर रहने की संभावना है। वस्तुत: (कच्चे तेल स्थल) के लिए आईएमएफ और ब्रेंट और वेस्ट टेक्सेज इंटरमीडिएट क्रूड के लिए यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) द्वारा किए गए प्राक्कलनों का औसत यह दर्शाति है कि तेल की कीमतें वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान लगभग 29 प्रतिशत कम होगी (59 अमेरीकी डालर बनाम अमेरिकी डालर 82) (चित्र 1.6)

यह जोखिम कि तेल की कीमतों में गिरावट आने से यह संभावना हमेशा मौजूद रहती है कि यह स्वत: ही बढ़ जाएगी जिसका कारण भौगोलिक, राजनैतिक परिदृश्य में अचानक घटित होने वाली गतिविधियां है। तथापि अनुकूलित तेल कीमतों की निरन्तरता से कम से कम तीन घटकों अर्थात कमजोर सार्वभौमिक मांग, बढी हुई आपूर्ति और सार्वभौमिक आर्थिक तथा नकदी स्थिति के लिए अत्यधिक संभाव्य प्रतीत होती है। विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में धीमे विकास के कारण मांग कमजोर रहेगी जिसमें चीन और यूरोप भी शामिल है। आपूर्ति में परिवर्तन देखा गया है जो अमेरिका में कच्चे तेल और शैल गैस उत्पादन में बृद्धि और ओपेक की अल्पविक्रेता अधिकार में सहवर्ती कमी से संबद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि इसका प्रमुख उत्पादक सऊदी अरब है (जिसने अन्य स्रोतों से आपूर्ति में वृद्धि पर प्रतिक्रिया न करने का निर्णय लिया है) इसके अतिरिक्त कीमतों का लगभग 60 से 65 प्रति बैरल अमेरिकी डालर पर आंकलित शैल उत्पादन की सीमांत लागत बढ़ाते हुए निर्धारण किया जा सकता है।

अन्तत: अमेरिका में असाधारण निम्न ब्याज चक्र की में प्रत्याशित समाप्ति और भावी दर वृद्धियों की संभावना से तेल को अधिक समय तक ने रखकर उसे बाहर निकालना और उसके द्वारा आपूर्ति को और बढ़ाना तथा कीमतों को कम रखना उचित होगा उच्चतर दरों के कारण वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनर्नियतन यू॰एस॰ वित्तीय इंस्ट्रमेंट में एक वर्ग आवश्यक वस्तुओं से विशेष रूप से तेल से दूर होगा।

वर्ष 2000 का एक पाठ अनुदेशात्मक है। यह दशक, उन्नत देशों में विद्यमान तुल्यकालिक आर्थिक नीति द्वारा सृजित नकदी आधिव्य के कारण आंशिक वस्तु मूल्यों में पूर्णरूप से वृद्धि का साक्षी है। उस तुल्यकालन को परिवर्तनकारी दीर्घ-आर्थिक मार्गों द्वारा खंडित किय गया है। जिसमें बसूली के कारण एक तरह सामान्य आर्थिक नीति में प्रत्यार्वतन होगा और दूसरी ओर यूरोप और जापान जहां नीतियां शिथिल हो सकती है, वस्तुत: यदि चीन अपेक्षाकृत सस्ते क्रेढिट और मूल्य द्वारा विनिमय दर के माध्यम से इसे कम करता है और इस पर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया करता है, तो वैश्विक नकदी की स्थिति में पुन: कभी हो सकती है लेकिन यूएस तब भी कठिनाई के दौर (टाइट्रेनिक मोड) में रहेगा।

दूसरी बात वह है कि तेल की कीमतों के अतिरिक्त, भारत की मुद्रा स्फीति कृषि, विदेशी और घरेलू दबाबों से निर्धारित होगी। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार वैश्विक कृषि कीमतें मंद रहेगी जिसमें वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 4.8 प्रतिशत की कमी हो सकती है। इसका महत्वपूर्ण

---

[5] Figure 1.5 is based on the new, re-based (from 2010 to 2012) CPI index.

[6] Arezki, R & Olivier Blanchard, "*The 2014 oil price slump: Seven key questions*", January 2015 accessed at http://www.voxeu.org/article/2014-oil-price-slump-seven-key-questions.

चित्र 1.5: सीपीआई में घट-बढ़ (आधार 2012) दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2014 (प्रतिशत)

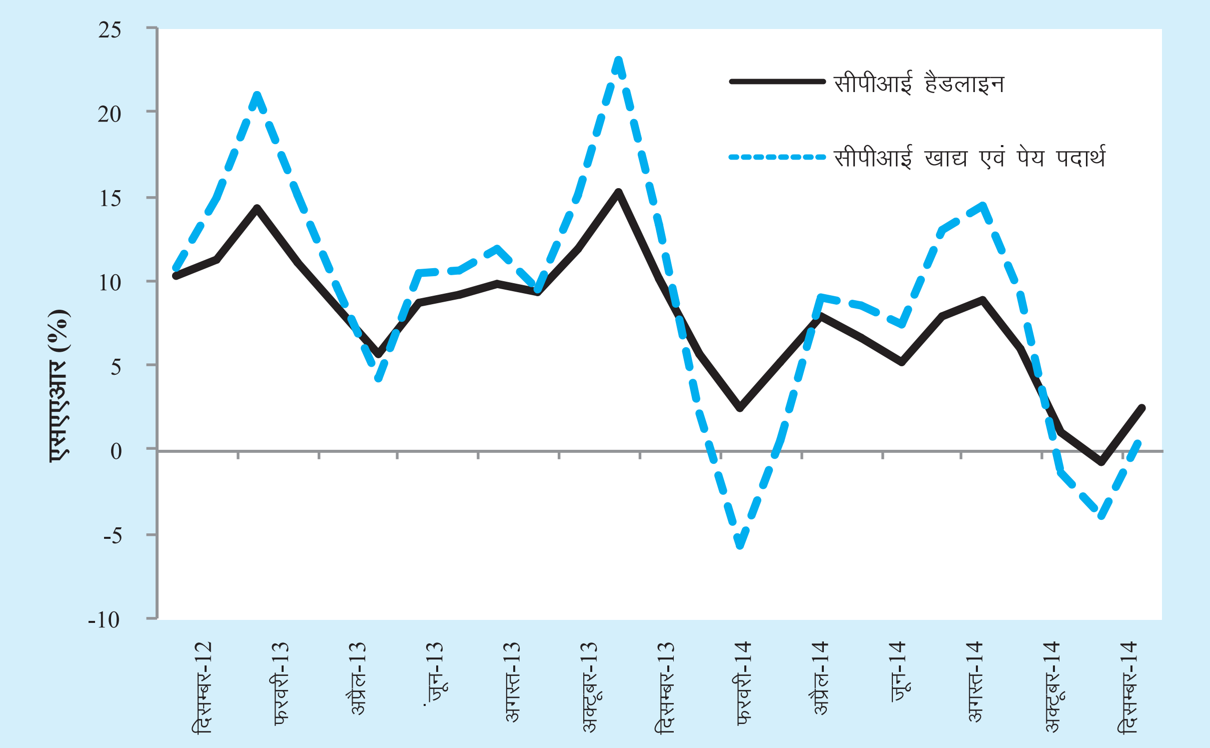

स्रोत : सीएसओ

चित्र 1.6: दिसम्बर 2017 तक ब्रेंट क्रूड का वायदा मूल्य (प्रति बैरल अमरीकी डॉलर

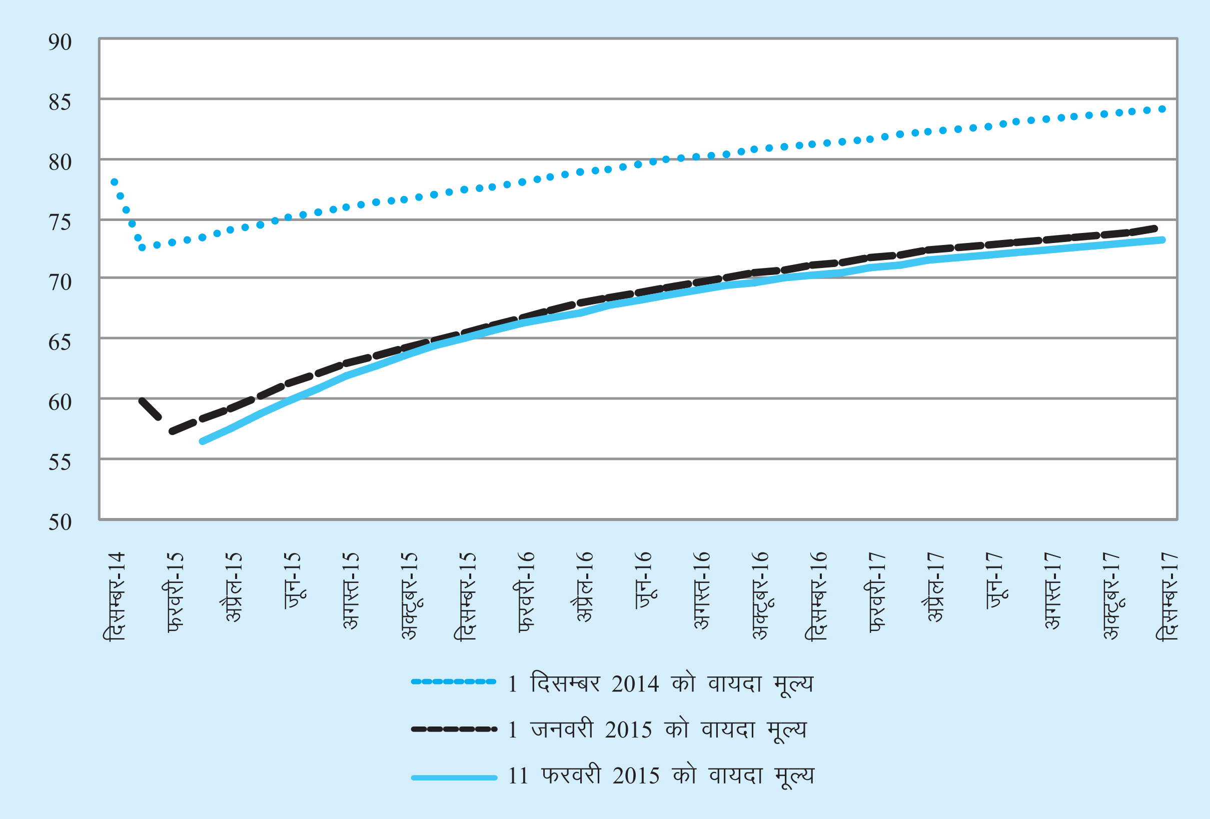

स्रोत : थामसन राइटर्स

प्रभाव घरेलू समर्थन मूल्यों में अनुकूल बृद्धि पर पड़ सकता है

सर्वाधिक आकस्मिक संरचनात्मक परिवर्तन मजदूरी दवावों से संबंधित होता है। जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। मजदूरी वृद्धि 20 प्रतिशत से लगभग 3.6 प्रतिशत कम हुई है। यदि यही रूझान जारी रहते है, तो ग्रामीण मजदूरी वृद्धि से और भी अनुकूल मुद्रास्फीतिकारी दबाव का कम होना जारी रह सकता है। तिलहनों और दलहनों का घरेलू उत्पादन लक्ष्य से कम हो सकता है किन्तु अत्यधिक आयातों से इस क्षेत्र की मुद्रा स्फीति संबंधी घट बढ़ को कम करने में मदद मिलेगी।

तीसरा घटक मुद्रास्फीति प्रत्याशा से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मुद्धस्फीति प्रत्याशा का घरेलू सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि प्रत्याशाएं अटल रूप से स्थायी और वास्तविक मुद्रास्फीति से काफी ऊंचे स्तरों पर रही हैं। किन्तु अत्याधुनिक सर्वेक्षण के अनुसार सभी क्षेत्रो में 7-8 प्रतिशत तक गिरावट आई है (चित्र 1.8)। यदि परिवर्तन का संकेत मिलता है तो मुद्रा स्फीति प्रत्याशाएं अधिक युक्तिसंगत स्तरों, अनुकूल मजदूरी स्तर पर स्थिर हो जाएंगी।

संक्षेप में, वह संरचनात्मक परिवर्तन, जिस पर छमारी आर्थिक विश्लेषण 2014-15 में चर्चा की गई थी, भलीभांति होता दिखाई दे रहा है। उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति जिसका 2014-15 में मुद्रण 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है वह और भी नीचे आ सकता है। वर्ष 2015-16 के लिए हमारा प्राक्कलन उपभोक्ता कीमत सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए 5.0 से 5.5 प्रतिशत की सीमा में है और जीडीपी डिफ्लेटर के लिए 2.8-3.0 प्रतिशत की सीमा में है। इसमें जटिलता यह है कि अर्थव्यवस्था मुद्रा स्फीति पर अत्यधिक प्रभाव डालेगी जिससे आगामी आर्थिक नीति सुविधा के लिए मार्ग निर्वाध होगा।

वित्तीय बाजारों के रूझान से यह पता चलता है कि हाल ही के कुछ माहों में जमादरों की क्रमिक सुविधा रही है। क्योंकि 10 वर्षीय सरकारी बांडों पर प्राप्त राशियों में इस अवधि के

चित्र 1.7: ग्रामीण मजदूरी वृद्धि, नवम्बर 2005 से नवम्बर 2014 (प्रतिशत)

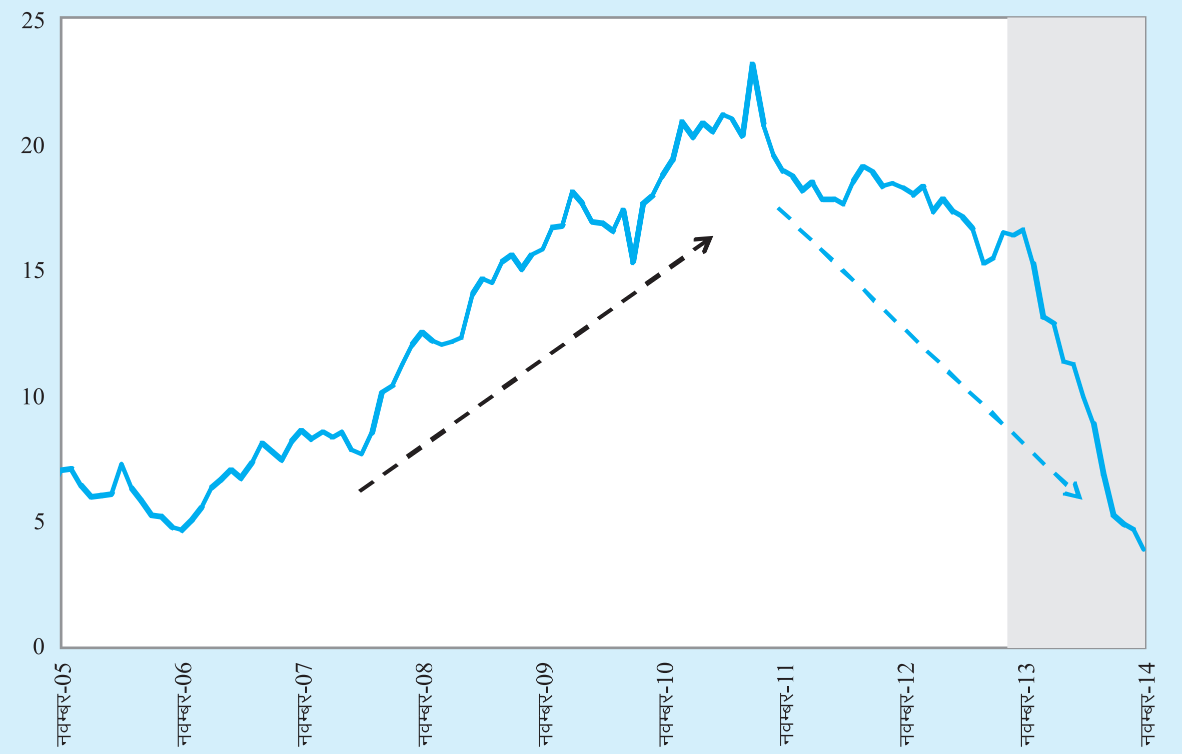

स्रोत : श्रम ब्यूरो

[7] तिलहन तथा दलहनों का घरेलू उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है, परंतु अधिक आयात करने से स्फीतिकारी दबाव को कम करने में मदद मिल सकेगी।

चित्र 1.8: परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सितम्बर 2008 से दिसम्बर 2014 (प्रतिशत)

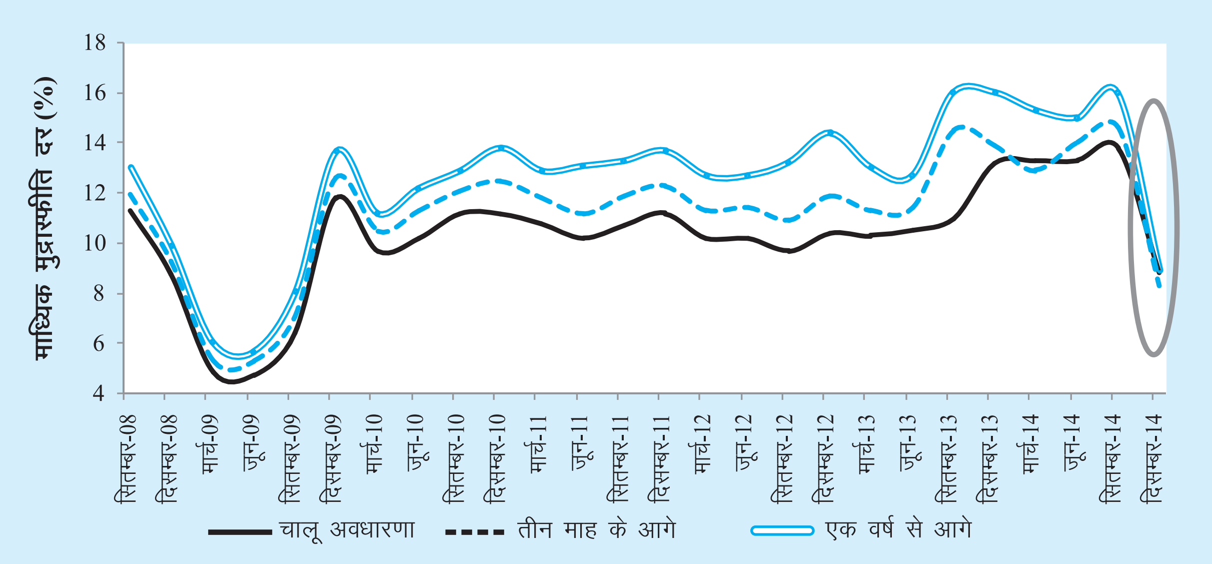

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दौरान निस्तर गिरावट रही है। (चित्र 1.9)। ये घटती हुई प्राप्तियां आगामी माहों में बैंकों द्वारा उधार दरों में कमी का संकेत दे सकती हैं।

मुद्रास्फीति संबंधी स्थितियों को आसान करने से भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक नीति में परिवर्तन का पहले ही संकेत दे दिया था जब 2015 में इसने पॉलिसी रेपो रेट मे 25 आधार अंक को 7.95 प्रतिशत तक किया थां एक प्रकार से भावी मौद्रिक नीति को आसान बनाकर पॉलिसी दर को बाजार दरों के अनुसार किया जा सकता है।

नकदी स्थितियां वर्ष 2014-15 तक सामान्य रूप से संतुलित रही हैं। संशोधित नकदी प्रबंधन फेमवर्क के कार्यान्वयन से ओवर नाइट इंटर बैंक सेगमेंट में परिवर्तन-शीलता कम करने और कॉल दर को पॉलिसी दर के समकक्ष बेहतर बनाने में मदद मिली है। वित्तीय घाटे के नियंत्रण में रहने और नई नकदी प्रबंधन फेमवर्क के यथा स्थान रहने से नकदी स्थितियों के वर्ष 2015-16 में अनुकूल रहने की संभावना है।

1.4 बाहय क्षेत्र (सेक्टर)

उक्त दृष्टिकोण चालू लेखा और इसके वित्त पोषण के लिए अनुकूल है। विदेशी पूंजी की कमी अपेक्षा संभावित अधिकता से विनिमय दर प्रबंधन जटिल होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (यू॰एस॰) की आर्थिक नीति में परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों और यूरोजोन में होने वाले उतार चढ़ावों पर निगरानी रखना आवश्यक होता है किन्तु यह नियंत्रण में होना चाहिए।

बाह्य क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण शायद 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से और विशेषत: वर्ष 2012-13 की तुलना में सर्वाधिक अनुकूल रहा है जब उच्च गुणवत्ता का तेल और स्वर्ण आयातों से मौजूदा लेखा घाटे में पूर्ति हुई है कच्चे पेट्रोलियम वैश्विक कीमतों का औसत जनवरी 2015 में लगभग 47 अमेरिका डालर प्रति बैरल और अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक) संपूर्ण वर्ष के लिए 90 अमेरिकी डालर प्रति बैरल था। कच्चे तेल और अन्य उत्पादों के औसत वार्षिक मूल्य में और भी अनुकूलता मानते हुए चालू लेखाघाटा को वर्ष 2014-15 के लिए जीडीपी का लगभग 1.3 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में जीडीपी का 1.0 प्रतिशत से कम आकलित किया गया है।

यह व्यावहारिक है कि तेल की कीमत में 10 अमेरिकी डालर की कमी से निवल व्यापार को सुधारने में मदद मिली है और इसी लिए चालू लेखा शेष 9.4 बिलियन अमेरिकी डालर तक हुआ है। अनुकूलित स्वर्ण आयातों से भी चालू घाटे को प्रबंध योग्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। नवबंर में सोने पर प्रतिबंधों को दूर करने से स्वर्ण आयात वर्ष 2013 में देखे गए उच्च गुणवत्ता स्तरों से काफी नीचे आ गए है घटती हुई अन्तरराष्ट्रीय कीमतों और मुद्रा स्फीति को अनुकूल करने का यह प्रभाव पड़ा है कि स्वर्ण आयातों का औसत दिसंबर 2014 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डालर और वर्ष 2015 के जनवरी माह में 1.6 बिलियन अमेरिकी डालर था जो अक्टूबर 2014 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डालर, और नवम्बर 2014 में 5.6 बिलियन अमेरीकी डालर था।

चित्र 1.9: बाण्ड प्राप्तियाँ, जुलाई 2014 से फरवरी 2015 (प्रतिशत)

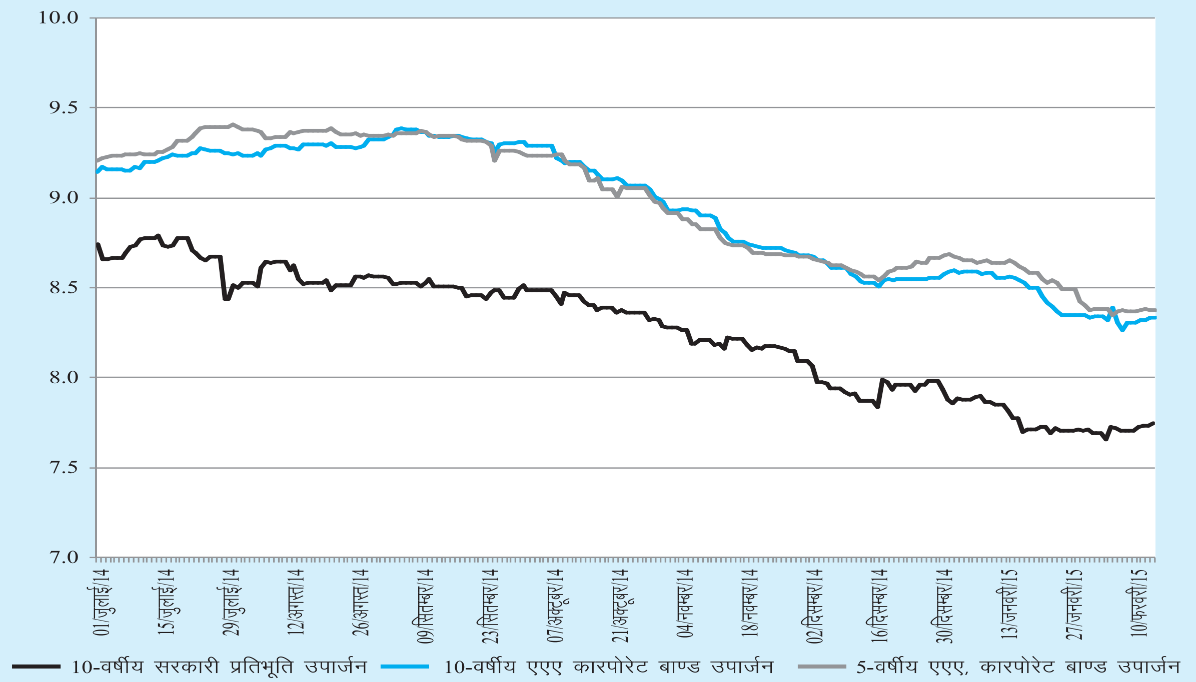

स्रोत : **भारतीय रिजर्व बैंक**

बाह्य वित्त पोषण के लिए दृष्टिकोण संगत रूप से अनुकूल है और कमी के बजाय उतार चढ़ाव अपेक्षाकृत अत्यधिक चुनौती का सामना कर सकता है। वर्ष 2014.15 में वित्तीय प्रवाह 5.5 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक होने की संभावना है जिसके कारण जमा राशि 26 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर लगभग 340 बिलियन अमेरिकी डालर तक हो जाएगी।

इसे व्यापक भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बाजार दखल द्वारा सुविधाजनक बना दिया गया है। यह अन्तर्वाह (प्राप्तियों) के वर्ष 2015-16 के अधिकांश भाग तक बने रहने की संभावना है। एक प्रमुख जटिलता यह है कि यदि चालू लेखा घाटा कम होता है तो पूंजी प्राप्तियां निर्धारित स्तर से रुपए पर अत्यधिक ऊर्ध्वगामी दबाव पड़ेगा।

चिन्ता का एक कारण अवमंदित निर्यात और बढ़ते हुए गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयात है। जिस पर भारत की ह्रासकारी प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रभाव पड़ सकता है जो जनवरी 2014 तक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के 8.5 प्रतिशत वृद्धि में परिलक्षित होती है। यहां रोचक तथ्य यह है कि व्यापार भागीदारों के सापेक्षिक भारत में उच्चतर मुद्रास्फीति का योगदान केवल 2.3 प्रतिशत प्वाइंट ही है और शेष 6.2 प्रतिशत प्वाइंट रुपए के खाते में जोड़ा जाता है जो अन्यच मुद्राओं की तुलना में मामूली स्तर तक मजबूती प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में स्पॉट और अग्रवर्ती बाजार दोनों में भारतीय रिजर्व बैंक का दखल होते हुए भी परिवर्तन-शील पूंजी प्राप्तियों में थोक ह्रासकारी प्रतिस्पर्धात्मकता का लेखा जोखा होता है।

इन वित्तीय प्राप्तियों के लाभों का निर्यात पर उनके प्रभाव चालू लेखा का समाधान करना आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है दूसरे शब्दों में भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी लेखा के खुलेपन और परिवर्तनशील प्राप्तियों, आर्थिक नीति स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता का समाधान करने के लिए संघर्ष करने में स्थूल आर्थिक दुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

निम्नलिखित चार घटक बाह्य स्थिति पर प्रभाव डालते हैं:

- *यू॰एस॰ फेडरल रिजर्व मॉनेटरी टाइटेनिंग के प्रत्युत्तर में नवीनीकृत वित्तीय बाजार परिवर्तनशीलता जिसकी इस वर्ष के बाद प्रत्याशा की जाती है।*
- *यूरोजोन की व्यवहार्यता ग्रीक एक्जिट के परिणामस्वरूप प्रश्न उठाए जाने पर संभावित हलचल।*
- *भू-राजनैतिक गतिविधियों से संबद्ध तेल कीमतों में स्पाइक।*
- *धारे-धीरे ह्रास होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर्यावरण। फेड और यूरोजोन से उत्पन्न जोखिमों पर दो बिन्दुओं का महत्व नगण्य होता है।*

चित्र 1.10: विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2013 से जनवरी 2015 (बिलियन अमरीकी डालर)

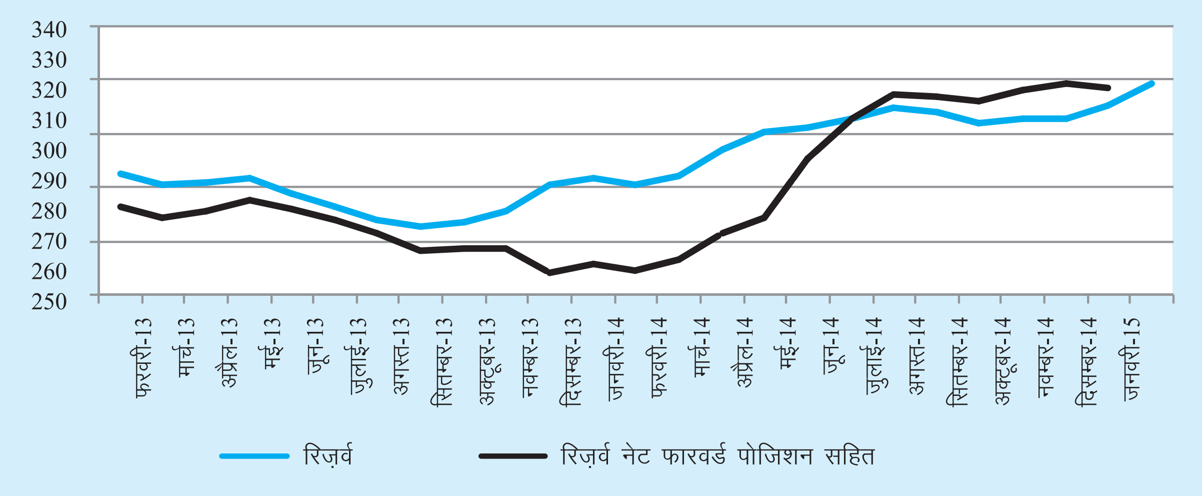

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

पहला प्वाइंट यह है कि भारत पराजेय हो सकता है क्योंकि मार्च 2014 तक विदेशी मुद्रा प्रवाह का पर्याप्त भाग हित संवेदी है, कुल पोर्टफोलियो संचित प्रवाह (38.4 बिलियन अमेरिकी डालर) का लगभग 23.8 बिलियन अमेरिकी डालर पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह रहे हैं। सरकारी और कारपोरेट बांडों पर प्राप्तियों में गिरावट जो चित्र 1.9 में दर्शाई गई है, से ये प्रवाह परिलक्षित होते हैं। फंड टाइटेनिंग के कारण इनमें से कुछ प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन हो सकता है जिससे रुपए पर अधोगामी दबाव पड़ेगा। तथापि भारत इस समय वर्ष 2014 या वर्ष 2013 की अपेक्षा अधिक लचीला है क्योंकि भारत में आरक्षित निधि की मात्रा अधिक है किन्तु अनुकूल स्थूल आर्थिक स्थिति के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि आत्म संतोष कभी प्रमाणित नहीं होता है फिर भी अत्यधिक चिंता का भी डटकर मुकाबला करना चाहिए। आमतौर पर, शायद व्यापार चुनौती ही चिन्ता का बड़ा कारण है (कृपया नीचे दिए गए खंड 1-11 को देखें)

बाह्य क्षेत्र में एक और मुद्दा भू-सामरिक महत्व (ज्यो स्ट्रेटिजिक) है। यदि आज के निरंतर बढ़ते हुए अंत:निर्भर आर्थिक वातावरण में ताकत के बल पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार के संचय से हार्ड और

चित्र 1.11: सांकेतिक तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर-निर्यात-आधारित सूचकांक जुलाई 2013 से जनवरी 2015

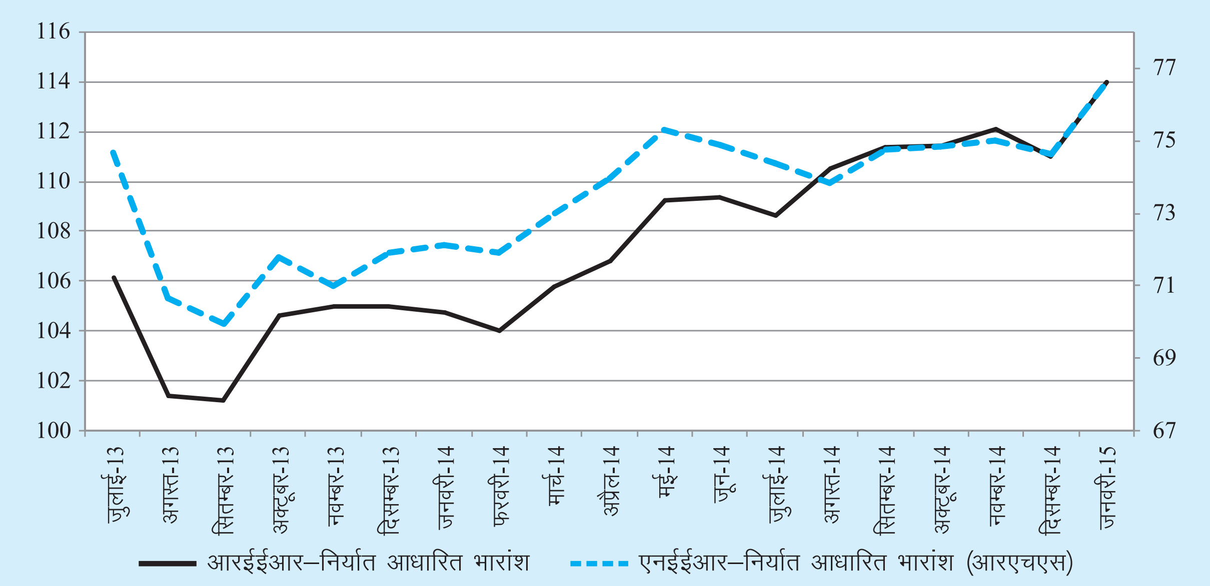

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सॉफ्ट पावर अर्जित की जा सकती है। चीन का प्रचुर मुद्रा भंडार इस तथ्य को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार इन समस्याओं को दूर करता है और आर्थिक तथा वित्तीय लचीलापन लाता है। उधारदाता के रूप में वस्तुत: आज चीन वित्तीय संकट का सामना कर रही सरकारों के लिए एक अंतिम साधन बन गया है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से विकास सहायता के एक बड़े प्रदाता के रूप में बन गया है। चीन अपने आप में सनातनी और बहुविधिक रूप से अपनी आरक्षित निधि के कारण अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि और विश्व बैंक दोनों की भूमिका निभा रहा है। इस समय आरक्षित निधि का अर्जन लागत रहित नहीं है क्योंकि इसके लिए वाणिज्यिक नीति और वित्तीय तथा विनिमय बाजार के परिणामी विकृति की नीति अपेक्षित होती है। किन्तु इसके लिए लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है। भारत के उभरते हुए आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के रूप में इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि इसे भी अपनी आरक्षित निधि में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। अधिमानत: क्रमिक संचयी चालू लेखा आधिक्य के माध्यम से प्राप्त अपनी निधियों को दीर्घकाल में 750 बिलियन अमेरिकन डालर-1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखकर इस आरक्षित निधि में वृद्धि की जाए।

1.5 कृषि

खरीफ फसल (जुलाई-सितम्बर 2014) का पहला अग्रिम आकलन पिछले वर्ष की तुलना में कम उत्पादन दर्शाता है। तथापि, इस आकलन को सामान्यत: ऊर्ध्वगामी दिशा में संशोधित किया जाता है। हाल ही में, आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा जारी रबी की फसलों के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल क्षेत्र में कमी आयी है किन्तु गेहूं की फसल के क्षेत्र में 2.9 प्रतिशत तक की कमी आई है। अन्यथा वर्ष 2014-15 के लिए सीएसओ ने कम वर्षा के बावजूद जो दीर्घकालिक औसत का केवल 88% ही था और 2013-14 में यह अत्यधिक था, कृषि के लिए 1.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर का आकलन किया है। सीएसओ का आकलन मूल्य वर्धित है जबकि कृषि उत्पादन आंकड़े मात्रा पर आधारित होते हैं। इसलिए सकारात्मक कृषि जीडीपी वृद्धि मात्रा में कमी के संगत नहीं है क्योंकि इनपुट लागतें तेजी से बढ़ जाती हैं। किन्तु शायद कृषि में तीव्र परिवर्तन हो सकता है जिसके कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। कृषि की दिशा में व्यापार संदर्भ में दशक का दीर्घ परिवर्तन का अन्त हो गया है क्योंकि कृषि मूल्य चरम सीमा पर पहुंच गए हैं इसको चित्र 1.12 में दर्शाया गया है जो दो भिन्न माध्यमों के अनुसार कृषि के लिए व्यापार के संदर्भों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दोनों ही अनेक वर्षों के सुधार[8] के बाद वर्ष 2000 से 2011 से आगे धीमी गिरावट दर्शाते हैं।

कृषि इनपुट, अंतिम खपत और पूंजीगत निवेश के लिए प्रदत्त कीमत का सूचकांक जैसे ही व्यापार के संदर्भ में कमी आती है और ग्रामीण आय पर दबाव पड़ता है। (चित्र 1.7 भी देखें), सहायता के लिए राजनैतिक दबाव में वृद्धि होगी। तिलहन और दलहनों जैसे अनेक क्षेत्रों में टैरिफ में वृद्धि करने और चीनी सेक्टर में निर्यात संबंधी इमदाद देने के प्रस्ताव पहले ही दिए जा चुके हैं।

निकट भविष्य में कृषि में विद्यमान कमी को दूर करने के लिए लक्षित सहायता देने पर विचार करना चाहिए। एमजीएनआरईजीए कार्यक्रम युक्तिसंगत रूप से इस लक्ष्य को पूरा करता है। यहां इस कार्यक्रम को लागू करना और इसका प्रयोग ग्रामीण सड़कों, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन जैसी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए करना ग्रामीण आमदनियों को बढ़ाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है।

आमतौर पर, कृषि में इन चुनौतियों के अधिक से अधिक प्रतिक्रिया और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समय है कि कृषि में निरन्तर आधार पर लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि हो।

एक ज्वलंत समस्या यह है कि कृषि बाजार कितने बिखरे हुए और विकृत हैं। (इस खंड का अध्याय 8 देखें। जिसमें संभव समाधान भी हैं) भारत के हमारे कृषि उत्पाद बाजार समितियां (एवीएमसी) बनाकर कृषि संबंधी आवश्यक वस्तुओं के

---

[8] व्यापार संदर्भों के सूचकांक प्रोफेसर एस. महेन्द्रदेव की अध्यक्षता में मई 2012 में समूह (डब्ल्यू जी) द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित फार्मूले पर आधारित हैं।

(1) व्यापार संदर्भों का सूचकांक =

कृषि उत्पादों के लिए प्राप्त कीमत का सूचकांक x 100

कृषि इनपुट, अंतिम खपत और पूंजीगत निवेश के लिए प्रदत्त कीमत का सूचकांक

(2) व्यापार संदर्भों का सूचकांक =

कृषि उत्पादों और कृषि मजदूरी के लिए संशोधित कीमत का सूचकांक x 100

कृषि इनपुट, अंतिम खपत और पूंजीगत निवेश के लिए प्रदत्त कीमत का सूचकांक

चित्र 1.12: विभिन्न सेक्टरों के मध्य व्यापार शर्तों का सूचकांक/ 2004-05 से 2013-14

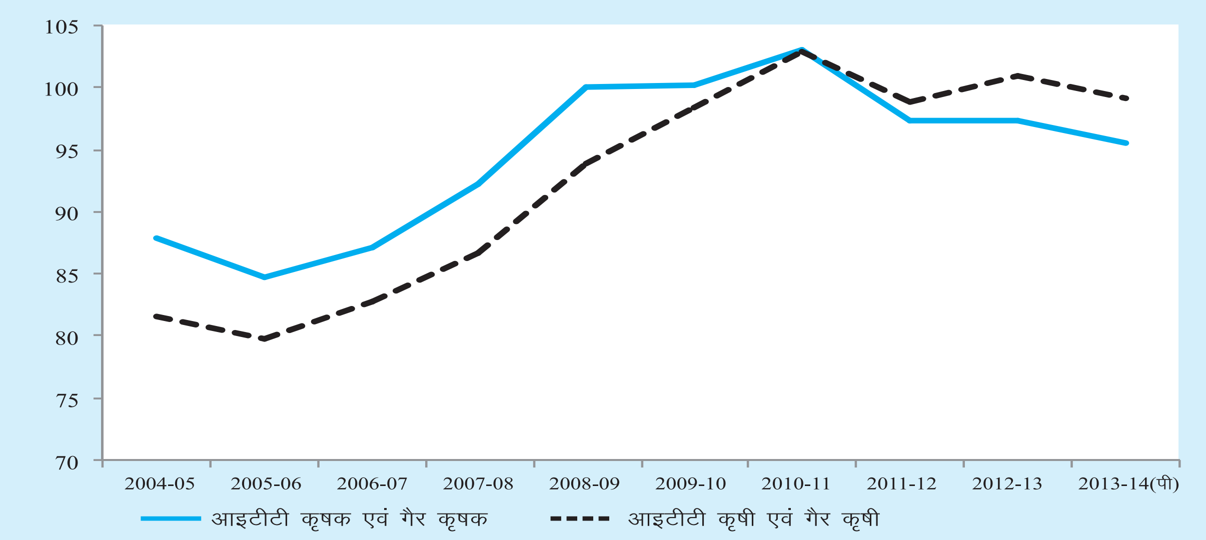

स्रोत : **फुटनोट 8 का संदर्भ करें।**

लिए एक आम बाजार होना आवश्यक है और यह कृषकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए उपलब्ध अनेक विकल्पों में से एक है।

सीधे अंतरणों के माध्यम से आर्थिक सहायता को सरल और कारगर बनाना तथा हिताधिकारियों को बेहतर लक्षित करना सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधनों का एक भाग हुआ जो अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई, जल प्रबंधन, मृदा परीक्षण, भांडागार तथा कोल्ड स्टोरेज में आवश्यक है। विविध नीतियों से होने वाली विकृतियों, जिसमें बिजली और पानी के प्रयोक्ता प्रभारों को छोड़ना भी शामिल है, को बेहतर लक्षित प्रक्रिया लीकेज के माध्यम से कम किए जाने की आवश्यकता है।

शान्ता कुमार समिति की सिफारिशों में खाद्यनीति के भावी रोड मैप के लिए उपयोगी सुझाव हैं। भारतीय खाद्य निगम के कार्य संचालन को पर्याप्त रूप से सुधारे जाने की आवश्यकता है।

राज्यों के अंदर कृषि उपजों में अत्यधिक भिन्नता है। यहां तक सर्वोत्तम राज्यों में भी विश्व के सर्वोत्तम राज्यों की तुलना में विभिन्न फसलों में काफी कम पैदावार है। यह नीचे दी हुई तालिका 1.1 से प्रमाणित किया जा सकता है।

फसली क्षेत्र का एक बड़ा भाग (लगभग 41%) अभी भी असिंचित है। सिंचाई की सुविधा प्रदान करके उपज को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित उत्पादन कार्य में परिवर्तन के लिए मूल्य अनुसंधान में निवेश आवश्यक होगा। यह जलवायु संबंधी जोन के अन्तर्गत यथा-संभव सीमा तक उपज अंतराल को कम करके उत्पादन में वृद्धि करने के प्रचुर अवसर प्रदान करता है।

संस्थागत रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की भूमिका, इसके राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और प्रत्येक संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान) के साथ संबंधों का पुन: निर्धारण करने के लिए यह समय उपयुक्त हो सकता है और अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार को अलग किया जाना चाहिए।

कृषकों के लिए कार्यक्रम अग्रिम कीमत जानकारी प्रदान करने के लिए और उन्हें कीमत जोखिमों से बचने में समर्थ करने के लिए वायदा बाजार आयोग (फारवर्ड मार्केट कमीशन), को सशक्त किया जा रहा है। यह चिन्ता कि इसमें अनावश्यक प्रयास हो सकता है, इसका निवारण वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलसी) द्वारा की गई सिफारिशों के दिशानिर्देशों के साथ प्रभावी विनियम के माध्यम से किया जाना चाहिए।

1.6 वृद्धि-आर्थिक नीति की चुनौतियां

भारत वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता के अनुसार वृद्धि (ग्रोथ) को पुर्नजीवित करने के लिए बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश की अल्पकालिक अनिवार्यता को संतुलित कर सकता है। आगामी बजट में और मध्यावधि बजट दोनों में निवेश के उपभोग से व्यय नियंत्रण और व्यय अन्तरण (स्विचिंग) महत्वपूर्ण होगा।

तालिका 1.1 फसल उपज की तुलना भारत बनाम विश्व

फसल	भारत का सबसे अधिक उपज वाले राज्य	विश्व के सबसे अधिक उपज वाले देश
धान	पंजाब-3952	चीन-6661
गेहूं	पंजाब-5017	यूनाइटेड किंगडम-7306
मक्का	तमिलनाडु-5372	यूएस.ए-8858
चिक पी	आन्ध्र प्रदेश-1439	इथोपिया-1663
कपास	पंजाब-750	आस्ट्रेलिया-1920
अलसी/सरसों	गुजरात-1723	यूके-3588

***टिप्पणी* : यह आंकड़े उपज/किलोग्राम/हेक्टेयर में है जो 2012 से संबंधित है।**

मध्यावधि वित्तीय ढांचा

छमाही आर्थिक विश्लेषण में विस्तार से उल्लिखित वर्ष 2014-15 के बजट के चुनौती पूर्व स्वरूप के होते हुए भी, सरकार जीडीपी के 4.1 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य का अनुशरण करेगी। राजस्व संग्रह और विलंबित विनिवेश में कमियों के बावजूद डीजल और पेट्रोल पर नया उत्पाद शुल्क (लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति) उत्पाद शुल्क पर आर्थिक-सहायता घटा दी गई है और व्यय तुलना से अनुशासन की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।

भारत निजी निवेश में विकास को फिर से बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समेकन की अपेक्षाओं तथा सार्वजनिक निवेश में तेजी लाने की आवश्यकता का समाधान कर सकता है बशर्ते कि सही कार्य योजना तैयार की गई हो। लेकिन ऐसा कैसा संभव हो? चूंकि यह नई सरकार का पहला पूर्ण बजट है और विशेषरूप से प्रेस में दिए गए चौदहवें वित्त आयोग की दूरगामी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसलिए उक्त पृष्ठभूमि में और हाल ही के अनुभव से मिले सबक को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि ढांचे की संवीक्षा करने और आने वाले वर्षों में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त समय है। (चित्र 1.13)

तीन चरण मौजूदा वित्तीय पूर्ववृत्त को चिह्नित करते हैं। वर्ष 2002-2008 के प्रथम भाग में तीव्र वृद्धि के कारण सभी वित्तीय समष्टियों धन-प्रवाह एवं स्टॉकों में सुधार हुआ किन्तु दूसरे चरण (2009-2012) में अत्यधिक प्रति चक्रीय नीतियों (काउण्टर साइक्लिकल पॉलिसीज़) से संयुक्त, उस चरण की समाप्ति की दिशा में व्यय नियंत्रण, विशेषत: राजस्व व्यय की विफलता के कारण वित्तीय नियंत्रण में हानि हुई। जो वर्ष 2013 के आसन्न संकट में सहायक था। पूंजीगत व्यय में आकस्मिकता कम और अवरोधकारी रही है। तीसरे चरण (2013 से अब तक) में वित्तीय स्थिरता थोड़ी सी बहाल हो गई है। इस पूर्ववृत्त से निम्नलिखित कार्य नीति का सुझाव मिलता है।

प्रथमत: आमतौर पर, भारत को अपना जीडीपी का 3% मध्यावधि लक्ष्य पूरा करना चाहिए। इससे भावी स्टॉकों को सुनिश्चित करने के लिए ओर इसके उभरते हुए बाजार पीयर्स के वित्तीय निष्पादन के पास पहुंचने के लिए वित्तीय साधन प्राप्त होगा। इससे मौजूदा वर्षों के ट्रेजेक्टरी को भी बदला जा सकता है और राजस्व घाटों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम नियम की प्राप्ति हो सकती है। और इससे सुनिश्चित हो सकता है कि उक्त चक्रानुक्रम में उधार लेना एकमात्र पूंजी निर्माण का साधन है।

दूसरी बात यह है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति का तरीका व्यय नियंत्रण और उपभोग से निवेश में व्यय परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त अन्तिम दशक में पूंजीगत व्यय में दीर्घकालिक गिरावट आने के कारण भारत की दीर्घकालिक विकास (ग्रोथ) संभावनाओं को क्षति पहुंची है। वर्ष 2016-17 से जैसे ही विकास को गति मिलेगी और जीएसटी लागू होगा वैसे ही कर उत्प्लावकता को व्यय से जोड़ा जाएगा तो यह सुनिश्चित होगा कि मध्यावधि लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। यह उत्प्लावकता पूर्ववृत्त से आश्वस्त होती है क्योंकि अन्तिम दशक में वृद्धि (ग्रोथ) में उतार-चढ़ाव के दौरान समग्र कर-जीडीपी अनुपात बाहरी कर सुधार के बिना वर्ष 2003-04 में 9.2 से लगभग 9.7 प्रतिशत तक और 2007-08 में 11.9% तक वृद्धि हुई है।

तीसरी बात यह है कि अनुशासन के प्रति मध्यावधि प्रतिबद्धता को कार्रवाईयों के स्वीकृति स्थगन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आगामी वर्ष में वित्तीय समेकन जारी रहना चाहिए। तथापि, त्वरित वित्तीय समेकन की आवश्यकता कम हुई है क्योंकि मुद्रास्फीति में अत्यधिक गिरावट और चालू लेखा कमी में परिवर्तन से स्थूल आर्थिक दबाव काफी मात्रा में कम हुआ है। इन परिस्थितियों में, विशेषत: अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव के बजाय पुन: बहाल

चित्र 1.13: हालिया राजकोषीय अनुभव 2002-03 से 2014-15 (स.घ.उ. का प्रतिशत)

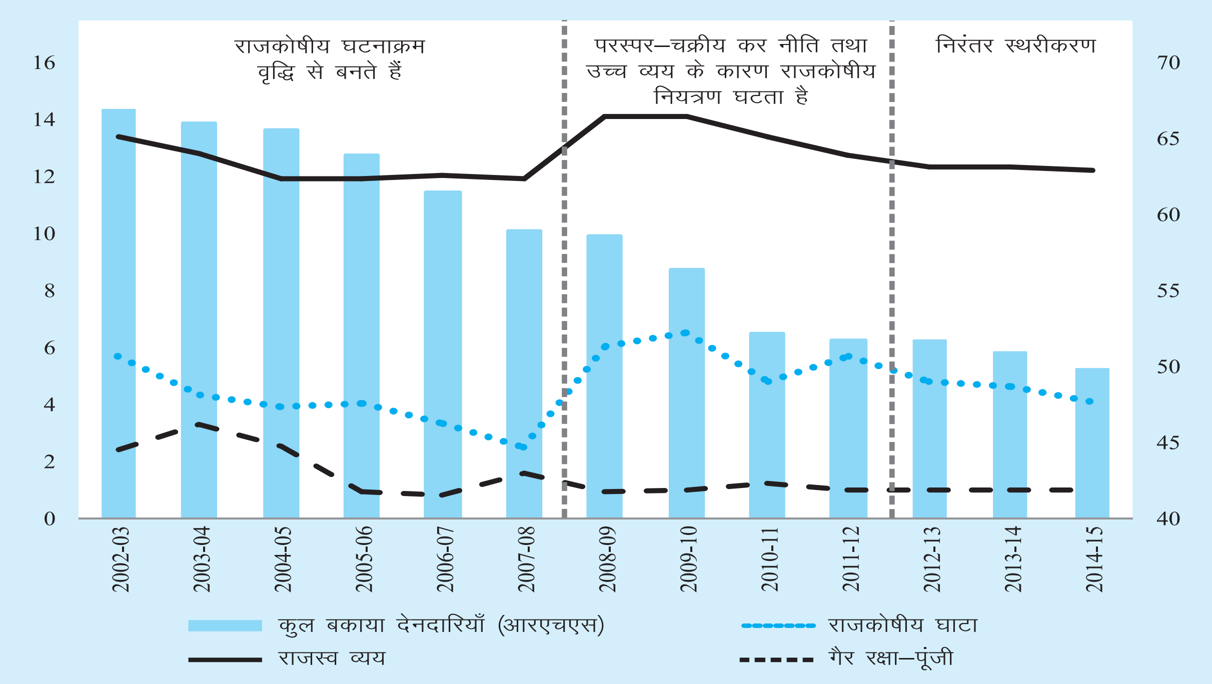

स्रोत : **बजट दस्तावेज और (सीएसओ)।**

टिप्पणी: **वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए आंकड़ों को क्रमशः संशोधित किया जाता है और बजट को आकलित किया जाता है।**

होने पर प्रो–साइक्लिकल नीति इष्टतम से कम होती है।

ऋण संबंधी सिद्धांत अग्रगामी रूप में अनुकूल रहते हैं। जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के तुलनपत्र का तीव्र सशक्तीकरण सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त त्वरित वित्तीय समेकन को चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने, केंद्रीय बिक्री कर में कटौती करने के लिए राज्य प्रतिपूर्ति बाध्यताओं को निपटाने और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता जैसे अनेक नए और अपरिहार्य घटकों द्वारा आगामी वित्त वर्ष में प्रतिबंधित करना है।

अन्यथा वित्तीय विश्वसनीयता और मध्यावधि लक्ष्यों की संगतता सुनिश्चित करने के लिए आगामी बजट से वित्तीय और राजस्व घाटों दोनों में कमी करने के लिए व्यय नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ–साथ व्यय की गुणवत्ता को निवेश के लिए आर्थिक मदद में कमी करके खपत से परिवर्तित करना अनावश्यक होता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए हैं जिनमें आर्थिक सहायता में कटौती करना और उस पर विनिवेश को आगे बढ़ाना शामिल है, उनमें सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद कर वृद्धिओं से उत्पन्न कर जीडीपी अनुपात से लघु और मध्यावधि वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

1.7 हर व्यक्ति का दुख दूर करना: जनधन, आधार, मोबाइल संख्या त्रयी समाधान

यह डिबेट इस बारे में नहीं है कि क्या गरीब और दुर्बल व्यक्तियों को नियत सरकारी सहायता प्रदान की जाए बल्कि इस बारे में है कि उनको यह सुविधा कैसे प्रदान की जाए। जेएएम नं. त्रयी-जनधन आधार, मोबाइल संख्या पर आधारित नकदी आधारित अंतरण स्कीम प्रभावी तौरपर लक्षित संसाधनों को उन व्यक्तियों को प्रदान करने की संभावनाएं प्रदान करती है जिनको इन संसाधानों की सर्वाधिक आवश्यकता है। उस क्षेत्र की सफलता से कीमतों में उदारीकरण आएगा जिससे वे आवंटित संसाधनों के बल पर अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पाएंगे और दीर्घकालिक विकास को नई उचाइयां प्रदान करेंगे।

स्वाधीनता के 68 साल बाद गरीबी भारत की सर्वाधिक दबावकारी समस्याएं बनी हुई है। कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता है जब तक कि उस देश में उसके बहुत से नागरिकों के जीवन से जुड़े अबसर खराब पोषण द्वरा निराशाजनक हो और वहां शिक्षा के अवसर उत्तम कोटि के न हों और लिंग भेद मौजूद हो (जिस पर भाग 13 में चर्चा की गई है)। शिक्षा रिपोर्ट का मौजूदा वार्षिक सर्वेक्षण जो पिछले दशकों से शिक्षा पर गतिरोध दर्शाता है संतुलित रीडिंग

के लिए किया गया है (खंड 2, अध्याय 9 में बाक्स देखें)।

आर्थिक वृद्धि गरीबो के लिए उत्तम होती है क्योंकि इससे आय में वृद्धि होती है और यह लोक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र में निवेश के लिए राज्य संसाधन प्रदान करती है जिनकी गरीबों को आवश्यकता होती है। वृद्धि, संभावनाएं और अवसर जो वृद्धि से आते है उनसे व्यक्ति अपनी निजी मानव पूंजी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। मौजूदा अध्ययन में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि बंगलौर से बाहर स्थित गांवों में रहने वाले परिवारों को केवल यह सूचना देने से कि कॉलसेंटर शिक्षित महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहे है, उन गावों की किशोर बालिकाओं की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की संभावनाओं में वृद्धि हो गई है।

तथापि इस वृद्धि को राज्य द्वारा प्रदत्त ऐसे प्रभावी कायक्रमों से पूरा किया जाना चाहिए जिनसे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसमें सफल होने के लिए गरीबी निरोधी कार्यक्रमों को अवश्य मान्यता दी जानी चाहिए जो नीतियों को व्यक्तियों और फर्मो के अनुरूप प्रोत्साहित कर सकें और राज्य की सीमित कार्यान्वयन ने क्षमता को स्वीकार करे ताकि निर्धनों को लक्षित करने और लोक सेवा प्रदान की जा सके।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विभिन्न उत्पादों पर आर्थिक सहायता देते है जिसका अभिव्यक्त उद्देश्य गरीबों को इन उत्पादों को पहंचाना है। चावल गेहूं, दाले, चीनी, मिट्टी का तेल, एलपीजी, नैप्था, पानी, बिजली, उर्वरक, लौह अयस्क रेलवे आदि ऐसे उत्पाद और सेवाएं जिन पर सरकार आर्थिक सहायता देती है इन (चयनित) आर्थिक सहायता कि आंकलित प्रत्यक्ष वित्तीय लागत लगभग 378000 करोड़ रुपए अथवा जीडीपी का लगभग 4.2 प्रतिशत है। मोटे तौर पर आय वितरण के 35 वें पर सेन्टाइल पर मौजूद परिवारों में से प्रत्येक परिवार के व्यय को बढ़ाने के लिए इसका कितना महत्व होगा। (जो 21.9 प्रतिशत की गरीबी रेखा से काफी ऊपर है। नीचे तालिका 1.2 में इन आर्थिक सहायता की लागत और इनसे लाभान्वित व्यक्तियों का निर्देशात्मक आंकलन है।

नि:संदेश मूल्यों में आर्थिक सहायता (इमदाद) से सहायता मिलती है किंतु इसका गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति पर कई रूपांन्तरकारी प्रभाव नहीं होता। बहुत सी इमदादों का केवल कुछ ही भाग, गरीब लोगों तक पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए विद्युत इमदादी लाभ मुख्य रूप से (अपेक्षाकृत अमीर लोंगों) 67.2 प्रतिशत परिवारों तक ही मिलता है। जल के लिए आबंटित की जाने वाली अधिकांश आर्थिक सहायता निजी नलों को इमदाद पर व्यय हो जाता है जबकि गरीब परिवार सार्वजजनिक नलों से जल प्राप्त करते है।

इसके अलावा आर्थिक सहायता का कार्यान्वयन जटिल हो सकता है। उर्वरकों के मामले में ये फर्म-विशिष्ट तथा आयात-प्रेषण विशिष्ट होते हैं इनमें उर्वरक के प्रकार के आधार पर अंतर होता है और कुछ निर्धारित मात्रा आधार पर होते हैं जबकि कई अन्य परिवर्तनीय होते हैं।

ये आर्थिक सहायता स्वत-स्थायीकरण के निर्दयी तर्क के कारण अतिसंवेदी होती हैं। चीनी के मामले में गन्ना उत्पादकों को संरक्षित करने के लिए उच्चय समर्थन मूल्य दिए जाते हैं; मिल मालिकों पर इस कर की कमी को पूरा करने के लिए इनको आर्थिक सहायता ऋण और निर्यात इमदाद के माध्यम से समर्थन दिया जाता है; और तब उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न शीरे की बिक्री रोक लगा कर पुन: (महसूल) कर लगा दिया जाता है।

विभिन्न प्रकार की इमदाद गरीबों को कष्ट पहुंचाती है। उदाहरण के लिए उर्वरक निर्माताओं को दुर्गम क्षेत्रों में अपने उत्पाद बेचने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि मूल्य नियंत्रण का अर्थ है कि हर जगह एक समान मूल्य, इसलिए रेलवे में माल भाड़ा इमदाद लागू की गई है जिससे कि व्यापक रूप से अपने उत्पाद की आपूर्ति के लिए इन निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जा सके। किंतु ये इमदाद कई बार बहुत अपर्याप्त होती है क्योंकि यहां माल भाड़ा विश्व में सबसे अधिक है और जानबूझ कर इस इमदाद को कृत्रिमता के लिए यात्री किराया कम किया है। यह इस बात को दर्शाने वाला एक उदाहरण है कि किस प्रकार मूल्य नियंत्रण का पाश (जाल) प्रोत्साहन के मार्ग को अवरूद्ध करता है जो अंतत: गरीब परिवारों को क्षति पहुंचाता है।

---

[9] जेन्सन राबर्ट क्या श्रम वाजार अवसर यंग वूमेन्स वर्क एण्ड फैमिली डिसीजन को प्रभारित करते है इंडिया 2012 से प्रायोगिक साक्ष्य। अर्थशास्त्र का तिमाही जर्नल

[10] भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 खंड 1 अध्याय 3

[11] योजना आयोग जुलाई 2013, तेन्दुलकर आयोग पर रिपोर्ट देना।

[12] भारतीय जनगणना (2011), प्रकाश का स्रोत

13 क्या मौजूदा जल सब्सिडी गरीबों तक पहुंचती है एमआईटी और विश्व बैंक वर्किंग पेपर (http://web.mit.edu/urbanupgrading/waterandsanitation/resources/pdf-files/WaterTariff-4.pdf)

सारणी 1.2 निर्धनों को कितनी अर्थिक सहायता का लाभ दिया

उत्पाद	उत्पादकं आर्थिक सहायता	उपभोक्ता आर्थिक सहायता	वित्तीय व्यय	वित्तीय व्यय (2011-12 जीडीपी का प्रतिशत)	लाभ का कितना भाग निर्धनों को प्राप्त होगा?
रेलवे	लागू नहीं	हमदादी यात्रा किराया	₹ 51,000 किराया	0.57 प्रतिशत	निचले 80% परिवारों से रेलवे को किराए के माध्यम से कुल यात्रियों का केवल 28.1 प्रतिशत बनता है।
तरलीकृत पैट्रोलियम गैस	लागू नहीं	हमदादी (अब डीपीटी के माध्यम से)	₹ 3,746	0.26 प्रतिशत	निचले स्तर के 50% परिवार केवल 25 प्रतिशत एलपीजी का उपभोग करते है।
मिट्टी का तेल (केरोसिन)	लागू नहीं	पीडीएस द्वारा हमदादी	₹ 20,415	0.23 प्रतिशत	पीडीएस कैरोसीन आबंटन का 41 रिसाव में नष्ट हो जाता है। केवल शेष बचे 46% की ही गरीब परिवारों द्वारा खपत हो पाती है।
उर्वरक और नाईट्रोजनीकृत सामग्री	जर्म और पोषक निर्माताओं को विशिष्ट हमदाद/सरकार द्वारा विनियमित यूरिआ का आयात	यूरिया के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है	₹ 73,790	0.82 प्रतिशत	यूरिया और पी एवं के निर्माता इमदाद से अधिकांश आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि किसानों विशेषरूप से गरीब किसानों को उर्वरकों के लिए मांग घटती-बढ़ती रहती है
चावल (धान)	न्यूनतम मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य	पीडीएस द्वारा हमदाद	₹ 129,000	1.14 प्रतिशत	पीडीएस चावल का 15% हिसाब में नष्ट हो जाता है। दशमलव के तीन दशमांक के निचले स्तर के परिवार 53 प्रतिशत चावल का परिवारों के पास पहुंचे 85 प्रतिशत चावल में से उपभोग करते है।
गेहूं					पीडीएस गेहूं का 54: रिसाव में नष्ट हो जाता है। दशमल 3 अंकों तक परिवार 46 प्रतिशत शेष बचे गेहूं में से 53 प्रतिशत का उपभोग करते है
दालें	न्यूनतम मूल्य (नयू॰स॰मू॰)	पीडीएस द्वारा इमदाद	₹ 158	0.002 प्रतिशत	निचले 3 दशमक हमदादी दालों के 36 प्रतिशत का उपभोग करते है
विद्युत	इमदादी	बाजर मूल्य से कम	₹ 32,300	0.36 प्रतिशत	निचले क्विंटाइल की औसत मासिक खपत > 45 ज्ञ्ँत ऊपरि क्विंटाइल 121 ज्ञ्ँत की तुलना में निचले क्वटाइल में इमदादी बिजली का केवल 10 प्रतिशत को लाभ मिलता है ऊपरी क्विंटाइल इमदाद का 37% प्राप्त करते है।
जल	लागू नहीं	इमदाद	₹ 14,202	0.50 प्रतिशत	अधिकांश जल के लिए इमदाद का निजी नलों का आबंटन होता है जबकि गरीब परिवारों के 60% परिवार सर्वजनिक नल से अपने लिए पानी प्राप्त करते है।
चीनी	गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य, मिलों को आर्थिक सहायता (इमदाद)	पीडीएस द्वारा इमदाद	₹ 33,000	0.37 प्रतिशत	48 प्रतिशत पीडीएस चीनी रिसाव में समाप्त हो जाती है निचले 3 दशमक के परिवार 52 प्रतिशत शेष बची चीनी के 44 प्रतिशत का उपभोग करते है।
जोड़			**₹ 377,616**	**4.24**	

सभी व्यय दशमक एनएसएस (2011-12) के 68वें चक्र के परिवार व्यय मॉड्यूल से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है।

रेलवे-wwwncer.org.download.php?pld=IIIi`"B107,oa,u,l,l 68वां चक्र

एलपीजी-एनएसएस (2011-12) के 68वें चक्र से खपत

कैरोसिन-इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2014-15 खण्ड ? अध्याय 3

उर्वरक-एग्रीकल्चरल इन पुट सर्वे htt\\inpatsurvey.dacnet.nic.in/nationaltuble 3 aspx

चावल एवं गेहूं-इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2014-15 खण्ड I अध्याय 3

दालें-एनएसएस (2011-12) के 68वें चक्र से खपत

जल-एमआईटी और विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट http:\\webmitt.edu\unbanpgrading\waterandsanitation\resouces\pdt\water tariff4 पृ॰2

चीनी-डिपार्टमेंट ऑफ फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (htt\\dspd.nic.in\\fcamim\sugar\notece.pdf)

उर्वरक इमदाद गरीबी विरोधी नीति के रूप में मूल्य इमदाद के उपयोग द्वारा एक और दिक्कत दर्शाती है। इमदाद का वास्तविक आर्थिक प्रभाव मांग और आपूर्ति की संगत इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है जिसमें पार्टी मूल्य परिवर्तन लाभ के प्रति कम जवाबदेह होती है जबकि इमदाद पर अधिक निर्भर होती है। उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता देने का वास्तविक उद्देश्य किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध करवाना है जिससे कि इनके उपयोग को और उत्तम फसल की पैदावार को प्रोत्साहित किया जा सके। जिन उर्वरकों की किसान मांग करते है वे उर्वरक निर्माताओं की आपूर्ति की उपेक्षा अधिक मूल्य संवेदी होते हैं। मूल्य इमदाद से आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा उर्वरक निर्माताओं द्वारा और अमीर किसानों द्वारा जो उर्वरक के बड़े भाग की खपत करते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है न कि अधिक जरूरतमंदों यथा गरीब किसानों को इसका लाभ मिलता है।

चावल तथा गेहूं के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन फसल विकल्प को विकृत कर देता है जहां जल की उपलब्धता तेजी से गिरी है और वस्तुत: इससे गैर एमएसपी समर्थित फसलों में अत्यधिक मूल्य अस्थिरता आती है जो उपभोक्ताओं को विशेष रूप से उन गरीब परिवारों को आहत करती है जिनकी आय निश्चित नहीं है और जो मौसमी अर्थव्यवस्था के झटके सहने का सामर्थ्य नहीं रखते। उच्च एमएसपी भी उन किसानों के लिए जोखिम उठाने पर नुकसानदायक होती है जो गैर पारंपरिक फसल उगाने का जोखिम उठाते है।

पहली नजर में मिट्टी का तेल (कैरोसिन) मूल्य इमदाद के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि यह विख्यात है कि इसका उपयोग अधिकांशत: गरीब लोगों द्वारा किया जाता है और एनएसएस आंकड़ों के आधार पर अभी इस सर्वेक्षण में किया गया सर्वेक्षण (अध्याय 3) दर्शाता है कि पीडीएस के माध्यम से आबंटित इमदादी कैरोसिन का केवल 59 प्रतिशत वास्तव में परिवारों द्वारा उपयोग किया जाता है शेष बचा रिसाव में नष्ट हो जाता है और कुल खपत के केवल 46 प्रतिशत का गरीब परिवारों द्वारा उपयोग किया जाता है। यहां तक कि पीडीए के द्वारा खाद्य सामग्री के वितरण के मामले में रिसाव की मात्रा बहुत अधिक होती है (लगभग 15 प्रतिशत चावल और 54 प्रतिशत गेहूं इनमें से अधिकांश रिसाव एपीएल सेगमेंट में केंद्रित होता है) यह विख्यात अबवोधन की अपेक्षा आंकड़ों पर गरीबी विरोधी नीति को आधारित करने को महत्व देता है। यह नीति निर्माताओं को इस जरूरत पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है कि वे पहले कदम के रुप में कारगर, लक्षित कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में राज्य को अपने नियंत्रण के लिए संबद्ध करे।

प्रौद्योगिकी गरीब लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार के लिए सरकार को उत्तम साधन प्रदान करती है। जे ए एम ट्रीनिटी जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर-इस परिवर्तन के कारण हो सकते हैं क्योंकि यह कल्याण तथा गरीबी विरोधी नीतियों के सेट का प्रसार करता है जिनका भविष्य में राज्य कार्यान्वियन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकीय अभिनव परिवर्तन ने गरीब लोगों की मदद के लिए सीधे नकद अंतरण के महत्व के लिए शैक्षणिक रुझान को बढ़ाया है।

हाल ही के से प्रायोगिक लक्ष्य प्रकट करते हैं कि बिना शर्त नकद अंतरण-यदि सही लक्ष्य पर किया जाए परिवारों की खपत और परिसंपत्तियों के स्वामित्व को बढ़ा सकता है और अत्यधिक गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा समस्याओं[15] को कम कर सकता है।

नकद अंतरण मनरेगा जैसे विद्यमान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कारगरता को भी संवर्धित कर सकते हैं। हाल के अध्ययन[16] यह साक्ष्य देते हैं कि आन्ध्र प्रदेश, जहां मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा भुगतान आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से किया गया, परिवार इस नए आधार लिंक डीबीटी सिस्टम के माध्यम से तेजी से भुगतान प्राप्त करते हैं और राशि वितरण में लीकेज कम हुई जिससे कि वित्तीय वचत लीकेज की कमी के कारण कार्यक्रमों को कर्यान्वित करने की लागत से 8 गुणा अधिक थी। इस लीकेज में कमी बायोमीट्रिक आइडेंटीफिकेशन स्टेम के परिणाम स्वरूप घोस्ट लाभ प्राप्तकर्ताओं का पता लगने से भी आई। वास्तव में सरकार 9.75 करोड़ लाभर्थियों के बैंक खातो में कुकिंग गैस इममाद का सीधे भुगतान कर सीधे लाभ अंतरण से लाभ प्राप्त कर रही है।

कृषि क्षेत्र के लिए, जो फिलहाल संकटग्रस्त है, ये साक्ष्य संभावनाएं उजागर करती हैं। मेनरेगा के परिणाम स्वरूप, इसकी सभी कमियो सहित यह स्वंय लक्ष्य पर पहुचती है। यदि यह कार्यक्रम ग्रामीण सड़कें, माइक्रो इरेगेशन (सूक्ष्म

---

[15] एक अनुमान से पता चला है कि किसानों की उर्वरकों की मांग में उर्वरकों में लगभग 6.4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि के कारण घट गई है। ढोलकिया, आरएस तथा जगदीप मजूमदार ''ऐस्टीमेशन आफ प्राइस इलास्टिसीटी ऑफ फर्टीलाइजर डीमांड इन इंडिया'', 2006 आधार पत्र

[15] जाहेन्स हैसोफर एवं जेर्मी शैपीरो ''हाउस होल्ड रिसवॉन्स टू इनकम चेंजेज' ऐवीडेंस फ्राम अन कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम इन केन्या, 2013 कार्यपत्र.

[16] कार्तिक मुरलीधरन, पॉल निहास एवं संदीप सुखंताकर, बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी 27: एवीडेंस फाम बायोमीट्रिक स्मार्टकार्ड इन इंडिया, 2014-कार्य पत्र,

सिंचाई) और जल प्रबंधन इंफ्रास्ट्रचर जैसी ग्रामीण परिसंपत्तियों को सृजित करने को दिशा में कम कर सके और जेएएम नंबर ट्रीनिटी के माध्यम से लीकेज न्यूनतम की जा सके तो ग्रामीण भारत वंचितों के लिए अवसरों का सृजन तथा सुरक्षा दोनों को प्राप्त कर सकेगा।

आज लगभग 125.5 मिलियन जनधन बैंक खाते है,[17]। 757 मिलियन आधार नंबर हैं और लगभग 904 मिलियन मोबाइल फोन हैं। इस बात पर जोर देना संभव है कि जब जेएएम ट्रीनिटी लिंक हो जाएगी तो आधार नंबर के माध्यम से पहचान के उपरांत बैंक खाते में आवधिक तथा निर्बाध वित्तीय अंतरण के लक्ष्य को गरीब लोगों की आजीविका में मदद के अनुलनीय लाभ के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की शीर्षस्थ प्रत्याशा यह है कि राज्यों में प्रबल निवेश करने पर निर्वाण (Nirvana) पहुंच में नजर आएगा। इस निर्वाण के दो कारण होंगे- एक तो गरीबों की रक्षा हो सकेगी और भारत में कई चीजों की कीमतों में उदारीकरण आने से संसाधन आवंटित करने की भूमिका को संपादित किया जा सकेगा और दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी। चूंकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बाजारगत सुधारों पर ध्यान दिया गया है, इसलिए भारत पहली पीढ़ी के बुनियादी सुधारों को पूरा करने में सक्षम होगा। यह भारतीय सुधारों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कदम होगा।

1.8 वृद्धि निजी और सार्वजनिक निवेश

''बैलेंशीट सिंड्रॉम विद इंडियन करेंक्टरिस्टिक्स'' ने ऐसी कठिन चुनौतियों के लिए वेब बनाया है जो निजी निवेश को रोक सकता हो। निजी निवेश को दीर्घ गामी विकास का प्रारंभिक इंजिन रहना चाहिए। किंतु अंतरिम तौर पर वृद्धि को पुनःजीवित करने के लिए तथा प्रत्यक्ष कनेक्टीविटी को गहनता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निवेश को विशेष रूप से रेलवे में, महत्वपूर्ण भूमिका निभनी होगी। चूंकि अब नई सरकार सत्ता में आ गई है। आर्थिक सुधारों की दिशा परिवर्तन से निवेशकों की भावनाओं का आंशिक पुनरूस्थान हुआ है।

प्रारंभिक संकेत मिलते हैं कि बुरा समय समाप्त हुआ। उदाहरण के लिए आंकड़े जो दर्शाते हैं कि अवरूद्ध (स्टाल्ड) परियोजनाओं की दर में कमी आई हैं और इनके पुनरूस्थान की दर में वृद्धि हो रही है (चित्र 1.14) चित्र 1.14 स्टाल्ड परियोजनाओं का ओवरव्यू, 2011 क्यू 1 से 2014 क्यू. 3 (लाख करोड़)

किंतु बढ़ते पूंजीगत प्रवाह, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, को अभी स्थायी गति प्रदान कियाजाना बाकी है। यह कम से कम ऐसे पांच परस्पर संबद्ध घटकों पर आश्रित होता है जो वर्ष के मध्य में आर्थिक विश्लेषण के कारक होते है जिसे *''बैलेंस शीट सिंड्रोम विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक'' कहा जाता है।*

सबसे पहले कम लाभप्रदता से लड़खड़ाता और अति ऋणग्रस्तता से दबा भारतीय निगमित क्षेत्र (चुनौतियां को वहन करने) निवेश करने में बहुत सीमित है। लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण संकेतक-व्याज कवर अनुपात-यदि एक से कम हो तो इसका अर्थ होता है कि फर्म की नकद प्राप्ति अपनी ब्याज लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति हाल हो के वर्षों में कम हुई है। (चित्र 1.15) इसके अलावा जैसा कि चित्र 1.16 दर्शाता है कि 500 बड़ी गैर-वित्तीय फर्मों का ऋण-ईक्विटी अनुपात निरंतर बढ़ रहा है और अब उनका स्तर उभरते विश्व बाजार मे उच्चतम है। चित्र 1.15 भारतीय निगमित क्षेत्र की स्थिति आईसीआर <21,,2011 क्यू 3 से 2014 क्यू 2 -कंपनियां।

दूसरे कमजोर संस्थान जो दिवालिए हो चुके हों का तात्पर्य होता है कि अति ऋण ग्रस्तता की समस्या आसानी से समाप्त नहीं हो सकती (स्टॉक और निर्गम की समस्या (डिफकल्टी ऑफ एग्जिट) चुनौती यह स्टाल्ड परियोजनाओं की विद्यमानता में परिलक्षित होता है। जो निरंतर पिछले चार वर्षों के दौरान जीडीपी का लगभग 8 प्रतिशत रहा है। ऋण वसूली अधि करण के पास बहुत अधिक काम है और इनके संसाधान कम हैं,वर्तमान विधानों (कानून) को प्रबल बनाने की आवश्यकता है।

तीसरे, भले ही इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान हो गया, कम से कम अभिसंरचना में पीपीपी मॉडल को प्रगति के लिए अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए पुन: व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी।

चौथा अभिसंचना का महत्वपूर्ण भाग को बैंकिंग सिस्टम द्वारा वित्त प्रदान किया जाना है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, इसकी बैलेंश शीट में गिरावट[19] आई है। उदाहरण के लिए अनर्जक और स्ट्रेस मुक्त परिसंपत्तियों की संख्या तीव्रता से बढ़ी है और पीएसबी के लिए कुल परिसम्पतियों के 12 प्रतिशत से अधिक है चित्र 1.17)

---

[17] प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रोग्रेस रिपोर्ट

[18] http://www.trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Presspercent20Release-TSD-Mar,14.pdf.

[19] आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2014 के अनुसार, खनन, लोह, और स्टील, टेक्सटाइल, एविएशन और अन्य अभिसंरचनाओं का कुल अग्रिम मे अंशदान 28 प्रतिशत है जबकि इनका स्ट्रेसयुक्त परिसंपत्तियों में अंशदान 54 प्रतिशत है।

चित्र 1.14: रुकी परियोजनाओं का विहंगावलोकन, 2011 ति. 1 से 2014 ति. 3 (लाख करोड़)

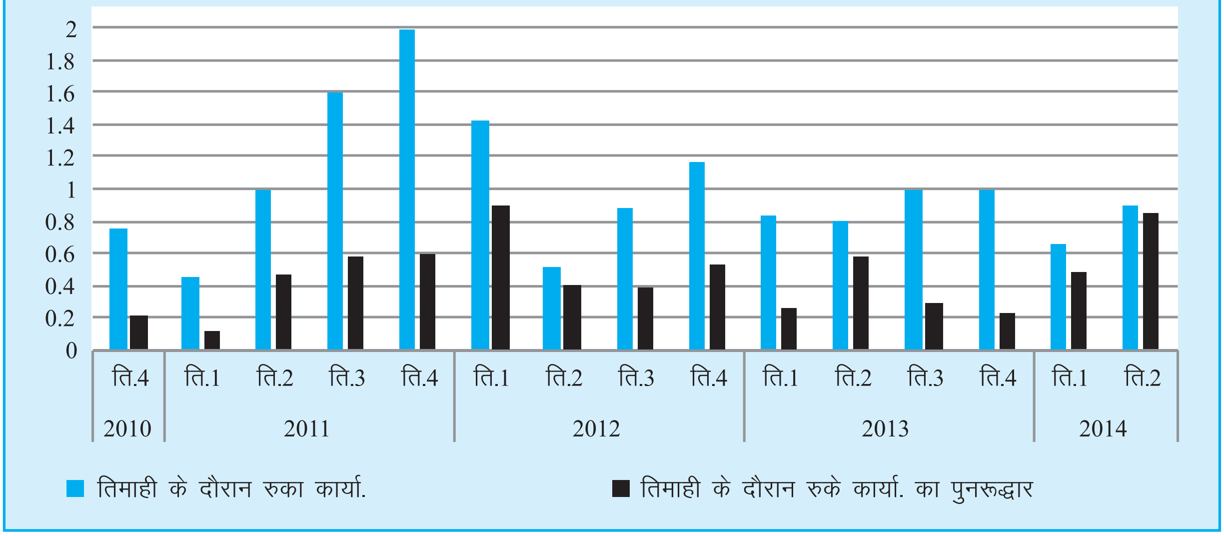

स्रोत : **सीएमआईई**

लेखा और मूल्यांकन के संबंध में अनिश्चतता और विभिन्न समयों और स्थलों पर बैंकिंग समस्याओं का इतिकृत समस्याओं की गंभीरता को कम आंकने की अपेक्षा अधिक आंकड़े का परामर्श देता है। जब बैंक की बैंलेंस शीट पर बल दिया जाता है तो ये ऋण देने के योग्य नहीं होते जिससे निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट कम रहता है। (वित्तीय चुनौतियां)[20]

अतंत: विशिष्ट भारतीय परिवेश में यह वित्तीय समस्या सामान्य जोखिम विरूचि के कारण बढ़ी है निर्णय लेने की चुनौती विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जिनके संबंध में सरकारी जवाबदेहिता होती है और इससे बचा जाता है, एनपीए की स्थिति में ऋण आसान नहीं होता क्योंकि सावधानी वरतने की सामान्य समस्या ब्यूरोक्रेटिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है।

कोयला और गैस जैसे महत्वपूर्ण इनपुट साथ ही साथ नियामक सुधारों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की गई, इससे कुछ दबाव कम हुआ है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में जहां आंकड़ों की नियामक के रूप में पहचान की जाती है। (कलेयरेंस और भू-अधिग्रहण)। संस्थागत समस्याओं को दूर करने के लिए पीपीपी के लिए बेहतर फ्रेमवर्क तैयार कर तथा समान्य रूप से बुनियादी निवेश के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की वसूल न हो पाने वाले ऋणों को समस्या की पहचान और इनका समाधान करने के प्रयास कर रहा है। किंतु इस पहल का प्रभाव सीमित है। रूकी पड़ी परियोजनाओं का स्टॉक बहुत अधिक है, फर्म की लाभप्रदता, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्य कर रही फर्म बहुत कम होती है। इस लिए निजी क्षेत्र में निवेश की वसूली की गति और क्षमता (स्ट्रेन्थ) कम रहती हैं।

यदि निजी निवेश की कमी बढ़ी हुए सार्वजनिक निवेश के लिए एक नकारात्मक या प्रत्यक्ष मूल आधार प्रस्तुत करती है तो इसके बहुत से सकारात्मक मूलाधार भी होते हैं। भारत के हाल के पीपीपी अनुभव से पता चला है कि एक कमजोर संस्थान में यदि कोई निजी क्षेत्र इस परियोजना को अपने हाथ में लेता है तो इसके कार्यान्वयन में लागत का जोखिम रहता है (भू-अधिग्रहण में, पर्यावरणीय स्वीकृति और इनपुट आपूर्ति की परिवर्तनशीलता आदि में विलंब) कुछ क्षेत्रों मे इन जोखिमो को आत्मसात करने में सार्वजनिक क्षेत्र उत्तम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंफास्ट्राक्चर (अभिसंरचना) के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण सड़कें, रेलवे जो मूल भूत प्रत्यक्ष कनेक्टीविटी (संपर्क) उपलब्ध करवाते हैं जिनमें निजी निवेश कम होगा। एक विडंबना यह है कि जहां वित्तीय और डिजिटल कनेक्टीविटी आगे बढ़ रही है वहीं यह देखा जाता है कि मूलभूत प्रत्यक्ष कनेक्टीविटी पिछड़ रही होती है।

इसलिए जैसे कि मिड-ईयर इकॉनॉमिक एनालायसिस 2014-15 (मध्य वर्षीय आर्थिक विश्लेषण 2014-15) में जोर दिया गया है कि लक्षित सार्वजनिक निवेश को विकास के प्रेरक घटक के रूप में संस्थापित करना अल्प अवधि के लिए

[20] इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण में किस प्रकार पूंजी बाजार बड़ी भूमिका निभा सकता है, पर सुझाव पिछले वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं।

चित्र 1.15: भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर की स्थिति आईसीआर के साथ कंपनियां <1,2011 ति.3 से 2014 ति.2

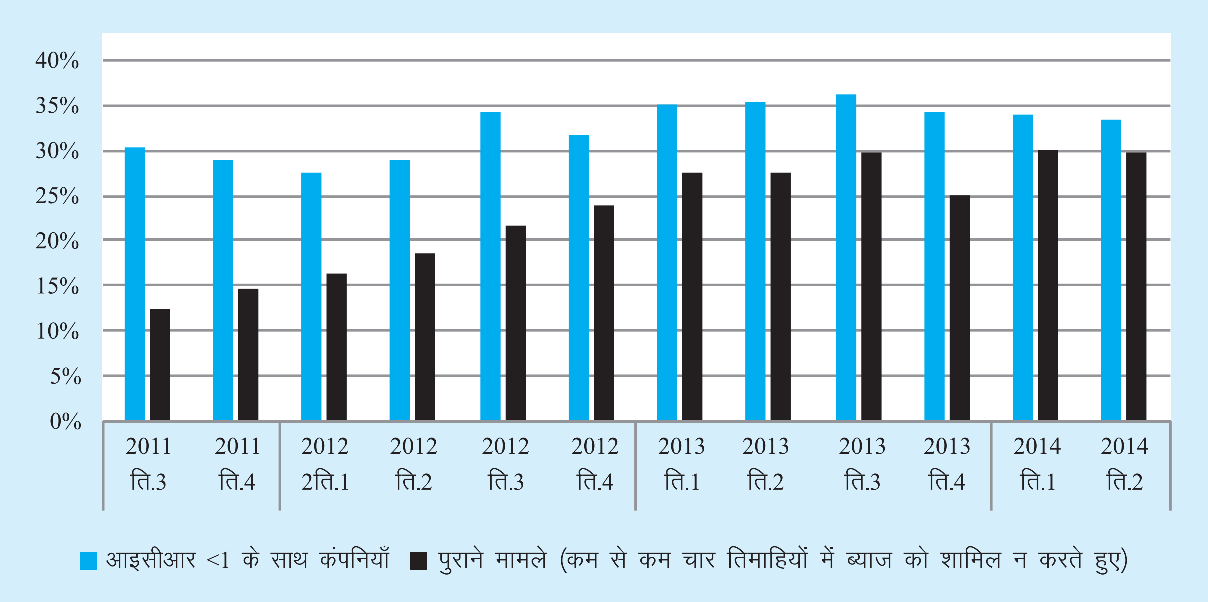

चित्र 1.16: गैर-वित्त कॉरपोरेट की इक्विटी के लिए ऋण

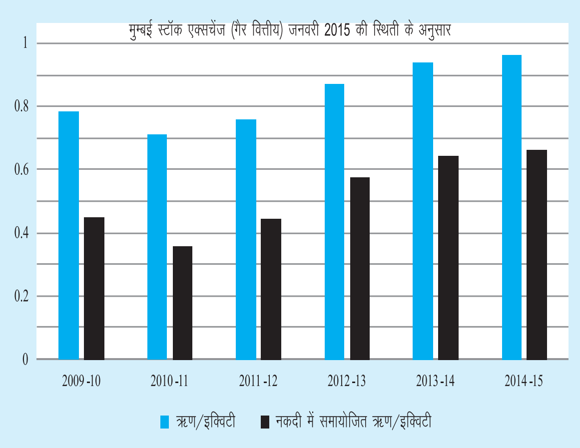

चित्र 1.16: गैर-वित्त कॉरपोरेट की इक्विटी के लिए ऋण

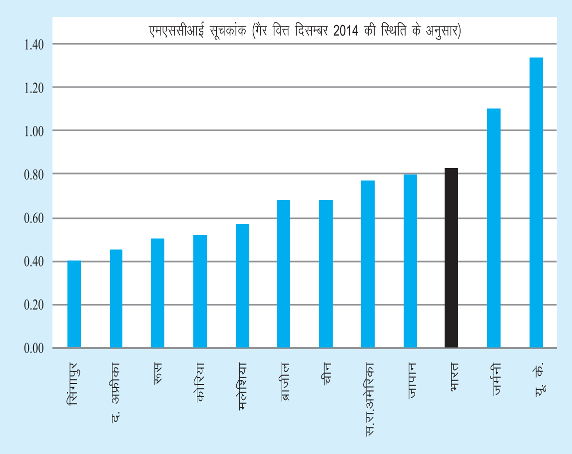

स्रोत : **ब्लूमबर्ग और जे पी मोरगन**

सकारात्मक लगता है किंतु यह निजी निवेश का प्रतिस्थापन नहीं होगा और इस प्रकार इसे प्रोत्साहित करना और बढ़ाना है। सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की दो चुनौतियां वित्तपोषण और क्षमता से संबद्ध हैं। वित्तपोषण संबंधी समस्याओं पर खंड 1. 6 में चर्चा की गई है।

भारत में निजी क्षेत्र की कार्यान्वयन क्षमता परिवर्तनीय है। किंतु अध्याय 6 में दिया गया विश्लेषण बताता है कि रेलवे वृद्धि का अगला साधन हो सकता है। रेलवे में अधिक सार्वजनिक निवेश सकल वृद्धि को बढ़ाएगी और भारतीय निर्माण क्षमता में पर्याप्त प्रतियोगिता लाएगी। अंशत: ये बड़े लाभ रेलवे में चालू भारी कम निवेश से मिलते हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत में 1990 के मध्य तक एक समान नेटवर्क क्षमता थी किंतु चीन ने प्रतिव्यक्ति के रूप में भारत की तुलना में ग्यारह गुणा अधिक निवेश किया। अत: चीन की क्षमता और सामर्थ्य में बढोत्तरी हुई (चित्र 1.18) इसके विपरीत अवरूद्ध निवेश की वजह से भारत मे संकुलन (कन्जेशन) क्षमता में कमी, खराब सेवा, कमजोर वित्तीय स्थिति और संभारतंत्र आधारित क्षेत्रों की प्रतियोगी क्षमता, विशिष्ट निर्माण क्षमता में गिरावट आई है। रेलवे में अधिक माल ढुलाई आने से सड़क परिवहन को भी लाभ हुआ है जो कि विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि रेल परिवहन अधिक सस्ता और ऊर्जा किफायती है। मालभाड़े से प्राप्त आय से यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं और भारतीय रेल भाड़ा सबसे अधिक है (पीपीपी समायोजित)।

चित्र 1.17: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिति, मार्च 2010 से सितम्बर 2014 तक

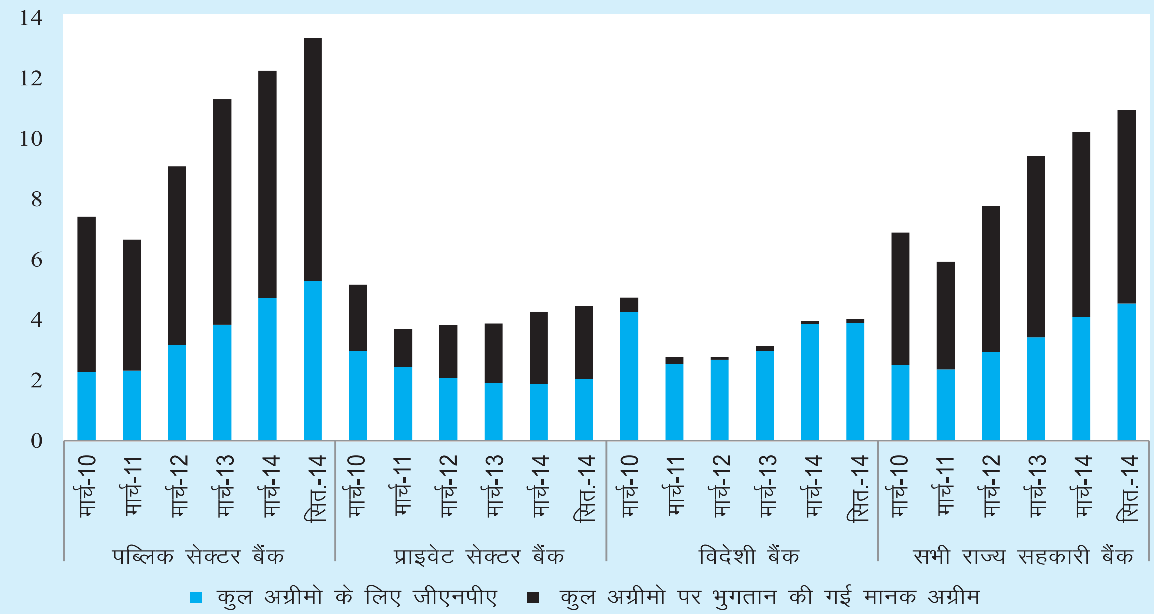

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 1.18: अतिरिक्त क्षमता - भारतीय और चीनी रेलवे, 1990-2010 (मार्ग हजार कि.मी.)

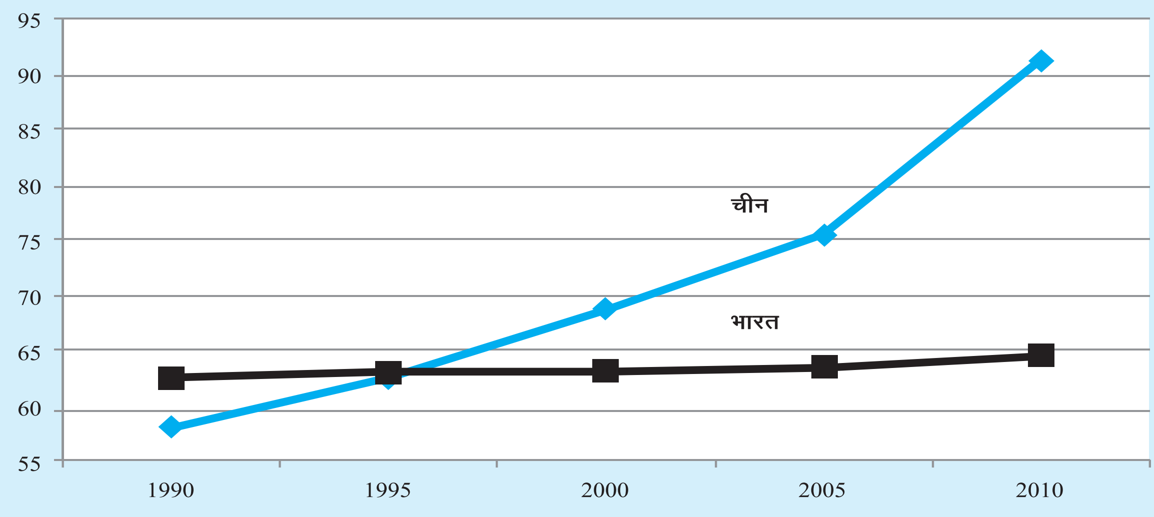

स्रोत : विश्व बैंक

पूर्व एनडीए सरकार ने सड़कों के लिए जो कुछ भी किया। वही वर्तमान सरकार रेलवे के लिए कर सकती है, जीवन यापन के उच्च मानकों, अधिकाधिक अवसर प्रदान करने और मानव जीवन के उत्थान के महत्व को बढ़ाने के रूप में अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के साथ ही साथ भारत की जनसंख्या को प्रत्यक्ष कनेक्टीविटी प्रदान कर मजबूती प्रदान कर सकती है।

1.9 बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां

बैंकिंग व्यवस्था नीतियों के अनुसार संचालित है जो दोहरे वित्तीय निरोध (रिपरेशन) उत्पन्न करती है और संरचनात्मक घटक द्वारा जो प्रतियोगिता में बाधा डालते हैं। इसका समाधान विनियमन के 4-डी में विद्यमान है। सांविधिक नकदी अनुपात (एसएसआर) और प्राथमिकता

क्षेत्रों के ऋण (पीएसएल), विभेदीकरण (पुन: पूंजीकरण, बैलेसशीट में घाटा और स्वामित्व के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र व बैंकों में विविधता (बैंकिंग और बैकिंग के बाहर निधि का स्त्रोत) और डिसइंटरिंग (एक्जिट मकैनिज्म में सुधार के द्वारा)।

भारत में बैंकिंग पर हाल ही में हो रही चर्चा कम तथा पुन: अभिसंरचित परिसंपत्तियों, की समस्याओं पर, पूंजीगत पर्याप्तता पर अस्पष्ट लूमिंग बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने के संसाधनों को प्राप्त करने की चुनौतियों, सरकार और बाजार के संबंधित सहयोग को शामिल करने और 2013 की नायक, समिति रिपोर्ट में दर्शाई गई शासन सुधार की आवश्यकताओं पर आधारित है। इन आसन्न मुद्दों से पीछे हटने से भारतीय बैंकिंग की समस्याओं का गहन विश्लेषणात्मक निदान करना होता है जो तद्नुसार अत्यंत अंशांकित समाधानों का आधार प्रदान करता है।

पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत क्रेडिट एडल्ड और ओवर बैंक्ड तो नहीं है। इसका मूल्यांकन करने का एक तरीका यह देखना है कि क्या भारतीय बैंक तेजी के दौर में अत्यधिक लापरवाह थे।[21] चित्र 1.19 अनेक देशों का जीडीपी या घरेलू क्रेडिट दर्शाता है कि विश्व बैंक द्वारा 'टेक ऑफ' वर्ष से इन देशों की तेजी से हुए विकास की अवधि में दर्शाया गया है। (ये अवधि अलग-अलग देशाों के संबंध में अलग-अलग है) यह दर्शाता है कि पिछले दशक में यह उछाल क्रेडिट में वृद्धि के कारण हुआ था जिसके मूल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के यह असंगतिपूर्ण ऐसी व्यवहार अन्य देशों में भी हमसे भिन्न नहीं था। अन्यों की अपेक्षा भारतीय क्रेडिट अधिक तीव्रता से नहीं बढ़ा उदाहरण के लिए जापान और चीन ने अपने वित्तीय सिस्टम में अपने समायोजन वर्ष के दौरान अधिक ऋण दिया है।

भारत के ओवर बैंक होने के प्रश्न के संबंध में हमने देशों के समूह के लिए कुल क्रेडिट में बैंकों के हिस्से का मूल्यांकन किया है (चित्र 1.20) ये आंकड़े सरकार को छोड़ कर, अर्थव्यवस्था में कुल क्रेडिट जिसमें विकास के स्तर के लिए फर्म और हाउसहोल्ड[22] शामिल हैं, का बैंकिंग क्रेडिट की तुलना में अनुपात दर्शाता है जैसाकि पीपीपी के रूप में प्रति व्यक्ति जीडीपी के लॉग द्वारा मापा गया है। यह चार्ट दर्शाता है कि भारत बहिर्वासी नहीं है, यह इसके विकास के स्तर से संबद्ध है, बैंक क्रेडिट का स्तर सामान्य तौर पर न तो बहुत

चित्र 1.19: टेक ऑफ के बाद से स.घ.उ. में घरेलू ऋण (प्रतिशत)

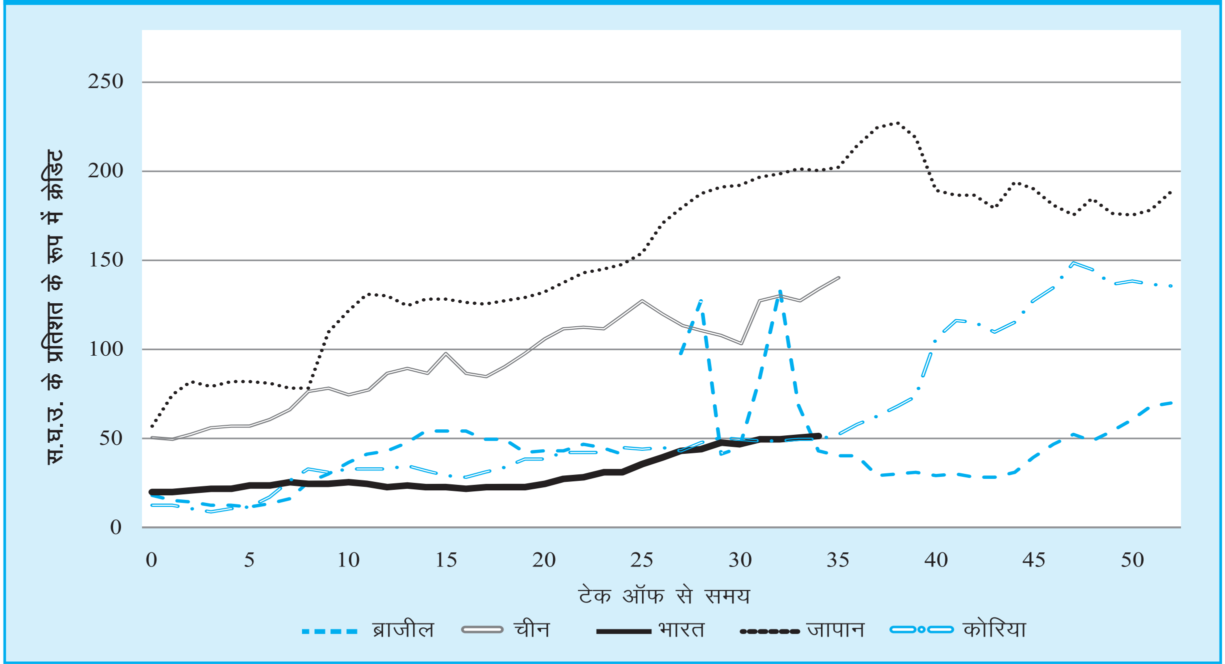

स्रोत: बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटलमेंट यह समस्या कहां विद्यमान है। भारतीय बैंकिंग क्रेडिट

[21] इस खंड के अध्याय 5 में हम यह परीक्षण भी करते हैं कि कैसे ऋण की भारमार वाले वाला भारत अन्य विभिन्न खण्डों और समय श्रृंखलाओं की तुलना पर आधारित है।

[22] अंतराष्ट्रीय समझौता बैंक द्वारा यथापरिभाषित, इसमें गैर वित्तीय निगमों (निजी और सरकारी दोनों), परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाली निर्लाभ संस्थाओं को दिया गया ऋण शामिल है जैसकि राष्ट्रीय लेखा व्यवस्था 2008 में पारिभाषित है।

अधिक है और न ही बहुत कम है। वास्तव में यदि भारत अगले 20 वर्षों में 8% की वृद्धि करता है तो बैंकिंग से परे भारत का वित्तीय क्षेत्र के संघटन में तीव्र परिवर्तन आवश्यक और वांच्छनीय हो जाएगा।

यह समस्या कहां विद्यमान है भारतीय बैंकिंग सिस्टम में समस्या अन्यत्र है और यह दो श्रेणियों में आती है नीति और संरचना नीति संबंधी चुनौती का संबंध वित्तीय निग्रह से है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम 'दोहरे वित्तीय निग्रह' से ग्रस्त है। बैलेंस शीट की परिसंपत्तियों की ओर वित्तीय निग्रह संविधि क नकदी अनुपात द्वारा किया जाता है जो बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां धारित करने के लिए विवश करता है तथा प्राथमिकतता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) जो पूर्ण सक्षम तरीकों से कम में संसाधन विकास के लिए मजबूर करता है। देयता की ओर वित्तीय निग्रह 2007 से उच्च मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से नकारात्मक वास्तविक ब्याज दर आई और परिवारों (हाउस होल्ड) की बचत में तीव्र गिरावट हुई। चूंकि भारत देयता की ओर के निग्रह की ओर से मुद्रा स्फिति में गिरावट के कारण हट रहा है ऐसे में यह इसके परिसंपत्ति की ओर के भाग का समाधान करने का यह सही समय हो सकता है।

प्रतियोगिता और स्वामित्व संबंधी संरचनात्मक समस्याएं। सर्व प्रथम प्रतियोगिता की कमी नजर आती है यह निजी क्षेत्र के बैंकों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में अयोग्यता वस्तुत: हल ही के बैंकिंग इतिहास का एक विरोधाभास यह है कि जब देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है तो ऐसे में निजी क्षेत्र के बैंक की भागेदारी सकल बैंकिंग में न के बराबर बढ़ी है और जोकि निजी क्षेत्र के द्वारा बढ़नी चाहिए थी। यह निजी क्षेत्र के बैंक के वित्त पोषण के बिना निजी क्षेत्र का असामान्य मामला है। यहां तक कि पीएसबी के इस दिशा में आधिक्य की अनुमति देने पर कि वह इस वृद्धि के मार्ग में वित्तपोषण कर सके निजी क्षेत्र का इस दिशा में मौन चौकाने वाला है।

दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के कार्यनिष्पादन में विवेकशीलता और लाभप्रदता के संदर्भ में व्यापक अंतर पाया गया है। चित्र-1.22 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों के लिवरेज अनुपात और प्रतिलाभ को दर्शाता

चित्र 1.20: वर्ष 2014 के लिए कुल ऋण के अंश के रूप बैंकिंग ऋण

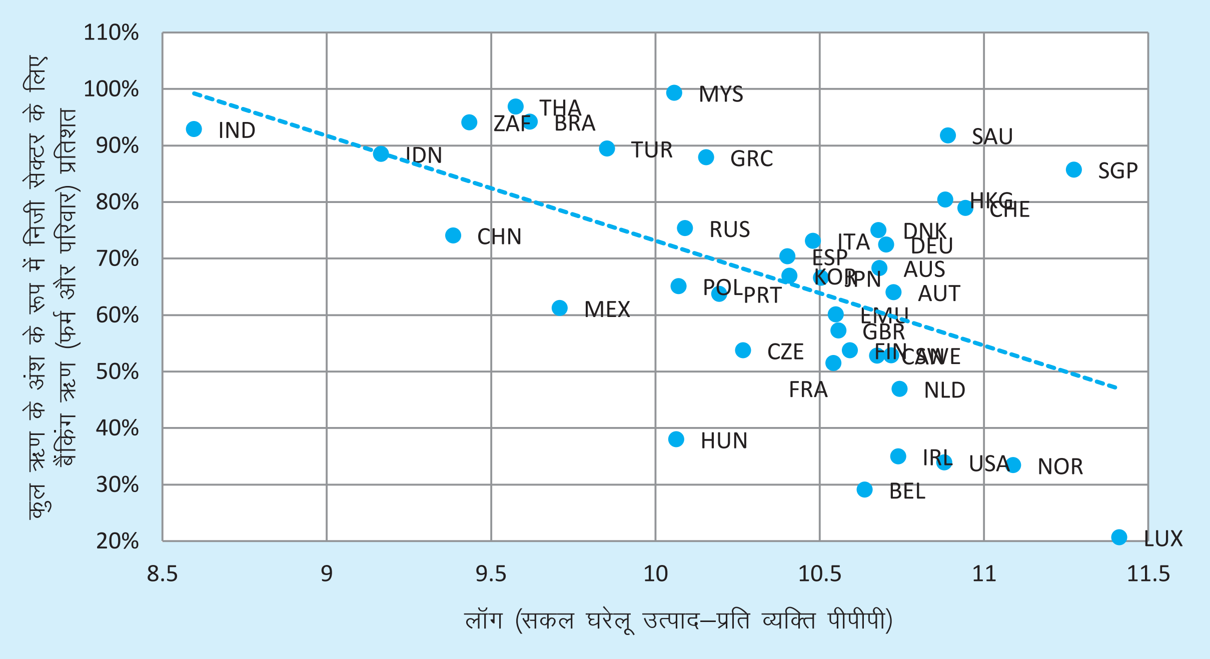

स्रोत: बैंक ऑफ इंटरनेशनल सैटलमेंट

[22] इस खण्ड के अध्याय 5 में और ब्यौरे देखे जा सकते हैं।

चित्र 1.21: कुल अग्रीमो का अनुपात, (वर्ष 1995-2014)

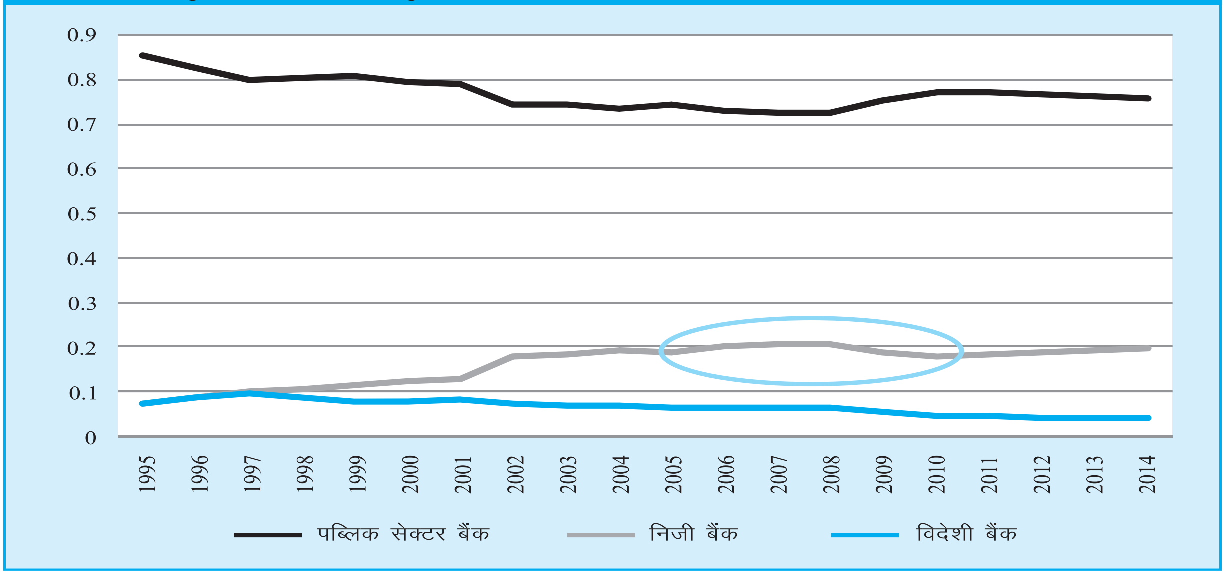

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

है[24] इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लिवरेज अनुपात के अंतर के दर्शाता है (जैसा कि बिंदुकित रेखाओं से दर्शाया गया हैं)। वास्तविक लिवरेज अनुपात की वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में तीन वर्षों के औसत को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत अदूरदर्शिता की तुलना में सर्वाधिक पूंजीगत दूरदर्शिता (पी॰एस॰वी॰) 1.7 गुणा थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद यह उल्लेखनीय है कि इन उपायों के आधार पर सर्वेत्तम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन निजी क्षेत्र के बैंकों से औसतन काफी कम है जो वास्तव में इस मान्यता पर आधारित है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामजिक दायित्व अधिक होते हैं जिसके कारण उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हानि उठानी पड़ती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक समस्या यह भी है कि उन्हें ऋण कठिनाइयों से उभरना काफी कठिन हो रहा है। यदि ऐसा है तो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्याशित स्वामित्व के संबंध में यह चिंता का अतिरिक्त कारण है।

उपरोक्त विश्लेषण और अध्याय 5 में दिए गए अनुसार चार स्तरीय नीति 4 डीएस (डी॰) पर आधारित है अर्थात डिरेग्यूलेट, डिफरेन्सीएट, डाइवर्सिफाइ और डिसएंटर।

चूंकि बैंकिंग सेक्टर में देयता पक्ष में मुद्रास्फीति में कमी सहित वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है इसलिए आस्तिपक्ष में नियंत्रण (रेपरेशॅन) को कम करने का यह उचित अवसर है। इससे बैंकों में नकदी बढेगी, सरकारी बांड बाजार को व्यापकता मिलेगी तथा कारपोरेट बांड बाजार में भी परिवर्द्धन होगा। पी॰एस॰एल॰ मानकों का फिर से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके दो विकल्प है जिसमें पहला विकल्प यह है कि अप्रत्यक्ष सुधारों द्वारा अधिक से अधिक सेक्टरों को पी॰एस॰एल॰ के दायरे में लाया जाए जब तक कि प्रत्येक सेक्टर प्राथमिकता के सेक्टर में न आ जाए, और दूसरा विकल्प है पी॰एस॰एल॰ को धीरे-धीरे अधिक लक्षित, छोटा और आवश्यकता आधारित बनाने के लिए मानकों को फिर से निर्धारित किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी॰एस॰बी॰) में अवश्य दी भेद किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा अपनाई गई पुनः पूंजीकरण की मौजूदा संकल्पना इस दिशा में एक सही कदम है। एक ही धारणा शासन सुधार जैसी संकल्पनों पर सर्वाधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। विभेदीकरण विकल्पों का अवसर प्रदान करता है जैसे चयनात्मक पुनः पूंजीकरण, सरकारी स्वामित्व को कम करना तथा निर्गम।

---

[24] आर॰बी॰आई॰ द्वारा लिवरेज अनुपात को कुल पूंजी की कुल आस्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेंटीमेंट द्वारा यथा परिभाषित परिभाषा एकदम इसके प्रतिक्रम में है। इस प्रयोजन के लिए इस खंड को हम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के लिए उपयोग में लाएगे। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आर॰ओ॰ए॰) लाभ प्रदता अनुपात है जो कुल आस्तियों से प्राप्त निवल लाभ (निवल आय) को दर्शाती है।

चित्र 1.22: बैंकिंग संकेतकः उत्तोलन अनुपात और आस्तियों पर अर्थागम 2001-2014

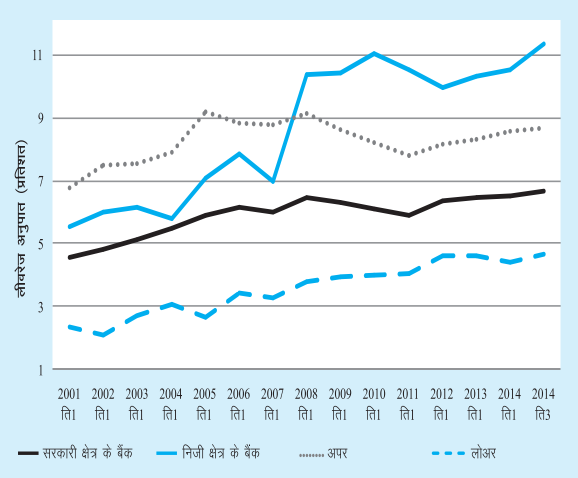

बैंकिंग संकेतकः उत्तोलन अनुपात और आस्तियों पर अर्थागम 2001-2014

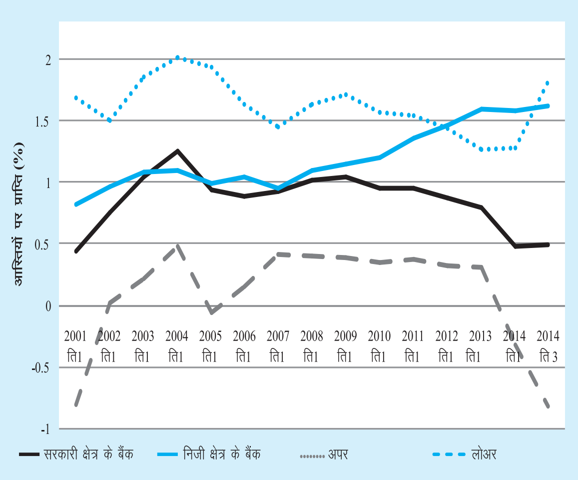

स्रोत : **भारतीय रिजर्व बैंक।**

विविधता का आशय यह है कि बैंकिंग प्रणाली में व्यापक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसमें बैंकों और विविध प्रकार के बैंकों के लिए उदार लाइसेंसिंग प्रणाली भी शामिल है। पूंजीगत क्षेत्र में विशेष रूप से बांड मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ऐसा करने से आस्ति पक्ष में निरोध (रिप्रेशन) अर्थात एसएलआर की गति को धीमा करना और बांड मार्केट को बढ़ावा देने की जरूरत होगी।

डिसएंटर (पड़ताल करने) का अर्थ होता है कि विकास प्रक्रिया अत्यंत कारगर होनी चाहिए ऋण वसूली अधिकरणों के पास अधिक कार्य है और इनके पास संसाधन कम हैं जिसकी वजह से निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। स्वामित्व संरचना और आस्ति पुनर्निमाण कंपनियां, जिनमें बैंकों की स्वयं की भी काफी भागेदारी है, बेमेल पहल करती है। द स्क्रूटनाइजेशन एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सीक्योरिटी इंटरेस्ट (एसएएफएईएसआई) एक्ट सबसे छोटे उधारकर्ताओं और एमएसई के विरुद्ध अत्यधिक कठोरता से कार्यान्वित किया जाता है। बैंकों के द्वारा असावधानी पूर्वक ऋण देने के लिए नीति संगत बाधा रहित प्रोत्साहन के बिना प्रोमोटरों, क्रेडिटटरों, उपभोक्ताओं और कर दाताओं को ऋण देने की कारगर प्रक्रिया आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि ऋणों को समाप्त करना, इनमें होने वाली वृद्धि के जितना ही महत्वपूर्ण है।

1.10 मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्माण, सेवाएं और इसकी चुनौर्तियां

ट्रांसफार्मेशनल (रूपांतरणकारी) क्षेत्र पंजीकृत निर्माण या सेवाओं का क्षेत्र हो सकता है। अर्थव्यवस्था विस्तृत कौशल को बढ़ाना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि अधिक निर्माण के लिए परिस्थितियों में सुधार करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय निर्माण को पुन जीवित करने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है जैसा कि उनके मेक इन इंडिया अभियान और स्लोगन में दिया गया है। इसका उद्देश्य उतना ही मुखर है जितना कि इसके मार्ग में चुनौतियां है ये चुनौतियां अत्यंत विषम हैं क्योंकि भारतीय निर्माण निचले स्तर पर ही थमा हुआ है विशेष रूप से पूर्वी एशिया की सफलता की तुलना में।[25]

यहां दो प्रश्न उठते हैं। क्या निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मेक इन इंडिया में ध्यान दिया जाना चाहिए? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए। एक-एक कर इन पर विचार करें।

नया शैक्षणिक कार्य यह बताता है कि विकास में और इसके लिए ट्रांसफार्मेशनल क्षेत्र के संबंध में विचार का एक अनुपूरक मार्ग है। वृद्धि का सिद्धांत इस ओर इंगित करता है कि रूपांतरणकारी क्षेत्रों का मूल्यांकन इनकी निहित विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए और न कि पारंपरिक

---

25 जीडीपी में निर्माण के स्तर के लिए हाल ही के अपवर्ड संशोधन वास्तविक होने के स्थान पर कुछ हद तक सांख्यिकीय हैं। इसके अतिरिक्त इसके भाग में कमी के रुझान की पैटर्न को संशोधित आंकड़ें नहीं बदलते तथा सांख्यिकीय विरोध, जगदीश भगवती (स्पिलटिंग एण्ड डिसएंवोडिमेंट अफ़ सर्विसेज एण्ड डेवलपिंग नेशन्स 1984; द वर्ड इकॉनॉमी 7(2) का तात्पर्य माल से स्पिलटिंग सेवाएं हैं।

निर्माण सेवा के रूप में। (सारणी 1.3) इस प्रकार की पांच विशेषताओं की पहचान निम्नानुसार की गई है:-

- उत्पादकता का उच्च स्तर जिससे आय बढ़ सके।
- विश्व फ्रंटियर (अंतरराष्ट्रीय अभिबिन्दुता) के संबंध में उत्पादकता वृद्धि की तीव्र बढ़ती दर और साथ ही साथ राष्ट्रीय फ्रंटियर (घरेलू अभिबिंदुता) की तीव्र वृद्धि।
- संसाधनों को प्राप्त करने के लिए गतिशील क्षेत्र का प्रबल योग्यता जिसके माध्यम से शेष अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभ का प्रसार हो।
- देश में विद्यमान संसाधनों, जो कि विशेषरूप से गैर कौशल प्राप्त श्रमिकों से संबद्ध हों, की मदद से गतिशील की ओर झुकाव।

इस क्षेत्र की व्यापारिक क्षमता इस बात को निर्दिष्ट करती है कि क्या यह क्षेत्र मांग के दबाव को पूरा किए बिना विकसित हो सकता है यह एक ऐसा विषय है जो कि भारत जैसे बड़े देश के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के संदर्भ में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि ट्रांस्फार्मेशनल (रूपांतरणकारी) क्षेत्र के रूप में निर्माण के विषय में विचार किया जाता है तो यह पंजीकृत या औपचारिक निर्माण होता है जिसमें उच्च उत्पादकता तथा उत्पादकता में तीव्र वृद्धि जैसी पूर्वापेक्षाएं होती हैं। अत: इसे औपचारिक रूप देने का प्रयास महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय साक्ष्य यह है कि टेलीकम्यूनिकेशन तथा वित्त जैसे सेवा के कुछ उप क्षेत्र अत्यधिक उत्पादक और गतिशील होने के कारण पंजीकृत निर्माता होते हैं। तथापि, ये क्षेत्र गैर कुशल श्रमिकों की अधिक संख्या को आकर्षित करने में सफल नहीं हुए हैं जिससे इसकी गतिशीलता के लाभ सीमित हुए हैं। दूसरे शब्दों में गतिशील क्षेत्रों को कौशल सम्पन्न क्षेत्र होना चाहिए जिस में भारत को कोई तुलनात्मक लाभ नहीं है। भवन निर्माण (कंस्ट्रक्शन) इसका अपवाद है जो कि गैर कुशल मजदूर बाहुल्य और जो पूर्णत: गतिशील क्षेत्र है। तथापि, भवन निर्माण एक व्यापार योग्य (ट्रेडेबल) क्षेत्र नहीं है जो अपने महत्व को रूपांतरणकारी (ट्रांसफार्मेशनल) क्षेत्र के रूप में भी सीमित करता है।

एक नीति निष्कर्ष जिसे अपनाया जाता है यह है कि मजदूरी बाहुल्य निर्माण के लिए सुधार के प्रयास कौशल में तेजी से उन्नयन के कार्य से करने होंगे क्योंकि कौशल गहन क्षेत्र भारत में गतिशील क्षेत्र होते हैं और अपनी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए यह अपेक्षित होता है कि कौशल के लिए बढ़ती मांग के साथ कुशल कार्मिकों की पूर्ति होती रहे; अन्यथा यह क्षेत्र भी गैर प्रतियोगी बन जाएगा।

दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के साथ-साथ स्किल इंडिया (दक्ष भारत) के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अब हम साधनों की बात करते हैं। कौन सी नीति (पॉलिसी) अपनाएं कि जो मेक इन इंडिया को साकार रूप प्रदान करने

सारणी 1.3: भारत सेवाएं बनाम विनिर्माण स्कोर बोर्ड

	विशेषता	पंजीकृत विनिर्माण	व्यापार, होटल और रेस्तरा	परिवहन भण्डारण और संचार	वित्तीय सेवाएं और बीमा	स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं आदि	निर्माण
1.	उच्च उत्पादकता	हां	नहीं	कुछ विशेष नहीं	हां	हां	नहीं
2क.	बिना शर्त घरेलू समाभिरूपता	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2ख.	बिना शर्त अंतरराष्ट्रीय समाभिरूपता	हां, लेकिन भारत के लिए	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
3.	समाभिरूप क्षेत्रों द्वारा संसाधनों का अवशोषण	नहीं	थोड़ा बहुत	थोड़ा बहुत	नहीं	थोड़ा बहुत	हां
4.	कौशल संबंधी रूपरेखा का आधारभूत क्षमता का मेल	कुछ विशेष नहीं	थोड़ा बहुत	थोड़ा बहुत	नहीं	नहीं	हां
5.	विक्रेय और/अथवा दोहराने योग्य	हां	नहीं	थोड़ा बहुत	हां	थोड़ा बहुत	नहीं

स्रोत : अमिराम और सुब्रह्मण्यम (2015)।

में हमारे सहायता कर सकें। उन्हें प्रभावकारिता के अवरोही क्रम में और विवाद के आरोही क्रम में 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

अविवादित प्रत्युत्तर में नियम बनाकर और करों को कम करके, बुनियादी संरचना तैयार करके श्रम विधि में सुधार करके व्यापारिक पर्यावरण में सुधार करना शामिल है और इन सबके एक साथ मिलने से व्यापार करने की लागत कम होगी, लाभ में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप घरेलू और विदेशी दोनों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिससे पूंजी निवेश में वृद्धि होगी। वास्तव में इन उपायों से न केवल मैन्यूफैक्चरिंग का, बल्कि सभी क्षेत्रों को लाभ होगा।

प्रत्युत्तरों के अगले सेट-जिन्हें सामान्य शब्दों में ''औद्योगिक नीति'' कहा जाता है का लक्ष्य, विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, छूट प्रदान करना, पूंजी की लागत को कम करना और कुछ अथवा सभी मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों में विशेषकर ''विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का निर्माण करना है।

प्रत्युत्तरों के अंतिम सेट-जिन्हें निश्चित रूप से ''संरक्षण वादी'' कहा जाना चाहिए का लक्ष्य मैन्यूफैक्चरिंग की कारोवारिता और परिणामस्वरूप शुल्कों द्वारा विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को कवच प्रदान करना और स्थानीय अपेक्षाएं और निर्यात संबंधी पहल की कार्रवाई शामिल है। गत अनुभवों को देखते हुए इन कार्यवाईयों की पभावकारिता वाद-विवाद के लिए खुली है। ये थोड़ा बहुत डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आने वाली भारत की बाह्य बाध्यताओं के विरुद्ध जा सकते हैं और इससे भारत की खुलेपन की साख को भी कम करके आंका जा सकता है।

बाद वाले दो बिन्दुओं पर अवांछित भरोसा करने से बचने में एक जोखिम है विशेषकर यदि इससे विस्तृत सूक्ष्म बाधा उत्पन्न होती है, जिसमें क्षेत्र विशेष में शुल्क कर परिवर्तन और प्रोत्साहनों के क्षेत्र में अनुदान शामिल हैं। इस संदर्भ में एक दखल जिसे तत्काल लागू किया जा सकता है, उसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और वह हर हाल में अच्छा है जिससे भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग द्वारा सामना किया जा रहा वर्तमान नकारात्मक संरक्षण समाप्त होगा।

1.11 व्यापारिक चुनौतियां

व्यापार को अनेक बाधाओं के साथ जूझना पड़ रहा है। व्यापारिक माहौल लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि वैश्विक प्रगति के संबंध में भारत के निर्यात में गिरावट आयी है तथा मेगा रीजनल ट्रेडिंग व्यवस्था संबंधी समझौते से भारत को बाहर कर दिए जाने का खतरा है।

विकास की त्वरित और स्थायी दरें निर्यात विकास की त्वरित दरों से संबंधित हैं। कुछ देशों, यदि कोई है ने अकेले अपने घरेलू बाजार की कम दर 7+ की विकास दर तक प्रगति की है। वास्तव में ओस्ट्री (2006)[26] के अनुसार स्थायी विकास मुख्यत: मैन्यूफैक्चरिंग निर्यातकों की अपनी विकास दर जो लगभग 36 प्रतिशत तक होती है पर जीडीपी अनुपात की तुलना में औसत विकास से संबंधित होने के कारण ही स्फुरित होती है। भारत को भी इससे अलग स्थिति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

यदि ऐसा है तो भारत क्या पूर्वानुमान करे? वर्ष 2002-03 और 2008-09 के बीच भारत के त्वरित विकास चरण के दौरान जीडीपी से संबंधित सेवाओं के निर्यात के अनुपात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई जो पहले लगभग 4.0 प्रतिशत प्रति थी, वह बढ़कर लगभग 9.0 प्रतिशत हो गयी। इसके विपरीत मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कम था (चित्र 1.23)। तथापि, वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात् लगता है कि भूमिकाएं परिवर्तित हो गयीं। मैन्यूफैक्चरिंग निर्यातकर्ता को यह लगता है कि वे सेवा निर्यातकों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। इससे भी अधिक दुखदायी बात यह है कि गत पांच वर्षों के दौरान दोनों ने ही गिरावट का सामना किया है जो एक अच्छा संकेत नहीं है।

ऐसा ही पैटर्न तब देखने को मिलता है जब हम विश्व के जीडीपी विकास के संबंध में (चित्र 1.24) भारतीय निर्यात वृद्धि की आधिक्यता (सेवाओं और वस्तुओं की) की गणना करते हैं। वर्ष 2000 के प्रारंभ में यह अधिकता विशेषकर सेवाओं के मामले में अधिक और बृद्धिमान थी। वर्ष 2001 में विश्व जीडीपी में हुई प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि भारत की निर्यात सेवाओं में हुई 3 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित थी जो बाद के कुछ वर्षों में 8% से भी अधिक तक बढ़ गई

[26] Johnson, Simon, Jonathan D. Ostry, and Arvind Subramanian, *"The Prospects for Sustained Growth in Africa; Benchmarking the Constraints,"* 2007, IMF Working Papers 07/52, International Monetary Fund.

बॉक्स 1.4 : मेक इन इंडिया का आधार संरक्षण नहीं बल्कि नकारात्मक संरक्षण को समाप्त करना है।

प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) सबंधी सभी छूटों को समाप्त करने से भारतीय विनिर्माताओं के द्वारा सामना किए जा रहे नकारात्मक संरक्षण समाप्त हो जाएगा और इससे मेक इन इंडिया की पहल में मदद मिलेगी और इससे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का भी उल्लंघन नहीं होगा।

एक प्रत्युत्तर जिससे मैन्यूफैक्चरिंग में सहायता मिलेगी और ''मेक इन इंडिया'' के प्रयास को बिना किसी कठिनाई के सहायता मिलेगी क्योंकि व्यावसायिक माहौल में वृद्धि होगी जबकि औद्योगिक नीति विवादास्पद और महंगी है अथवा संरक्षणवादी है। प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) में छूट को समाप्त करने से आयात पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) लगता है। इससे सहायता कैसे होगी?

कर सिद्धान्त के मामले में यह एक सुस्वीकृत मान्यता यह है कि घरेलू उत्पादन और आयात के बीच प्रोत्साहनों की न्यूट्रेलिटी को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित होता है कि सभी घरेलू अप्रत्यक्ष कर भी आयातों पर लगाए जाएं। इसलिए यदि कोई देश बिक्री कर मूल्यवर्धित कर (बैट), अथवा सीमाशुल्क अथवा जीएसटी घरेलू बिक्री/उत्पादन पर लगाता है तो यह आयातों पर भी लगना जरूरी है तथापि भारत की मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली कभी-कभी देश में उत्पादित वस्तुओं की तुलना में विदेशी उत्पादन के पक्ष में होती है।

प्रतिकारी शुल्क जिसे घरेलू उत्पादकों पर सीमा शुल्क को समायोजित करने के लिए लगाया जाता है वह आयात की संपूर्ण रेंज पर लागू नहीं होता है।

इन रियायतों को अंकीय बनाया जा सकता है। देश में उत्पादित गैर-तेल सामग्री पर सीमा शुल्क की प्रभावी दर लगभग 09 प्रतिशत है। सैद्धांतिक रूप से सीवीडी की प्रभावी संग्रहण दर भी समान होनी चाहिए लेकिन वास्तव में यह मात्र लगभग 06 प्रतिशत है। यह अंतर न केवल सरकार को 40 हजार करोड़ रुपए की राजकोषीय लागत को दर्शाता है बल्कि यह स्वदेश में उत्पादित सामग्री की तुलना में विदेशों में उत्पादित सामग्री के पक्ष में नकारात्मक संरक्षण को दर्शाता है।

यहां पर तीन महत्वपूर्ण भेदों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहला तो यह है कि विनिर्माताओं की इनपुट लागत को कम करके इनपुट पर सी.वी.डी. की छूट देकर उनकी सहायता की जा सकती है परन्तु मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत और भविष्य में जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो इन पुटों पर सीवीडी का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सदैव पुन: दावा किया जा सकेगा। इसलिए सीवीडी संबंधी रियायत कोई अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं करती।

दूसरे का संबंध उस स्थिति से है जब सीमा शुल्क और सीवीडी दोनों में छूट दे दी जाय। स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि इससे घरेलू उत्पादन और आयातों के बीच न्यूट्रल स्थिति हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है। जब आयातित वस्तुएं सीवीडी लगे बिना बाजार में आती है और चूंकि स्रोत देश में यह शून्यदर पर है इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का कोई इनपुट टैक्स का भार नहीं होता है। संगत घरेलू वस्तु पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता परन्तु चूंकि इसे छूट मिली हुई है इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए घरेलू सामान विदेशी सामानों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी होता है क्योंकि इस पर इनपुट टैक्स लगा होता है जोकि विदेशी वस्तु पर नहीं लगा होता।

तीसरे, सीवीडी से बहुत से आयातित सामान को मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि हमारे यहां उनका मुकाबला करने के लिए कोई घरेलू उत्पादन नहीं है। यह तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि यदि घरेलू उत्पादन प्रतिस्पर्धा नहीं करता है तो यह उन प्रोत्साहनों की न्यूट्रेलिटी प्राप्त नहीं करने का परिणाम होगा जो सीवीडी से सृजित होंगे। घरेलू उत्पादक हो सकता है यह सोचकर खेल के मैदान में न उतरे कि यह उनके स्तर का नहीं है।

इस प्रकार से भारतीय कर नीति एक प्रकार से घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बुरी तरह से दण्डित करती है। आखिर इस विसंगति का हल क्या है? इसका हल एकदम साधारण है इसके लिए सुनियोजित जीएसटी को लागू करना होगा जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी दर और सूक्ष्मता के साथ परिभाषित रियायतें शामिल होंगी। पहली बार में घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग पर लगे दण्ड को समाप्त किया जाएगा क्योंकि जीएसटी (केन्द्र और राज्य) स्वत: ही प्रोत्साहनों की न्यूट्रेलिटी को सुनिश्चित करने के लिए आयातों पर लागू हो जाएगा। ऐसा होने से भारत संरक्षणवादी हुए बिना और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अथवा मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) के अन्तर्गत की गई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बाध्यताओं में से किसी का उल्लंघन किए बिना घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकेगा।

इसके साथ-साथ ही सीवीडी पर लागू रियायतों को समाप्त करने से जीएसटी के प्रभाव को आंशिक रूप से प्रोत्साहित किया जा सकेगा। स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि शासन व्यवस्था रियायत मुक्त हो। यदि किसी क्षेत्र विशेष को सीवीडी से रियायत की जरूरत है तो उसे अपने मामले को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर उठाऐ जाने की जरूरत है।

एक तरह से देखा जाए तो भारत एक तरफ जहां स्वयं को नकारात्मक संरक्षण की स्थिति में पाता है वहीं दूसरी ओर शुल्कों की दरों को ऊंची भी करना चाहता है। शुल्क की दरों को ऊंचा करने का मुकाबला करने की यह बेहतर स्थिति है जिससे भारत की खुलेपन की साख में वृद्धि होगी और अनावश्यक तथा महंगे नकारात्मक संरक्षण भी समाप्त होगा।

और वित्तीय संकट से एकदम पूर्व यह लगभग 5 प्रतिशत पर स्थिर थी। इसके बाद इसमें निरंतर गिरावट आई और एकदम हाल ही के आकलनों से एक की अधिकता का पता चला है। विनिर्मित निर्यातों के यहीं पैटर्न विस्तृत रूप से समान है हालांकि यह बाजार के चढ़ने के दौरान सेवाओं की तुलना में इसमें कम अधिकता थी।[27]

[27] **वैश्विक विकास की तुलना में वैश्विक व्यापार की गिरती नम्यता को कौंसटेन्टीनेस्क्यू सी, ए मैट्टू और एम रूटा (2015) ''दी ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन: साइक्लिकल ऑर स्ट्रक्चरल? विश्व बैंक नीति अनुसंधान आधार पत्र डब्ल्यूपीएस 7158 में दस्तावेजबद्ध किया गया है।**

चित्र 1.23: विनिर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात (स.घ.उ. का प्रतिशत), 2000-01 से 2014-15 के दौरान

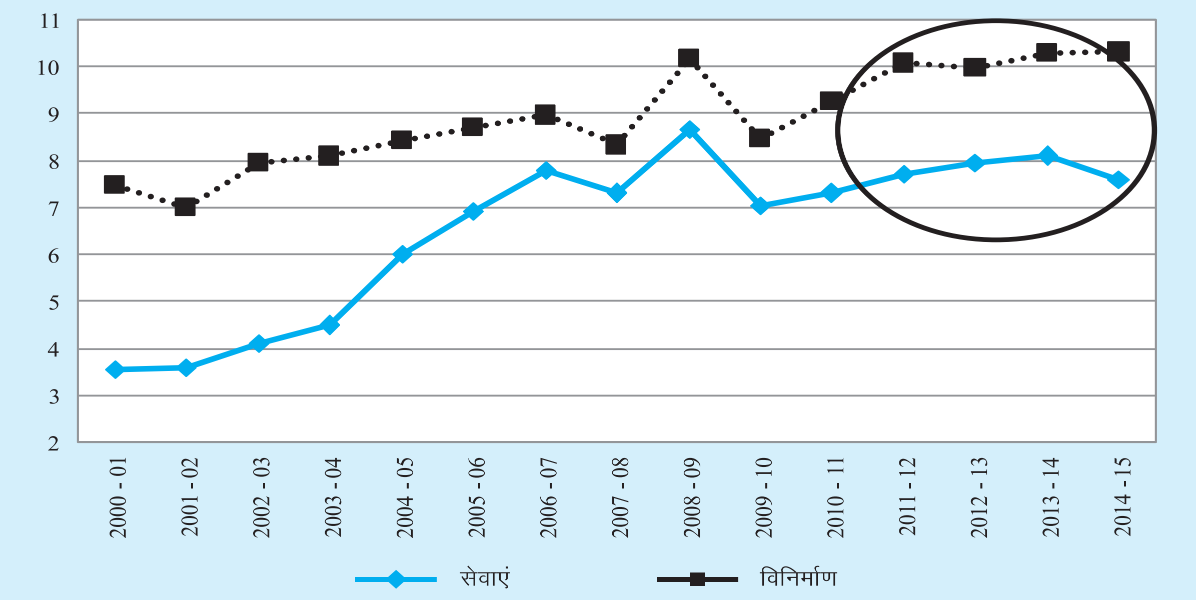

चित्र 1.24: 2000-01 से 2014-15 (2009-10 को छोड़कर) के दौरान विकास की प्रगती की तुलना में भारतीय निर्यात की आधिम्यता

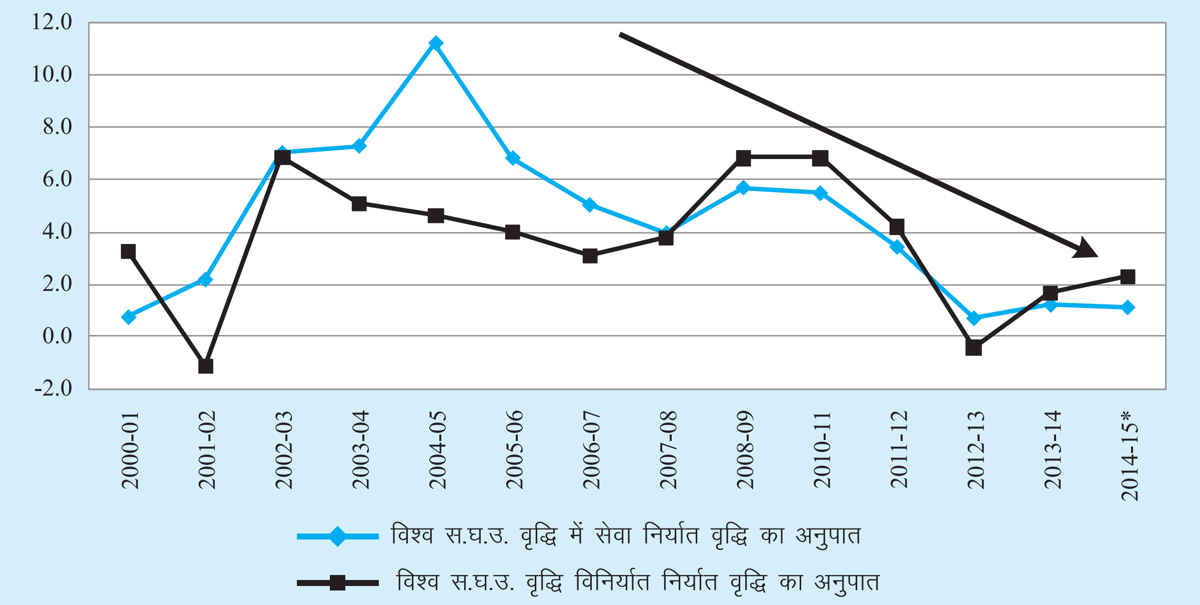

स्रोत : आईएमएफ, डब्ल्यूईओ, डीजीसीआई और एस तथा भारतीय रिजर्व बैंक।

टिप्पणी : निर्यात आधिक्य गणना तीन वर्ष के चल औसत पर आधारित है। इसमें वर्ष 2009-2010 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि निर्यात में आयी अत्यधिक गिरावट के कारण आधिक्य गणना को व्यक्त करना कठिन है।

दो चार्टों को मिलाकर देखने से भारत के लिए यह संदेश प्रतीत होता है कि बाह्य व्यापार परिवेश को दो तरफा लड़ाई झेलनी पड़ रही है। एक तो है वैश्विक विकास की दर में गिरावट का आना, जिससे भारतीय निर्यात में कमी आएगी और दूसरा है किसी वैश्विक विकास में व्यापार की गिरती दर के कारण और भी कम हो जाएगी।

इसलिए भारत को विशेष रूप से सेवा निर्यातों-विकास के प्रेरक घटकों-के बारे में जिसकी गति बहुत धीमी हो गई है,

के संबंध में अधिक चौकन्ना होना होगा। विकास दर को कम करने में सहयोग करने वाले घटकों के अलावा वे परस्पर विरोधी बातें हैं:- कमजोर बुनियादी ढांचा और मैन्यूफैक्चरिंग के मामले में चुनौतीपरक श्रमविधि और सेवाओं के मामले में कुशल श्रमिकों की बढ़ती मजदूरी और कमी।

व्यापार के लिए प्रतिकूल हो रहे बाह्य वातावरण के अलावा भारत को तेजी से परिवर्तित होते परिवेश से भी संघर्ष करना होगा। चूंकि नई सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में पुन: स्फूर्ति प्रदान करने की तैयारी कर रही हैं इसलिए उसे तीन उल्लेखनीय प्रकारों से पर्याप्त रूप से परिवर्तित होते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य का सामना करना होगा।

प्रथम, उत्पादन के अपूर्ण अनुवर्ती स्तरों पर आधारित वैश्विक मूल्यवर्धित श्रृंखलाओं के तथ्य और उन्हें न्यूनतम लागत लक्ष्यों पर तलाश करना गिरावट के बावजूद भी विशेषकर एशिया में व्यापार की विशेषता का वर्णन करना उनका गुण हो गया है। भारत धीरे-धीरे इन श्रृंखलाओं में समायोजित होता जा रहा है लेकिन अधिकांश अन्य गतिमान एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उसका स्तर काफी ऊंचा है।

दूसरा, मेगा क्षेत्रीय करारों पर गंभीरता के साथ वार्ताएं आरंभ की गई हैं। एशिया के भीतर और एशिया तथा अमेरिका के बीच व्यापार समेकन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा यदि और जब ट्रांसफैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पर वार्ता हो जाती है और अनुसमर्थन मिल जाता है। इसी प्रकार से उत्तरी अमरीका और यूरोप के बाजार एक साथ आएंगे यदि और जब ट्रांसएटलांटिक ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) पर निष्कर्ष आ जाता है तो इससे लगभग आधा विश्व व्यापार इन दो करारों के अन्तर्गत आ जाएगा।

तीसरा, चीन, जो अभी हाल ही तक यथास्थिति बनाए रखना चाहता था अब वह मूक दर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय भागीदारी करने हेतु परिवर्तन के लिए तैयार बैठा है। वह व्यापार नियमों के अगले दौर में शामिल होने और संभवत: उसके स्वरूप की रचना करने का इच्छुक है। यह परिवर्तन अर्थव्यवस्था को पुन: संतुलित करने के घरेलू आदेशों की प्रतिक्रिया है जिसके लिए चीनी अर्थव्यवस्था में भारी उदारीकरण की जरूरत पड़ेगी और टीपीपी तथा टीटीआईपी सहित अमेरिकी व्यापार प्रयासों द्वारा बाहर कर दिए जाने का डर भी शामिल है। चीन रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) जिसमें भारत भी शामिल हैं, दी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (एएसईएएन) देशों, साथ ही जापान, कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी केंद्र है।

व्यापार में आए इस वैश्विक परिवर्तन के प्रति भारत को किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। भारत के समक्ष दो विकल्प हैं एक तो है मापित एकीकरण (यथास्थिति और/अथवा (आरसीईपी) और दूसरा है महत्वकांक्षी एकीकरण (टीपीपी के द्वारा)। मापित एकीकरण में भारत की राजनैतिक बाधाओं और क्षमता द्वारा आदेशित घरेलू सुधार के मध्यम परन्तु स्थायी गति शामिल है जो केवल उस प्रकार के क्षेत्रीय करारों को जारी रख सकते है जिन्हें भारत ने एशियायी भागीदारों के साथ समझौता किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए तुलनात्मक रूप से कुछ वाध्यताएं उदारवादी रियायतें और अपवाद तथा एक उदार समय तालिका की जरूरत है।

यथास्थिति परिदृश्य में एक जोखिम भारत को विशाल एकीकृत बाजारों से न्यून व्यापारिक संभावनाओं के साथ बाहर कर देने का है और वैश्विक मूल्य श्रंख्लाओं की प्रकृति के कारण व्यापार में निवेश और बौद्धिक सम्पदा घुलमिल गई है उन्होंने भी निवेश संभावनाओं को कम किया है (आरसीईपी में शामिल होने से निश्चित रुप से सहायता मिलेगी लेकिन पूरी तरह से नहीं क्योंकि अपेक्षा यह है कि आरईसीईपी में समग्र मानदण्ड (टीपीपी) और (टीटीआईपी) के अंतर्गत की तुलना में कमजोर होंगे)। उच्चतर शुल्कों का सामना करने के लिए भारत के निर्यातकों से न केवल मानदण्ड विचलन प्राप्त होंगे बल्कि वे भिन्न और उच्चतर उत्पाद तथा स्थायी विकास मानकों से भी निरन्तर संघर्ष करना होगा। विश्व विकास और भारत के निर्यात आधिक्यता दोनों में मंदी के संदर्भ में कोई भी संभावित अपवर्जन से परेशानी और भी बढ़ेगी।

महत्वाकांक्षी एकीकरण का आशय निश्चित रुप से यह निकाला जाना चाहिए कि भारत टीपीपी में शामिल हो रहा है अथवा भविष्य में किसी दिन शामिल होने की मांग करने की कोशिश कर रहा है। इस विकल्प के चारों ओर अनिश्चितता के पर्याप्त वातावरण बना हुआ है क्योंकि समय और स्वयं टी.पी.पी. की शर्तें अभी तक अस्पष्ट हैं तथापि जो स्पष्ट है वह यह है कि किसी भी भावी टी.पी.पी. के अन्तर्गत पर्याप्त उदारीकरण बाध्यताएं उनसे कहीं अधिक होंगी जो भारत के मौजूदा एफ.टी.ए. के अंतर्गत हैं और संभवत: भारत के घरेलू सुधार नियोजित प्रयास से आगे है। भारतीय व्यापार क्षमता का उल्लेखनीय उन्नयन भारत के लिए जरूरी होगा ताकि वह इन मेगा क्षेत्रों में शामिल होने का चयन करने में सक्षम हो सके।

1.12 जलवायु परिवर्तन

भारत में पेट्रोलियम पदार्थों पर उल्लेखनीय उच्चतर कराधान लागू करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को

पुनऊर्जित करने सहित पर्यावरण संबंधी अनेक कार्रवाईयां की है। पर्यावरण परिवर्तन पर होने वाली पेरिस समझौते पर इससे सकारात्मक योगदान दिया जा सकता है।

इस वर्ष के अंत में पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पेरिस में बैठक करेंगे जिसमें दिसंबर 2015 तक यूनाइटेड नेशन्स फेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के अंतर्गत नए करारों संबंधी समझौतों को अंतिम रुप देंगे। पर्यावरण परिवर्तन पर सभी देशों द्वारा वर्ष 2020 के बाद से न केवल साझा बल्कि विभिन्न उत्तरदायित्वों के सिद्धांत के अनुपालन में एक कार्रवाई की अपेक्षा है।

दी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई.पी.सी.सी.) में वर्ष 2014 मे प्रकाशित अपनी हालिया रिपोर्ट दी फिफ्थ एसेसमेंट रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि औद्योगिक क्रांति के आगमन से ग्रीन हाउस गैसों (जी.एच.जी.) के मानवजनित उत्सर्जन में वृद्धि हाने का रुझान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मानवजनित कार्बनडाई ऑक्साइड का आधा उत्सर्जन तो गत 40 वर्षों के दौरान ही हुआ है। वर्ष 1983-2012 की अवधि के दौरान 30 वर्ष की यह अवधि पिछले 1400 वर्ष की अवधि में सबसे अधिक गर्म रही है। वर्ष 1970-2010 की अवधि के दौरान जीवाश्म ईंधन दहन और औद्योगिक प्रक्रिया से कुल ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जित हुई कार्बनडाई आक्साइड कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का बड़ा भाग रही है।

जलवायु प्रणाली में होने वाले परिवर्तन के कारण जीवनयापन के तौर-तरीको, खेतीबाड़ी और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लगता है कि भारी गर्मी लंबे समय तक पड़ा करेगी और वर्षा पैटर्न में परिवर्तनों के साथ ही यह घनीभूत होगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के देशों और भारत के भीतर अधिक ही होगा। गरीब लोगों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने में भारत उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। कुछ अन्य देशों से भिन्न भारत में पेट्रोलियम संबंधी राज्य सहायता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की है और इससे भी आगे बढ़ते हुए इन पेट्रोलियम उत्पादों पर पर्याप्त कर लगाने की कार्रवाई की है।

भारत इन कार्रवाइयों से कार्बन सब्सिडाइजेशन व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण कार्बन कराधान व्यवस्था तथा नकारात्मक मूल्य से अंतर्निहित सकारात्मक मूल्य की ओर बढ़ा है और यह परिवर्तन बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए अक्टूबर, 2014 से की गई हालिया कार्रवाईयों के प्रभावस्वरूप वस्तुतः पेट्रोल (ब्रांड रहित) के मामले में कार्बन डाईआक्साइड की प्रति टन मात्रा पर 60 अमेरीकी डालर के समकक्ष और डीजल (ब्रांड रहित) के मामले में प्रति टन लगभग 42 अमेरीकी डालर का वस्तुतः कार्बन कर लगाया गया है। वास्तव में अंतर्निहित कार्बन कर (पेट्रोल के लिए 140 अमेरीकी डालर तथा डीजल के लिए 64 डालर पर्याप्त रूप से उससे अधिक ही है जिसे आज कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन पर प्रति टन 25 अमेरीकी डालर (चित्र 1.25) के संबंध में उचित प्रारंभिक कर समझा गया है। पेट्रोलियम पदार्थों पर कर लगाने के मामले में भारत आज बहुत ऊंचे स्थान पर है। भारत द्वारा केवल हाल ही में उठाए गए कदमों से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रत्ययपत्रों में स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है।

चित्र 1.25: पेट्रोल तथा डीजल पर बढ़ते उत्पाद शुल्क से प्राप्त अप्रत्यक्ष कार्बन कर 2012 से जनवरी 2015 (यूएसएस/टीसीओ2)

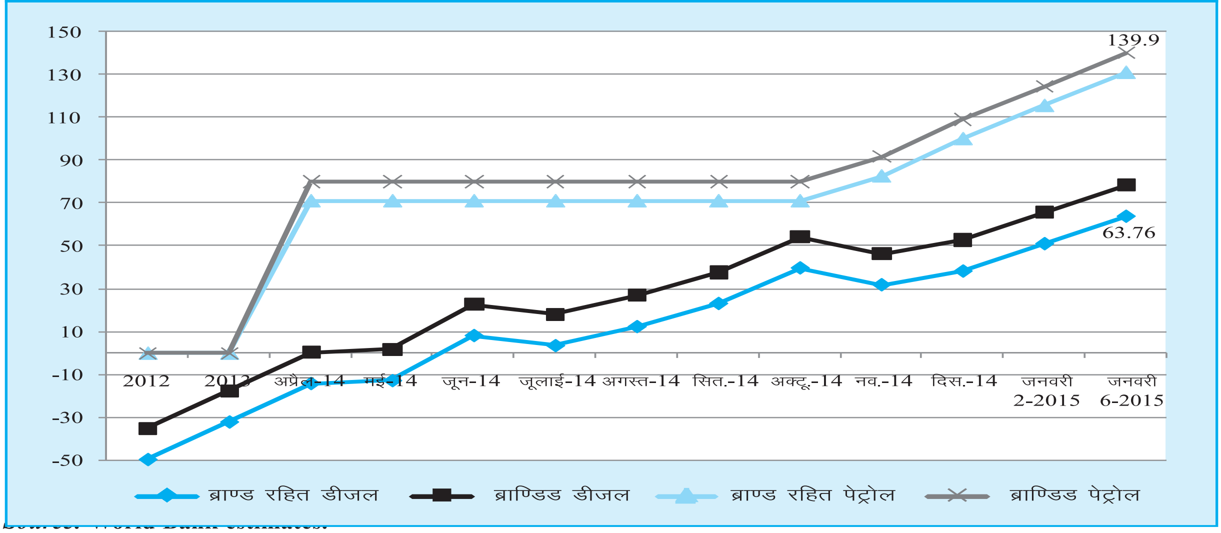

Source: World Bank estimates.

इसके साथ ही भारत में प्रति टन 50/- रुपए के कोयला उप-कर को बढ़ाकर 100/- रुपए प्रतिटन कर दिया है जो कि लगभग प्रतिटन एक अमेरीकी डालर के कार्बन कर के समतुल्य है। सांख्यिकीय जीवनमान के आधार पर भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की स्वास्थ्य परक लागत अनुमानत: प्रतिटन 3.41 अमेरीकी डालर से प्रतिटन 51.11 अमेरीकी डालर के बीच है। औसत संख्या 27.26 अमेरीकी डालर ही प्रति टन है। कोयला चालित विद्युत संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन की स्वास्थ्य लागत में पूर्ण होने वाली कार्डियोप्लमोनरी मृत्यु और अल्पावधिक प्रकटन के गंभीर प्रभावों तथा दीर्घावधिक प्रकटन के जीर्ण प्रभावों से उत्पन्न बीमारियों से संबंधित लागतें भी शामिल है। इन पूर्णत: घरेलू बाध्यताओं को समायोजित करने के लिए कोयले पर उच्चतर करों को विद्युत के मूल्यकरण के लिए अंतवृद्धियों के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए उसे समायोजित करना पड़ेगा और इसी कारण से 300 मिलियन घरों में अभी भी लोग बिना बिजली के रह रहे हैं।

इस समझौताकारी तालमेल (ट्रेड-ऑफ) से यह पता चलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा पहुंच के वैकल्पिक मार्गों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जनवरी, 2010 में प्रारंभ हुए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन पूरे देश में अपना विस्तार करने के लिए नीतिगत स्थितियों को निर्मित करके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को निर्मित करके सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक लीडर घोषित करता है। इस स्कीम के लिए बारहवीं योजना वित्तीय परिव्यय 8795 करोड़ रुपए का है। इस सौर मिशन की क्षमता 20,000 मेगावाट से एक लाख मेगावाट तक लगभग 5 गुन हो रहा है। अत: इसके लिए 100 बिलियन अमेरीकी डालर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य लगभग 300 मिलियन घरों को ऊर्जा प्रदान करना है। इसका संपार्श्विक लाभ यह होगा कि इससे कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 165 मिलियन टन की कमी आएगी।

भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों और ऊर्जा संबंधी प्रयासों को समायोजित करते हुए कोयले को जलाने की प्रक्रिया को और भी स्वच्छ और अधिक पर्यावरणानुकूल बनाने के लिए एक बड़ी प्रौद्योगिकीगत खोज की जरूरत होगी। यदि भारत पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसी के संगत विश्व को भी कोयला प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक संसाधन जुटाने होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि कोयला प्रौद्योगिकियों में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी और यदि इस अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाता है तो उन्नत देश निश्चित रुप से उच्च और बढ़ती हुई कार्बन मूल्यन पर तत्काल ध्यान देंगे। एक नए प्रकार के वैश्विक सौदे की विस्तृत रूप रेखा और उन्नत तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था से अपेक्षित योगदान आदित्य मट्टू और अरविंद सुब्रमण्यम के ग्रीन प्रिन्ट में देखा जा सकता है। *जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिए एक नया दृष्टिकोण।*

1.13 महिलाओं का सशक्तीकरण: नारीशक्ति को बेड़ियों से मुक्त करना

महिलाओं की स्थिति और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में सुधार लाना प्रमुख विकास की चुनौती है। थोड़े समय के लिए परिवार नियोजन लक्ष्यों और प्रोत्साहनों के प्रावधान, महिला नलबंदी पर अनपेक्षित ध्यान केंद्रित करते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान की शुरूआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय समाज द्वारा लड़कियों को कमतर आंकने की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना है। लेकिन भारतीय समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव करने की परस्परविरोधी सोच विद्यमान है। एक तरफ तो भारत में महिला राष्ट्रपति और महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानीमानी महिलाएं हुई हैं तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बड़े राजनीतिक दलों की प्रमुख की महिलाएं हैं। इसके अलावा कई महिलाएं कैबिनेट रैंक के मंत्रीपद तक पहुंची है तथा कई महिलाएं उद्योग प्रमुख (विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में) हुई हैं और इसके बावजूद यूएनडीपी की अद्यतन मानव विकास रिपोर्ट (2014 के अनुसार) मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई) में 187 देशों में भारत 135वें स्थान पर है और लिंग असमानता सूचकांक (जी.आई.आई.) में भारत का स्थान 152 देशों में 127वां है। जीआईआई स्त्री और पुरुष के बीच उपलब्धियों में असमानता दर्शाने वाले समग्र उपायों को तीन प्रकार:प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकारिता और श्रम बाजार के आधार पर देखता है इसके अनुसार भारत एच.डी.आई. पर सभी देशों से 25 प्रतिशत नीचे है और जी.आई.आई. में तो यह प्रतिशत और भी गिरकर 20 प्रतिशत ही रह जाता है इसके अलावा भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्मदर सापेक्षतया पूरी दुनिया में कम है और वर्ष 2001 में जहां यह गिरावट एक हजार लड़कों की तुलना में 927 लड़किया थी वहीं 2011 में एक हजार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 918 ही रह गई। (चित्र 1.26) चीन उन कुछ देशों में ऐसा देश है जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों की जन्मदर और भी कम है।

चित्र 1.26: प्रति 100 लड़कियों पर लड़के, 1990-2010

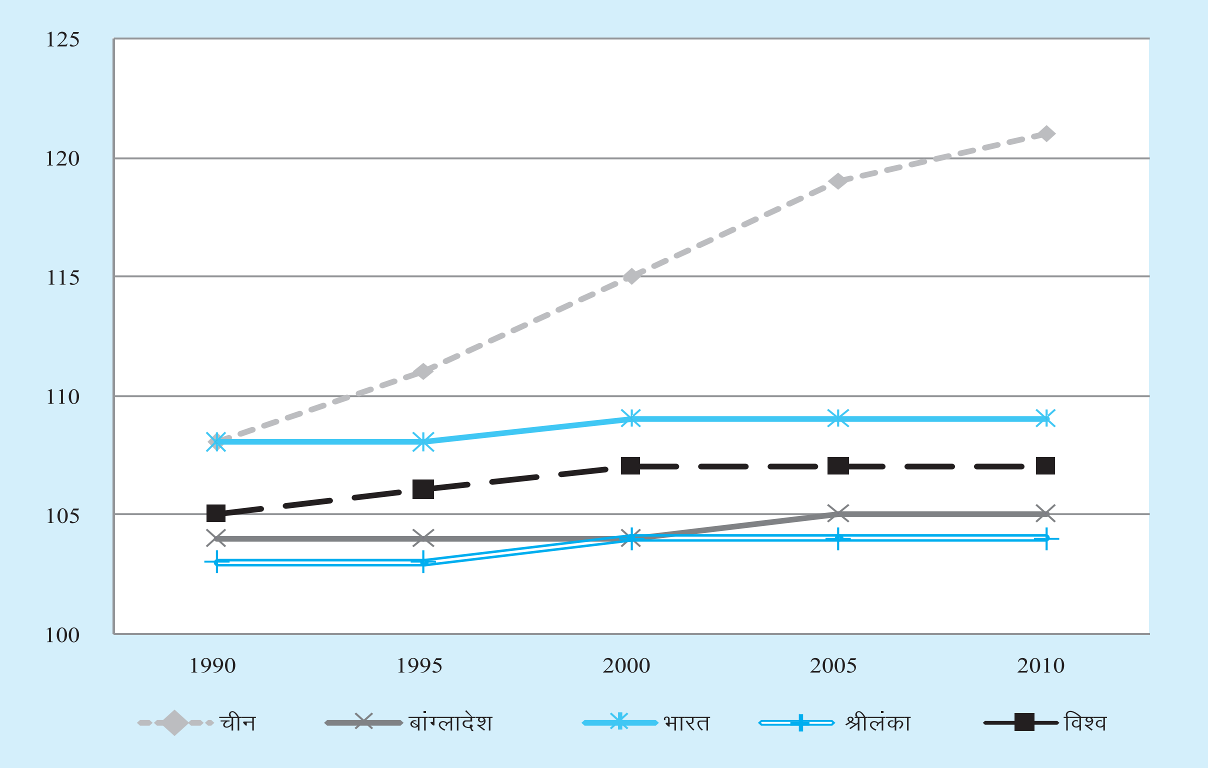

स्रोत : **स्टैटिस्टिकल इयरबुक फॉर एशिया एण्ड दी पेसिफिक 2011।**

लेकिन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में नवंबर 2014 में हुई त्रासदी जिसमें 13 युवा महिलाओं की मौत हो गई थी जिनके बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे थे और 45 गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। एक ऐसी विशिष्ट और गंभीर समस्या महिला नसबंदी की ओर इशारा करती है जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीसरे दौर की रिपोर्ट (एनएफएचएस-3, 2005-06) में बताया गया है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में महिला नसबंदी 90 प्रतिशत है और सभी गर्भ निरोधकों की प्रतिशतता 76 है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र दोनो राज्यों में महिला नसबंदी की औसत आयु 24.9 वर्ष सूचित की गई है।

ऐसा लगता है कि बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने पर विशेषकर महिलाओं पर केन्द्रित नए ढंग से ध्यान केन्द्रित किया गया है और जिस साधन को अपनाया गया है उसे अपनाने में अनुरोध और जबरदस्ती के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अनुरोध नसबंदी और नसबंदी के लिए न केवल गरीब दम्पत्तियों को प्रोत्साहन के रूप में किया जाता है वल्कि स्थानीय निकायों के कार्य निपादन के लिए उन्हें पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसे संवध 'नपरक और प्रेरणदायी नारे के रूप में वर्णित किया गया है। परिणामस्वरूप महिला नसबंदी के लिए बड़े-बड़े कैंप लगाए जाते है। भारत की जनसंख्या नीति परिवार नियोजन उपायों विशेषकर महिलाओं संबंधी गर्भ निरोधकों, उन्हें प्रजनन का मामूली विकल्प अथवा स्वायत्तता के साथ विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया प्रतीत होता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए कुल नसबंदी आपरेशनों, दूरबीन नसबंदी/नलबंदी की संख्या 97.4 प्रतिशत रही जबकि पुरूष नसबंदी आपरेशनों, कम जटिल जोखिम के बावजूद, की संख्या केवल 2.5 प्रतिशत रही (1.27) 1 महिला नसबंदी के प्रति सरकारी व्यय की स्थिति भी सही नहीं है वर्ष 2013-14 के दौरान परिवार नियोजन के लिए निर्धारित 397 करोड़ रुपए की बजट राशि में से 85 प्रतिशत (338 करोड) राशि महिला नसबंदी पर ही खर्च कर दी गई। तुलना करें तो पाएंगे कि कुल बजट का 1.5 प्रतिशत स्पेसिंम तरीकों पर खर्च किया गया और 13 प्रतिशत बुनियादी ढांचे और संचार पर खर्च किया गया।

अधिकांशतया जन्मदर नियंत्रण पर ध्यान देने वाली जनसंख्या नियंत्रण नीति को बढ़वा देने में आने वाली नकारात्मक बातों से शिशुलिंग अनुपात में गिरावट आयी है। यदि प्रत्येक परिवार में कम बच्चे हो तो मन मे यह भावना अधिक बलवर्ती रहती है कि परिवार में कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए।

चित्र 1.27: पुरुष नसबन्दी तथा स्त्री नसबन्दी संख्या 1980-81 से 2012-13 (हजार में)

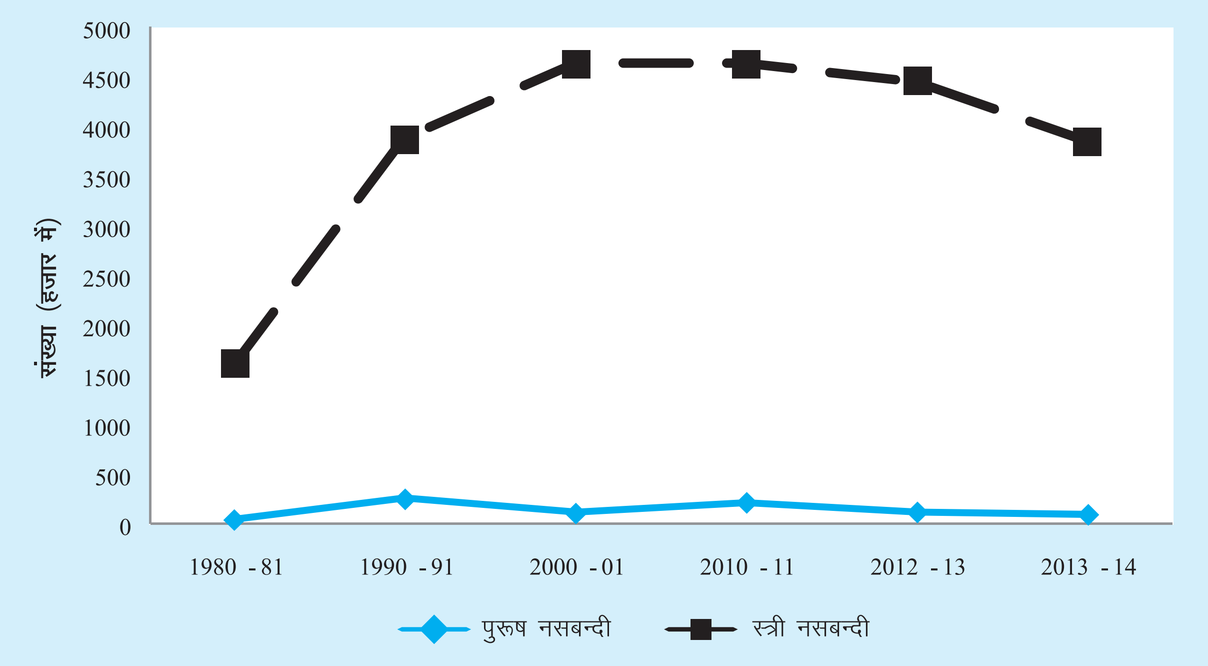

स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

ऐसी स्थिति में सरकार के सामने क्या करे और कैसे करें की स्थिति आ जाती है। उदाहरण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए बिना (ईएलए अथवा उपलब्धि के अपेक्षित स्तर), महिला नलबंदी और नसबंदी अभियान शिविरों संबंधी प्रोत्साहनों को वापस लेना। इसके अलावा सरकार निम्नलिखित कार्य कर सकती है:-

(i) भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा करना ताकि यह महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और भारत की जनसंख्या संबंधी जरूरतों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके।

(ii) गुणवत्तापूर्ण सेवाओं, स्टैटिक परिवार नियोजन क्लिनिकों और गुणवत्तापूर्ण मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए बजट बढ़ाना।

(iii) युवाओं की जरूरतों को पूरा करना, यौन स्वास्थ्य के लिए अधिक परामर्शदाताओं को लेना, ऐसी सेवाएं प्रदान करना जो युवाओं के लिए अधिक अनुकूल हो और स्पेसिंग मैथड की पर्याप्त आपूर्ति करना।

1.14 सहयोगात्मक संघवाद और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

14वें वित्त आयोग ने एक ओर तो केन्द्र और राज्यों के बीच और दूसरी ओर राज्यों के ही अंदर राजस्व के बटवारे के लिए दूरगामी परिवर्तनों की सिफारिश की है। इसके सफल कार्यान्वयन से सहयोगात्मक संघवाद को बढावा मिलेगा जिसे लेकर सरकार बहुत उत्साहित है।

14वें वित्त आयोग ने हाल ही में 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए केन्द्र से राज्यों को और राज्यों के बीच करों के अंतरण और अन्य अंतरणों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इनसे केन्द्र राज्य संबंधों, बजट निर्धारण पर और केन्द्र राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बड़े प्रभाव पड़ने की संभावना है। कुछ सिफारिशें इस प्रकार है:-

14वें वित्त आयोग ने करों केन्द्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा वर्तमान 32 प्रतिशत से बढ़ाकर मूलत: 42 प्रतिशत कर दिया है, जो ऊर्ध्वाधर अंतरण में अब तक का सबसे अधिक है। पिछले दो वित्त आयोगों अर्थात् 12वें (अवधि 2005-2010) और 13वें (अवधि 2010-2015) ने केन्द्रीय विभाज्य पूल में राज्य हिस्सा क्रमश: 30.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत की वृद्धि) और 32 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत की वृद्धि) की सिफारिश की थी।

14वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच विभाज्य पूल में राज्य हिस्से के वितरण के लिए नए क्षैतिज सूत्र (सारणी 10.1) का भी सुझाव दिया है। सम्मिलित/असम्मिलत परिवर्तनीय कारकों तथा उन्हें सौंपे जाने वाले भारांशों, दोनों में बदलाव हैं। 13वें वित्त आयेग की अपेक्षा, 14वें वित्त आयोग ने दो नए परिवर्तनीय कारक जोड़े हैं - 2011 की जनसंख्या और वन

क्षेत्र; और राजकोषीय अनुपालन कारक को निकाल दिया है। (ब्यौरे के लिए अध्याय 10 देखें)।

इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने से देश अधिक राजकोषीय संघवाद की दिशा में आगे बढ़ेगा जिससे राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता मिलेगी। उदाहरणत: 2015-16 के लिए अनुमानित स.घ.उ. वृद्धि और कर उछाल के पूर्व अनुमानों के आधार पर यह उम्मीद है कि 2014-15 के संबंध में राज्यों के लिए अतिरिक्त राजस्व दो लाख करोड़ रुपए तक होंगे। इसमें से काफी बड़ा हिस्सा उस अंतर का द्योतक है जो विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से में हुए परिवर्तन से उपजा है।

सारणी 1.4 में दिए गए प्रारंभिक अनुमान दर्शाते हैं कि सम्पूर्ण तौर पर सभी राज्य एफएफसी अंतरणों से लाभान्वित होंगे। लेकिन वितरण संबंधी प्रभावों का आकलन करने के लिए, इन वृद्धियों को जनसंख्या, चालू बाजार मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद अथवा राज्य की अपनी कर राजस्व प्राप्तियों से मापा जाना चाहिए। इसे सारणी 1.4 के कालम 4.6 में दिखाया गया है। इन संकेतकों के अनुसार मापे जाने पर सबसे बड़े लाभ प्राप्त कर्ता और मात्रा की दृष्टि से विशेष श्रेणी के राज्य हैं (एससीएम) अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं।

प्रति व्यक्ति संदर्भ में सबसे बड़े लाभ प्राप्त कर्ता एससीएस राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम हैं तथा

सारणी 1.4 : अतिरिक्त एफ.एफ.सी. अंतरण (2014-15 की तुलना में 2015-16 में)

राज्य	श्रेणी	एफ.एफ.सी. से लाभ (करोड़ रुपये)	प्रतिव्यक्ति के रूप में लाभ (रुपए में)	ओटी आर के रूप में लाभ	एन एस डी पी के प्रतिशत के रूप में लाभ
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश (एकीकृत)	जीसीएस	14620	1728	27.4	2.2
अरुणाचल प्रदेश	एससीएस	5585	40359	1758.1	51.0
असम	एससीएस	7295	2338	95.5	5.8
बिहार	जीसीएस	13279	1276	105.3	4.9
छत्तीसगढ़	जीसीएस	7227	2829	67.5	5.2
गोवा	जीसीएस	1107	7591	44.1	3.0
गुजरात	जीसीएस	4551	753	10.3	0.8
हरियाणा	जीसीएस	1592	628	7.8	0.5
हिमाचल प्रदेश	एससीएस	8533	12430	207.7	14.6
जम्मू एंड कश्मीर	एससीएस	13970	11140	294.4	22.4
झारखण्ड	जीसीएस	6196	1878	89.1	4.8
कर्नाटक	जीसीएस	8401	1375	18.1	1.8
केरल	जीसीएस	9508	2846	37.0	3.1
मध्य प्रदेश	जीसीएस	15072	2075	55.9	4.5
महाराष्ट्र	जीसीएस	10682	951	12.2	0.9
मणिपुर	एससीएस	2130	8286	578.7	19.5
मेघालय	एससीएस	1381	4655	198.0	8.6
मिजोरम	एससीएस	2519	22962	1410.1	33.3
नागालैंड	एससीएस	2694	13616	886.5	18.7
ओडिशा	जीसीएस	6752	1609	50.2	3.2
पंजाब	जीसीएस	3457	1246	18.3	1.4
राजस्थान	जीसीएस	6479	945	25.5	1.6
सिक्किम	एससीएस	1010	16543	343.7	10.7
तमिलनाडु	जीसीएस	5973	828	10.0	0.9
त्रिपुरा	एससीएस	1560	4247	181.8	6.9
उत्तर प्रदेश	जीसीएस	24608	1232	46.8	3.5
उत्तराखंड	एससीएस	1303	1292	23.2	1.4
पश्चिम बंगाल	जीसीएस	16714	1831	67.0	3.0
कुल		204198	1715		

स्रोत : वित्त मंत्रालय।

जीसीएस-सामान्य श्रेणी के राज्य; एससीएस-विशेष श्रेणी के राज्य

अन्य राज्यों (जीसीएम अथवा सामान्य श्रेणी के राज्य) में केरल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं।

जाहिर है केन्द्र के लिए राज्यों को दिए जाने वाले करों में वृद्धि तभी रुपायित की जा सकती है यदि राज्यों में दी जाने वाली केन्द्रीय (आयोजना) सहायता में कटौती की जाए। दूसरे शब्दों में अन्य राज्यों के पास राजस्व और व्यय दोनों मोर्चों पर अधिक स्वायत्तता होगी।

यह अनुमान लगाना भी संभव है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें राज्यों की निवल व्यय क्षमता के साथ क्या करेगी जहां निवल का अर्थ है एफएएसी के निवल अंतरणों और घटायी गई केन्द्रीय सहायता के बीच अंतर जिसके लिए एफएफसी की सिफारिशों की आवश्यकता होगी। मुख्यत: विशेष श्रेणी के राज्य सबसे बड़े लाभ प्राप्तकर्ता होंगे। इसके अतिरिक्त जीवीएम में ऐसे 9 राज्य हैं जिनके द्वारा अपने कर राजस्वों के 25 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने की संभावना है। (ब्यौरा अध्याय 10 पर देंखे)

सीएसए से हट कर FFC अंतरणों को अपनाने का एक संपार्श्विक लाभ यह होगा कि इससे समग्र प्रगति में तेजी आयेगी अर्थात् अपेक्षाकृत कम प्रतिव्यक्ति एनएसडीपी वाले राज्य अधिक प्रतिव्यक्ति एनएसडीपी के मुकाबले अधिक राशि प्राप्त करेंगे।

यह इस तथ्य से जाहिर होता है सीएएस अंतरण जो पहले विवेकाधीन थे, वित्त आयोग के अंतरणों के मुकाबले कम प्रगतिशील थे।

निश्चित रूप से, सीएएस अंतरणों में कटौती से कुछ संक्रमण लागतें भी होंगी। लेकिन अव्यवस्था की गुंजाइश कम कर दी गई है क्योंकि अतिरिक्त एफएफसी संसाधन सिर्फ उन्हीं राज्यों को दिए जाएंगे जिनकी सबसे बड़ी सीएएस वित्तपोषित स्कीमें हैं।

कुल मिलाकर, एफएफसी की दूरगामी प्रभाव वाली सिफारिशों के साथ-साथ नीति आयोग के सृजन से सरकार का सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। शहरों और अन्य स्थानीय निकायों को सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धी संघवाद की परिधि में शामिल करने का आवश्यक, बल्कि सच कहें तो, अहम कार्य अब अगली नीतिगत चुनौती है।